चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 02 मई–08 मई 2016 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

चुनौतियां ही चुनौतियां

संतोष भारतीय

बहुत पुराना शेर है और आपको जरूर याद होगा... *ये इश्क नहीं आसां, बस इतना ही समझ लीजे, इक आग का दरिया है और डूब के जाना है.* सारे देश में और जो राजनीति में हैं, उनमें यह सिर्फ नीतीश कुमार के ऊपर, जिस लम्हा हम और आप बात कर रहे हैं, लागू होता है. नीतीश कुमार के कई सपने हैं. एक सपना देश के लोगों को जय प्रकाश नारायण की तरह व्यवस्था बदलने के लिए तैयार करना, बिहार को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना और तीसरा समाज में फैले हुए उन मूल्यों का विरोध करना, जिनका आमतौर पर विरोध करने का साहस लोग स्वयं नहीं कर पाते.

इन सारे सपनों को पूरा करने का मतलब है राजनीति में कुछ नए तत्वों का प्रवेश करवाना. खासकर एक ऐसा उदाहरण पेश करना, जो जय प्रकाश जी के बाद समाप्त हो गया था. गांधीजी स्वयं, जवाहर लाल जी भी उसके एक हिस्से थे, और जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने समाजसेवा व राजनीति में दखल रखते हुए लगातार सामाजिक काम किए, जिसे रचनात्मक काम कहते हैं. जयप्रकाश जी के बाद नानाजी देशमुख ने रचनात्मक कामों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और राजनीति से संन्यास लेने के बाद समाज के बीच काम करते हुए जितना रचनात्मक काम वह कर सकते थे, उन्होंने किए. आज नीतीश कुमार आकंठ राजनीति में डूबे हुए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सत्ता के अंतरविरोध उनके दाएं–बाएं घूम रहे हैं और इन अंतरविरोधों के बीच उन्होंने रचनात्मक काम की धारा को बढ़ाने का गुरुत्तर दायित्व अपने कंधों पर लिया है. बिहार में संपूर्ण शराबबंदी का फैसला एक बहुत मुश्किल फैसला था. पूरा तंत्र शराब से पैसे कमा रहा है और जब मैं तंत्र कहता हूं, तो उसका मतलब अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री और छोटे–मोटे नेता, उसमें सब शामिल हैं. यह फैसला जब नीतीश कुमार ने लिया होगा, मैं समझ सकता हूं चार हजार करोड़ के राजस्व का सीधा नुकसान और चार हजार करोड़ के राजस्व का वह नुकसान जो इसे कमाने के रास्ते में अधिकारियों की जेब में चला जाता है. हर शराब की दुकान पर टैक्स की चोरी होती है और वह चोरी उतनी ही होती है जितना टैक्स शराब की बिक्री से सरकार के खजाने में आता है.

नीतीश कुमार लगभग 11 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और अब उन्होंने जद (यू) का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही संघ मुक्त भारत का नारा दिया है. उन्होंने अपील की है कि गैर भाजपा दल आपस में मिल जाएं या मिलकर कोई मोर्चा बनाएं. क्योंकि उन्हें लगता है कि मौजूदा शासन जिसके प्रतीक नरेंद्र मोदी हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की नीतियों को इस देश में प्राण–पण से लागू करने में जुटे हुए हैं. नीतीश कुमार का ये नारा नीतीश कुमार के लिए राजनीति की संभावनाएं तो खोलता है, लेकिन राजनीतिक परेशानियां भी पैदा करता है.

नीतीश कुमार के लिए पहली राजनीतिक परेशानी उनके राजनीतिक साथियों द्वारा खड़ी की जाएगी, बल्कि कुछ ने खड़ी करनी शुरू भी कर दी है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे. पर, हम सबसे पहले बात करते हैं इस देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की और हम जैसे ही अल्पसंख्यक कहते हैं, हमारे सामने मुस्लिम समाज आ जाता है, मुस्लिम समाज का मनोविज्ञान है कि वह उससे दूर भागता है जो पहले भाजपा या जनसंघ के साथ रह चुका है. नीतीश का 11 साल का भाजपा का साथ मुसलमानों के मन में नीतीश कुमार को लेकर कोई संदेह नहीं पैदा कर सका. यह कमाल नीतीश कुमार बिहार में कर चुके हैं. जब वो लालू यादव के खिलाफ बिहार में भाजपा के साथ अगुआ का रोल निभा रहे थे, तब पहली बार मुसलमानों के एक बड़े हिस्से ने लालू यादव के खिलाफ जाकर नीतीश कुमार को वोट दिया था और वो वोट नीतीश कुमार को भाजपा का अभिन्न अंग के रूप में देखे जाने के बाद भी मुसलमानों ने दिया था. इसका मतलब मुसलमानों ने नीतीश कुमार को सांप्रदायिक नहीं माना. और जब इस बार का विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी ने अपने दुश्मन नंबर एक के रूप में बिहार के लोगों से कहा कि नीतीश कुमार को वोट न दें, तो लोगों ने नरेंद्र मोदी की अपील को मानने से इंकार कर दिया. नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि या तो आप मुझे चुनें, अगर मेरी नीतियों में आपको भरोसा है, क्योंकि लोकसभा के लिए आप मुझे चुन चुके हैं या फिर नीतीश कुमार को चुनें. मेरी पार्टी अगर जीतती है तो बिहार का विकास होगा और नीतीश कुमार जीतते हैं तो बिहार में जंगल राज होगा. बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को चुना, नरेंद्र मोदी की पार्टी को नहीं चुना और मुसलमानों ने अपना संपूर्ण समर्थन नीतीश कुमार को दिया. अब जब नीतीश कुमार जद (यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब उनके इस संघ मुक्त भारत के नारे का अंदर की राजनीतिक धारा में मुसलमानों ने सबसे ज्यादा स्वागत किया है. इसलिए, नीतीश कुमार के पक्ष में राजनीति का पहला चरण गया है, जिसमें मुसलमान नीतीश कुमार के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का नीतीश के पक्ष में जाना समाजवादी पार्टी जिसके अगुआ मुलायम सिंह यादव हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए कितना स्वागत योग्य होगा और इनका विरोध कहां से शुरू होगा, इस नारे ने नीतीश कुमार के सामने चुनौती के रूप में पेश कर दिया है.

बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने जी–जान लगाकर मुलायम सिंह के यहां कई बैठकें कर, अधिकांश गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा दलों के लोगों को बैठा कर, जिसे जनता परिवार के रूप में कहा जाता है, सार्वजनिक रूप से मुलायम सिंह को अपना नेता मानने की और उन्हें नई बनने वाली एक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में घोषणा कर दी थी. मुलायम सिंह की घोषणा वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे नेता शामिल थे, जिसकी मुख्य कमान नीतीश कुमार और लालू यादव ने संभाली थी और सार्वजनिक रूप से सबने मालाएं पहनाकर मुलायम सिंह को अपना नेता घोषित कर दिया था. मुलायम सिंह खुश भी थे, लेकिन जैसे ही बिहार चुनाव की घोषणा हुई मुलायम सिंह अघोषित कारणों से रूठ गए. मुलायम सिंह ने बिहार चुनाव से पहले एक पार्टी बनाने के प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, जबकि यह तय हुआ था कि बिहार चुनाव से पहले एक पार्टी बन जाएगी. मुलायम सिंह ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद हम पार्टी की बात करेंगे. पहला झटका देने के बाद मुलायम सिंह बिहार में चुनाव लड़ने की रणनीति बनाने लगे. लोग उसके पीछे उनके भाई राम गोपाल यादव का हाथ देखने लगे, क्योंकि इस संपूर्ण प्रक्रिया में सिर्फ राम गोपाल यादव, जिनके ऊपर मुलायम सिंह दिल्ली की राजनीति में सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, इस सारी प्रक्रिया के शुरू से खिलाफ थे और उनका मानना था कि अगर एक पार्टी बन जाती है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि ये जितने भी सहयोगी दल हैं, उत्तर प्रदेश में हमसे सीटें मांगेंगे. दूसरी तरफ नीतीश कुमार और लालू यादव, मुलायम सिंह को अध्यक्ष बनाने की सार्वजनकि घोषणा के बाद ये मान रहे थे कि जल्दी से जल्दी एक पार्टी बन जाएगी, जिसका नाम मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी होगा. उसका झंडा समाजवादी पार्टी का होगा, उसका निशान (चुनाव चिन्ह) समाजवादी पार्टी का होगा. एक तरह से सारे लोग समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे और उनका मानना था कि मुलायम सिंह अपनी कलम से बिहार चुनाव में सभी 200 उम्मीदवारों की टिकटें बांटेंगे, पर मुलायम सिंह के फैसले से सब धराशाई हो गया. चुनाव के दिनों को देखते हुए आपस में समझौता हुआ और सारी सीटें आरजेडी और जेडीयू के खाते में रहीं, जिसमें से 40 सीटें गठबंधन में शामिल तीसरी पार्टी कांग्रेस के लिए छोड़ दीं.

मुलायम सिंह ने बिहार में न केवल उम्मीदवार उतारे, बल्कि बिहार चुनाव में उन्होंने लालू–नीतीश गठबंधन का खुलकर विरोध भी किया और यहां तक कह दिया कि लालू यादव को भटका दिया गया है. नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ रहेंगे और उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है. ये बात न नीतीश कुमार को समझ में आई, न लालू यादव को समझ में आई, क्योंकि बिहार चुनाव की घोषणा होने से पहले तक लालू यादव ने व्यक्तिगत रूप से जाकर मुलायम सिंह से यह अनुरोध किया था कि अगर वो साथ नहीं देते, तो विरोध भी न करें, क्योंकि जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी का विरोध करना और बिहार में चुनाव जीतना इनका लक्ष्य था, वहीं लालू यादव अपनी बढ़ती उम्र के साथ अपने दोनों बेटों को राजनीति में स्थापित करना चाहते थे. मुलायम सिंह ने लालू यादव की बात नहीं सुनी.

अब जब नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन बिहार में सत्ता में है, तो लालू यादव की पहली घोषणा सामने आई है कि प्रधानमंत्री पद के लिए अगर नीतीश कुमार उम्मीदवार हैं, तो मैं उनका समर्थन करूंगा. नीतीश कुमार के सामने पहली चुनौती मुलायम सिंह के रूप में खड़ी है. मुलायम सिंह देश के अकेले नेता होते जिन्हें संपूर्ण विपक्ष प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करना चाहता था. अगर उन्होंने एक पार्टी बना ली होती, अगर उन्होंने किन्ही अंजान कारणों की वजह से बिहार में नीतीश कुमार का और लालू यादव का विरोध न किया होता, तो अपनी–अपनी शंकाओं के बावजूद श्री एच डी देवगौड़ा, श्री ओम प्रकाश चौटाला, श्री कमल मोरारका, श्री लालू यादव और श्री नीतीश कुमार इस विचार के थे कि मुलायम सिंह के नेतृत्व में अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और इन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे. लेकिन इतिहास के अंतरविरोध और संभवत: प्रोफेसर रामगोपाल यादव की सलाह पर मुलायम सिंह ने इस सारे प्रयास को ध्वस्त कर दिया. उन्होंने बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में सामान्य शिष्टाचार के तहत अपने पुत्र अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर भी पटना जाने से रोक दिया. अब तक बिहार चुनाव की घोषणा तक जो दो तीन बैठकें हुई थीं उनमें शिवपाल यादव मुलायम सिंह जी के प्रतिनिध के रूप शामिल हुए थे, लेकिन इस बार उन दोनों को जाने से रोक दिया.

मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में दोबारा सामजवादी सरकार चाहते हैं, मायावती वहां खामोश बैठी हैं, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह सक्रिय है. मुलायम सिंह के सारे कदम उत्तर प्रदेश में लोगों को डरा रहे हैं. उन्हें लग रहा है कि मुलायम सिंह के फैसलों की वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिल सकती है. दूसरी तरफ मुलायम सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ अभियान छेड़ते हुए अभी तक नहीं दिखाई दे रहे हैं. यहीं पर नीतीश कुमार और मुलायम सिंह का पहला आमना सामना होने वाला है. नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी घोषित की

(शेष पृष्ठ 2 पर)

क्या नीतीश कुमार उड़ीसा में नवीन पटनायक, बंगाल में ममता बनर्जी, दक्षिण में के. चंद्रशेखर राव से कोई संवाद बना पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार भी ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो किसी भी राजनीतिक फैसले में पहले अपना स्वार्थ देखते हैं. उन्हें देश में वैचारिक लड़ाई की जगह अपना स्थान पहले नजर आता है. और नीतीश कुमार की समझदारी के ऊपर विश्वास रखते हुए भी यह विश्वास नहीं होता कि वे ऐसे लोगों से फिलहाल मुक्ति पा सकेंगे. और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार के पास देश की लड़ाई लड़ने के लिए धन नहीं है. बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते वो धन के लिए कोई कोशिश करेंगे, इसका विश्वास भी नहीं है. क्योंकि नीतीश कुमार देश के उन चंद लोगों में हैं जिन पर किसी भी तरह का कोई दाग नहीं है. देश के लोगों को उनमें तीन प्रधानमंत्रियों का सम्मिश्रण दिख रहा है, जिनमें वीपी सिंह, चंद्रशेखर और अटल विहारी वाजपेई हैं. इन तीनों की छवियां, तीनों की विचारधाराएं और तीनों के एक्शन कहीं न कहीं नीतीश कुमार में दिखाई देते हैं.

चुनौतियां ही चुनौतियां

पुराने बिन वापस लाने की जद्दोजहद...

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

पृष्ठ 1 का शेष

है और उन्हें बिहार में जिस तरह महिलाओं का राजनीतिक समर्थन मिला है और वो राजनीतिक रूप से जिस तरह से गोलबंद हुई हैं, उसने नीतीश कुमार का उत्साह बढ़ा दिया है. नीतीश कुमार के पास देशभर की महिलाओं के समर्थन की चिट्ठियों के अंबार लगे हुए हैं. महिलाओं के प्रतिनिधिमंडल उनसे पटना जाकर मिल रहे हैं. नीतीश कुमार ने सारे देश में मद्यनिषेध के पक्ष में शराबबंदी लागू करने के लिए अभियान चलाने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत वो 15 मई को लखनऊ से करने जा रहे हैं. मुलायम सिंह के लोग नीतीश कुमार के इस कदम को राजनीतिक कदम के रूप में देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार की राजनीतिक पहल का प्रारंभ मान रहे हैं. उत्तर प्रदेश के वो सारे वर्ग, जिनमें मुख्यत: किसान हैं और जो अब तक मुलायम सिंह के समर्थक रहे हैं, वो अब नीतीश कुमार के समर्थन में खड़े हैं. नीतीश कुमार को मिल रहे समर्थन या मिलने वाले संभावित समर्थन के पक्ष में मुलायम सिंह का एक बयान काफी मदद कर रहा है. मुलायम सिंह ने ये कहा कि मैंने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिराई और चंद्रशेखर की सरकार बनवाई. जब वीपी सिंह की सरकार गिरी थी उस समय वीपी सिंह की सरकार के गिरने के पीछे का सबसे बड़ा कारण उनका मंडल कमीशन लागू करना था. इस मंडल कमीशन ने सारे देश में, हिंदुस्तान के पूरे इतिहास में पहली बार पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी दी. आज देश की बदली हुई राजनीति की जड़ में विश्वनाथ प्रताप सिंह का मंडल कमीशन लागू करने का फैसला था. सारे पिछड़े वर्ग के बीच ये सवाल पूछा जा रहा है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजपूतों के लिए, सवर्णों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, सवर्ण गरीबों के लिए कोई निर्णय लागू नहीं किया. उन्होंने तो पिछड़ों के पक्ष में निर्णय लागू किया, जिसने देश में मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, एचडी देवगौड़ा, उमा भारती जैसे पिछड़े नेताओं का नेतृत्व स्थापित कर दिया, तो उस नेता के खिलाफ मुलायम सिंह क्यों खड़े हुए, उसकी सरकार क्यों गिराई, जो देश मे मंडल मसीहा माना जाता है. पत्रकार के नाते मुझे लगता है कि मुलायम सिंह से चूक हुई है और मुलायम सिंह का ये कहना कि मैंने वीपी सिंह की सरकार गिरवाकर चंद्रशेखर की सरकार बनाई, यह संदेह पैदा करता है कि मुलायम सिंह मंडल कमीशन के पक्ष में थे भी या नहीं.

उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार के पास संपूर्ण पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों का आना जाना लगा है. उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पिछड़े वर्ग का तबका कुर्मी, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ताकतवर पिछड़े यादव समाज से कहीं कम नहीं है, बल्कि गावों में उनसे ज्यादा मजबूत है. कुर्मी समाज नीतीश कुमार के साथ खड़ा हो गया है. अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज और मुस्लिम समाज को अपने साथ ले लेते हैं, तब ये स्थिति एक तरफ मुलायम सिंह जी के लिए और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर देगी.

नीतीश कुमार के लिए दूसरी बड़ी चुनौती कर्नाटक में है. कर्नाटक में एचडी देवेगौड़ा आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के विरोधी माने जाते हैं, लेकिन उनके पुत्र कुमार स्वामी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक माने जाते हैं. मुझसे श्री देवेगौड़ा ने एक रहस्य खोला कि मैंने अपनी पत्नी के सामने अपने बेटों को बुलाया और मैंने उनसे साफ पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते हुए आप भारतीय जनता पार्टी से कोई समझौता करेंगे. मेरे बेटों ने मुझे मेरी पत्नी के सामने आश्वस्त किया है कि आपके जिंदा रहते हुए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई चुनावी गठबंधन नहीं करेंगे और न ही उसके साथ जाएंगे, लेकिन कर्नाटक में देवेगौड़ा के समर्थक वर्ग और कांग्रेस समर्थक वर्ग में अंतरविरोध है. देवेगौड़ा के ही बनाए हुए सिद्धारमैया इस समय कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं. कुमार स्वामी को लगता है कि जब तक सिद्धारमैया नहीं हटते तब तक कांग्रेस के साथ उनका समझौता नहीं हो सकता. उनका ज्यादा आसानी के साथ समझौता भाजपा के साथ हो सकता है. प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष बीएस येदुरप्पा के साथ ज्यादा आसानी के साथ समझौता हो सकता है. इस अंतरविरोध को दूर करना नीतीश कुमार के लिए बड़ा चैलेंज है. देवेगौड़ा केरल में एमपी वीरेंद्र कुमार के जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने को बहुत गुस्से से देख रहे हैं. इसलिए केरल में भी यही चुनौती नीतीश कुमार के सामने है.

नीतीश कुमार के सामने तीसरी बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में पार्टी को खड़ा करना है और उन सारी ताकतों को अपने साथ समेटना है, जो पिछले दो सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निराश हुए या निराशा की तरफ बढ़ रही हैं. नीतीश कुमार के सामने यह चुनौती इसलिए है, क्योंकि अगर वह 2019 के चुनाव में विपक्ष के साझा प्रत्याशी बनते हैं, तो इन राज्यों में नीतीश कुमार के समर्थक तो हैं, लेकिन समर्थक संगठन नहीं हैं. यहां पर मुलायम सिंह यादव और मायावती मिलकर नीतीश कुमार को बहुत अच्छी तरह परेशान कर सकते हैं. नीतीश कुमार के सामने आखिरी सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी स्वयं हैं. नीतीश कुमार की अब तक की जो योजना समझ में आई है, वो यह कि नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए या संघ मुक्त भारत के नारे को साकार करने के लिए उन्हें कांग्रेस के समर्थन की भी जरूरत होगी, क्योंकि कांग्रेस पुरानी पार्टी और उसके लोग अभी भी गांव–गांव में हैं. पर कांग्रेस की जिस तरह की निर्णय पद्धति है, उसमें कांग्रेस के लोग राहुल गांधी का इस्तेमाल करने की जगह उन्हें कन्फ्यूज करने में ज्यादा रुचि रखते हैं.

नीतीश के लिए सबसे आसान हरियाणा है, जहां ओमप्रकाश चौटाला ने उनसे कह रखा है कि वे जब कहेंगे तब वे उनके साथ आ जाएंगे. उनकी कोई शर्त भी नहीं है, पर चौटाला के मन में डर अवश्य है कि कहीं चौधरी अजीत सिंह उनके प्रदेश में हस्तक्षेप करना न शुरू कर दें. चौटाला और अजीत सिंह के बीच जाट नेतृत्व को लेकर अघोषित युद्ध चलता रहा है.

आज सारे देश में राहुल गांधी को खुद कांग्रेस के लोगों ने हंसी का पात्र बना डाला है, लेकिन नीतीश कुमार का मानना है कि वो राहुल गांधी के साथ देश में संघ मुक्त नारे की रणनीति बना सकते हैं. पर राहुल गांधी को उनके साथी समझा रहे हैं कि अगर आपने एक बार भी नीतीश कुमार का समर्थन किया, तो फिर आपके हाथ से भविष्य के प्रधानमंत्री पद की ओर जाने की उम्मीद नीतीश कुमार के साथ चली जाएगी. यह जो भविष्य का डर है, ये नीतीश कुमार को विपक्ष का सर्वमान्य उम्मीदवार बनने देगा या नहीं बनने देगा, यह बहुत बड़ा प्रश्न है. नीतीश के लिए सबसे आसान हरियाणा है, जहां ओमप्रकाश चौटाला ने उनसे कह रखा है कि वे जब कहेंगे, तब वे उनके साथ आ जाएंगे. उनकी कोई शर्त भी नहीं है, पर चौटाला के मन में डर अवश्य है कि कहीं चौधरी अजीत सिंह उनके प्रदेश में हस्तक्षेप करना न शुरू कर दें. चौटाला और अजीत सिंह के बीच जाट नेतृत्व को लेकर अघोषित युद्ध चलता रहा है. हालांकि चौधरी चरण सिंह के समय चौधरी देवीलाल जी उनके साथ थे, पर चौधरी चरण सिंह के देहांत के बाद स्थितियां बदल गईं.

उत्तर प्रदेश में भी अजीत सिंह नीतीश के साथ किन शर्तों के साथ आएंगे, यह प्रश्न जिंदा है. अफवाहें चारों तरफ हैं कि अजीत सिंह एक ओर कांग्रेस से बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा से. वे मायावती से भी बात करना चाहते हैं. उनके पुत्र जयंत चौधरी की रणनीति कुछ अलग दिखाई देती है. वे हर सभा में अपने को चौधरी चरण सिंह का पोता बताते हैं. उत्तर प्रदेश की राजनीति की इस पहेली को सुलझाना नीतीश कुमार के लिए थोड़ा मुश्किल होगा. उत्तर प्रदेश में ही पीस पार्टी नीतीश के साथ मिल कर चुनाव लड़ना चाहती है. बहुत सारी और छोटी पार्टियां हैं, जो नीतीश के साथ आना चाहती हैं, पर सबके साथ बड़े अंतरविरोध भी हैं. नीतीश की अपनी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा समर्थक आधार नहीं है, पर अब सभी नेता अपने लिए अग्रिम पंक्ति में स्थान सुनिश्चित करना चाहते हैं. यह स्थिति वीपी सिंह के साथ भी थी और अब यही नीतीश के साथ भी है.

क्या नीतीश कुमार उड़ीसा में नवीन पटनायक, बंगाल में ममता बनर्जी, दक्षिण में के. चंद्रशेखर राव से कोई संवाद बना पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार भी ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, जो किसी भी राजनीतिक फैसले में पहले अपना स्वार्थ देखते हैं. उन्हें देश में वैचारिक लड़ाई की जगह अपना स्थान पहले नजर आता है. और नीतीश कुमार की समझदारी के ऊपर विश्वास रखते हुए भी यह विश्वास नहीं होता कि वे ऐसे लोगों से फिलहाल मुक्ति पा सकेंगे. और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार के पास देश की लड़ाई लड़ने के लिए धन नहीं है. बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते वो धन के लिए कोई कोशिश करेंगे, इसका विश्वास भी नहीं है. क्योंकि नीतीश कुमार देश के उन चंद लोगों में हैं, जिन पर किसी भी तरह का कोई दाग नहीं है. देश के लोगों को उनमें तीन प्रधानमंत्रियों का सम्मिश्रण दिख रहा है, जिनमें वीपी सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी हैं. इन तीनों की छवियां, तीनों की विचारधाराएं और तीनों के एक्शन कहीं न कहीं नीतीश कुमार में दिखाई देते हैं.

इसलिए नीतीश कुमार की ये रचनात्मक पहल कि सारे देश में वो शराबबंदी के लिए जाएंगे और हर जगह शराबबंदी के लिए आवाज उठाएंगे, उन्हें देश में मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में एक अनूठा राजनेता बनाती है. हालांकि, इस बात के खतरे हैं कि नीतीश कुमार के साथ के लोग उनके साथ रहते हुए उनके कदमों को कमजोर करें. इस बात की आशंका है कि सारे देश का शराब माफिया मिलकर नीतीश कुमार को बिहार में ही सत्ता से उतारने की पहल शुरू कर दे. और अगर उसके लिए उसे पांच हजार करोड़ भी खर्च करने पड़े तो वह ऐसा कर सकते हैं. इसका मुकाबला करने का नीतीश कुमार के पास सिर्फ एक ही साधन है और वह है देश की जनता. देखते हैं कि नीतीश कुमार अपने सामने आने वाली इन चुनौतियों का कैसे सामना करते हैं हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती मान रहे हैं. इसीलिए वो नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से अनदेखा कर राहुल गांधी को अपना मुख्य विरोधी बता रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो राहुल गांधी को आसानी से गिरा सकते हैं. यही काम एक जमाने में इंदिरा गांधी ने किया था. वो अपने सामने संघ को मुख्य विरोधी बनाती थीं, जबकि संघ उस समय राजनीतिक तौर पर कहीं मजबूत था ही नहीं और कदम भी नहीं उठा रहा था, जिसका इंदिरा जी को बहुत फायदा मिला. आज वही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं. इसलिए नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां इतनी गंभीर हैं कि उन चुनौतियों के भंवरजाल से नीतीश कुमार का निकलना एक राजनीतिक कौशल का उदाहरण होगा. पर देश के सामने एक नई राजनीतिक लड़ाई, जिसे हम देश में सालों बाद मुद्दे की लड़ाई के रूप में देखेंगे, सामने आने वाली है. देखना है नीतीश कुमार को मुलायम सिंह यादव से कितनी चुनौती मिलती है और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को घेरने के लिए उन्हीं के किन–किन साथियों के साथ हाथ मिलाते हैं. खेल मजेदार है. मीडिया पूरा नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह के साथ खड़ा है. नीतीश कुमार के विरोध में है. नीतीश कुमार भंवर से निकलेंगे या भंवर में लुप्त हो जाएंगे इसका बहुत बड़ा दारोमदार खुद नीतीश कुमार पर ही है. ■

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 09
02 मई–08 मई 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

वर्तमान में बिहार में पूर्ण शराबबंदी का इतना असर है कि सामाजिक स्तर पर लोगों में एकजुटता बढ़ने लगी है. दशकों से सामाजिक परंपरा से खुद को अलग कर चुके बुजुर्ग भी एक बार फिर से सक्रिय नज़र आने लगे हैं. शराबबंदी का आलम यह है कि युवा वर्ग भी अब नशे के सेवन से अलग पड़ने लगे हैं. शादी सहित अन्य मांगलिक अवसरों में शराब के नशे में धुत्त लोगों का हंगामा थम गया है. बारातों में फिल्मी गीतों की धुन पर थिरकने वाले युवाओं के पैर में शराबबंदी की बेड़ियां लग गई हैं. वहीं महिलाओं में उत्साह के साथ सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है.

शराबबंदी की मुहिम राष्ट्रव्यापी बनाएंगे नीतीश

बिहार पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि शराबबंदी के बाद अपराधियों के सिर से जुर्म का नशा उतरने लगा है. हत्या और बलात्कार जैसी वारदातों में गिरावट आई है. यातायात पुलिस के एक मोटे आकलन के अनुसार सड़क हादसों में भी पचास फीसदी की कमी आई है. मार्च में पटना जिले में जहां हत्या के 24 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं शराबबंदी लागू होने के 15 दिनों के बाद महज़ आठ मामले दर्ज किए गए हैं. इसी तरह बलात्कार, डकैती और अपहरण के मामलों में भी कमी आई है. यह हाल केवल पटना जिले का नहीं है, बल्कि बिहार के लगभग सभी जिलों में अपराध कम हुए हैं.

सरोज सिंह

कहते हैं सच्चे दिल से लिया गया फैसला चाहे जितना कठिन हो इसे पूरा करने में धीरे-धीरे हर सच्चे आदमी का सहयोग मिलने लगता है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब राज्य में पूर्ण शराबबंदी का फैसला लिया, उस समय तो ऐसा लगा कि यह जल्दबाजी में लिया गया राजनीतिक फैसला है और इसके सफल होने के आसार बेहद कम हैं. लेकिन शराबबंदी को लागू हुए अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ और ऐसा लगने लगा है कि नीतीश कुमार अपने सपने को पूरा करने की राह में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं. अब आलम यह है कि समाज के तकरीबन हर तबके और वर्ग ने नशाबंदी को समर्थन देना शुरू कर दिया है. हालांकि, नशा करने वाले अभी जुगाड़ तंत्र के जरिए कुछ हासिल कर ले रहे हैं लेकिन लगातार हो रही पुलिसिया छापेमारी से जल्द ही इस जुगाड़तंत्र के टूट जाने के आसार हैं. मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं स्वयं जानता हूं कि यह काम कठिन है लेकिन यह संकल्प पूरा होगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है. नीतीश कुमार कहते हैं कि जिस तरह से नशाबंदी की आवाज़ दूसरे राज्यों में उठने लगी है, उससे साफ है कि मेरी नीति और नीयत दोनों ठीक है और जल्दी ही इसका असर पूरे देश में देखने को मिलेगा. बिहार में पूर्ण शराबबंदी का नीतीश कुमार का फैसला अब पूरे देश में एक नजीर बनता जा रहा है.

वैसे तो शराबबंदी ने अपना प्रभाव हर जगह छोड़ा है लेकिन इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव का आकलन करना यहां बेहद जरूरी हो जाता है. पहले बात सामाजिक प्रभाव की ही करते हैं क्योंकि राजनीतिक प्रभाव बहुत हद तक इसी से जुड़ा है. सूबे की आधी आबादी यानी सूबे की महिलाओं का शराबबंदी को व्यापक समर्थन मिल रहा है. प्रत्येक घर में नीतीश कुमार की शराबबंदी की ही चर्चा है. महिलाओं का कहना है कि यदि नीतीश कुमार ने यह कदम कुछ समय पहले उठाया होता तो कई घर उजड़ने से बच जाते. जानकार बताते हैं कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने शराबबंदी का ऐलान कर चुनावी जीत का अचूक तीर चला दिया था. महिलाओं के वोट तो पहले भी नीतीश कुमार को मिलते रहे हैं पर पूर्ण शराबबंदी के ऐलान ने महिला वोटरों को पूरी तरह नीतीश कुमार के पाले में कर दिया. महिलाओं ने नीतीश कुमार के वादे पर भरोसा किया और महागठबंधन के पक्ष में जमकर वोट डाले. मतदान के दिन महिलाओं की लंबी-लंबी कतारें इसकी गवाह हैं. इन कतारों को देखकर लोगों ने कहा कि लालू के जंगलराज से नाराज़ महिलाओं ने भाजपा के पक्ष में वोट डाला. लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो बड़े-बड़े राजनीतिक पंडित धराशाई हो गए और नीतीश कुमार का महागठबंधन दो तिहाई सीटों के साथ सत्ता में आ गया. राजनतिक पंडितों का मानना है कि महादलित, अतिपिछड़ा के बाद अब महिलाओं के वोट बैंक पर भी नीतीश कुमार का कब्जा हो चुका है. नीतीश की यही ताकत उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा किरदार बनाएगी. नीतीश के हाल के बयानों और क्रियाकलापों से ऐसा दिखने भी लगा है. नीतीश अपने शराबबंदी के कार्यक्रम को पूरे देश में फैलाना चाह रहे हैं. अब वह अपने प्रत्येक भाषण में कह रहे हैं कि शराबबंदी की अपनी मुहिम को वह देशव्यापी बनाएंगे. कई राज्यों से उन्हें न्यौता भी आया है.

शराबबंदी के अपने फैसले को लेकर नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत होकर उभरे हैं. विधानसभा चुनाव में लाभ उठाने के बाद अब वह साल 2019 की लड़ाई में अपने इस शस्त्र का जमकर उपयोग करना चाहते हैं. यही वजह है कि यूपी में इसी महीने शराबबंदी को लेकर हो रहे एक बड़े आयोजन में नीतीश शरीक हो रहे हैं. इसी तरह दूसरे राज्यों में भी वे शराबबंदी के लिए अभियान चलाएंगे.

बिहार पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि शराबबंदी के बाद अपराधियों के सिर से जुर्म का नशा उतरने लगा है. हत्या और बलात्कार जैसी वारदातों में गिरावट आई है. यातायात पुलिस के एक मोटे आकलन के अनुसार सड़क हादसों में भी पचास फीसदी की कमी आई है. जहां मार्च में पटना जिले में हत्या के 24 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं शराबबंदी लागू होने के 15 दिनों के बाद महज़ आठ मामले दर्ज किए गए हैं. इसी तरह बलात्कार, डकैती और अपहरण के मामलों में भी कमी आई है. यह हाल केवल पटना जिले का नहीं है, बल्कि बिहार के लगभग सभी जिलों में अपराध कम हुए हैं. पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि महिला उत्पीड़न के मामले अप्रत्याशित रूप से घटे हैं. महिलाओं के हक़ के लिए काम करने वाली डॉ आशा सिन्हा कहती हैं कि मर्द शराब के नशे में महिलाओं पर ज्यादा अत्याचार करते हैं. अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए वे मारपीट का सहारा लेते हैं. और इसके लिए वह शराब को अपना हथियार बनाते हैं. अगली सुबह यह कहकर समझौता कर लेते हैं कि रात में कुछ ज्यादा पी ली इसलिए यह सब हो गया. लेकिन अगली रात वे फिर ऐसा ही करते हैं. दरअसल शराब मर्दों को जुर्म करने का साहस देती है. शराब पीकर वे सही-गलत में फर्क नहीं कर पाते और जुर्म कर बैठते हैं. लेकिन शराबबंदी के बाद हालात बदले हैं और रात में घरों का माहौल खुशनुमा होने लगा है. खासकर बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं है. वे अब घर लौटे पापा से डांट की बजाय प्यार पा रहे हैं और अपनी पढ़ाई को लेकर उनसे समझ भी रहे हैं.

शराबबंदी ने अपना प्रभाव हर जगह छोड़ा है लेकिन इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव का आकलन करना यहां बेहद जरूरी हो जाता है. पहले बात सामाजिक प्रभाव की ही करते हैं क्योंकि राजनीतिक प्रभाव बहुत हद तक इसी से जुड़ा है. सूबे की आधी आबादी यानी सूबे की महिलाओं का शराबबंदी को व्यापक समर्थन मिल रहा है. प्रत्येक घर में नीतीश कुमार की शराबबंदी की ही चर्चा है. महिलाओं का कहना है कि यदि नीतीश कुमार ने यह कदम कुछ समय पहले उठाया होता तो कई घर उजड़ने से बच जाते. जानकार बताते हैं कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने शराबबंदी का ऐलान कर चुनावी जीत का अचूक तीर चला दिया था.

शराबबंदी के अपने फैसले को लेकर नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत होकर उभरे हैं. विधानसभा चुनाव में लाभ उठाने के बाद अब वह साल 2019 की लड़ाई में अपने इस शस्त्र का जमकर उपयोग करना चाहते हैं. यही वजह है कि यूपी में इसी महीने शराबबंदी को लेकर हो रहे एक बड़े आयोजन में नीतीश शरीक हो रहे हैं. इसी तरह दूसरे राज्यों में भी वे शराबबंदी के लिए अभियान चलाएंगे. जानकार बताते हैं कि शराबबंदी का विरोध कोई भी राजनीतिक दल खुलकर नहीं कर सकता है और इसी का पूरा लाभ नीतीश कुमार को मिल रहा है. नरेंद्र मोदी ने शराबबंदी को केवल अपने राज्य गुजरात तक सीमित रखा लेकिन नीतीश कुमार इसे राष्ट्रीय पटल पर रखने की मुहिम में जुट गए हैं. शराबबंदी की सौ फीसदी सफलता के मार्ग में अभी ढेर सारी चुनौतियां हैं खासकर सीमाई इलाकों में यह एक कठिन काम है. शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं और अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं. ऐसे हालात में अब एक अहम सवाल यह कि क्या बिहार सरकार इस क़ानून को लागू रख पाने में सफल होगी? क्योंकि अभी भी कई ऐसे रास्ते बचे हैं, जिनसे होकर सरकार के इस क़ानून को तोड़ा जा सकता है. यह अलग बात है ऐसा एक दायरे तक ही संभव है. लेकिन इस दायरे के कम से अधिक होने की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता है. दूसरा यह कि उत्तर बिहार के कई जिले नेपाल की सीमा से जुड़े हैं. शराब कारोबारी किसी भी तरह अपना कारोबार करने से बाज नहीं आने वाले है. उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी व दरभंगा सहित कई जिले ऐसे हैं, जिनकी सीमा नेपाल से लगी है. भारत-नेपाल सीमा के खुले रहने की वजह इन क्षेत्रों में अवैध कारोबारी हर वक्त सक्रिय रहे हैं. वर्तमान में सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की सक्रियता भी देखी जा रही है. मगर यह कितने दिनों तक कायम रह पाएगी. इसको लेकर संशय बना हुआ है. जानकारों की मानें तो एसएसबी बहुत अधिक दिनों तक भारत-नेपाल सीमा पर शराबबंदी को लेकर जारी फरमान को अमल में नहीं रख सकती. इसका कारण यह है कि सीमा क्षेत्र में सक्रिय कुछ तत्वों की ज़मात अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए एसएसबी के खिलाफ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भड़काकर अपना काम निकालते रहे हैं. एसएसबी की कहीं न कहीं कुछ ऐसी मजबूरियां बनती रहीं हैं कि उसे उक्त लोगों के साथ समझौता करके काम करना पड़ता है. यदि एसएसबी की समझौतावादी विचारधारा कारगर हुई तो उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में नेपाली शराब आसानी से उपलब्ध होने लगेगी. जिससे बिहार सरकार द्वारा लागू क़ानून पर असर पड़ने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है. वैसे वर्तमान में एसएसबी की सख्ती सीमा पर देखी जा रही है. हालांकि, सीमावर्ती जिला सीतामढ़ी के जिला पदाधिकारी राजीव रौशन व एसपी हरि प्रसाथ एस एवं शिवहर जिला पदाधिकारी राजकुमार और एसपी प्रकाशनाथ मिश्र ने शराबबंदी को पूर्णतः लागू कराने को लेकर कई आवश्यक कदम उठाए हैं. इन जिलों में तो गांवों की गलियों तक प्रशासन की पैनी नज़रें घूम रही हैं. दूसरी ओर बिहार में मौजूद कैंटीनों पर भी सख्त पहरे की दरकार है. इसका कारण यह है कि शराबबंदी के बाद नशे के आदी लोगों की नजरें सेवा निवृत सैनिकों के शराब कोटे को तलाशने लगी हैं. बिहार में दानापुर सैनिक छावनी के अलावा मुज़फ्फरपुर में मौजूद सेना कैंटीन सहित एसएसबी कैंटीन पर भी उक्त लोगों की नजरें हैं. सैनिकों को प्रतिमाह मिलने वाले शराब के कोटे के उठाव को लेकर जाल फैलाया जाने लगा है. संभव है अगर इस दिशा में कुछ भी सफलता मिली तो सरकारी क़ानून लागू करने का मतलब नहीं रह जाएगा.

इसके अलावा पड़ोसी राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश से आने वाले वाहनों की जांच नियमित तौर पर कराने की आवश्यकता है. खासकर व्यावसायिक वाहनों पर पैनी नज़र रखना जरूरी है. वर्तमान में बिहार में पूर्ण शराबबंदी का इतना असर है कि सामाजिक स्तर पर लोगों में एकजुटता बढ़ने लगी है. दशकों से समाजिक परंपरा से खुद को अलग कर चुके बुजुर्ग भी एक बार फिर से सक्रिय नज़र आने लगे हैं. शराबबंदी का आलम यह है कि युवा वर्ग भी अब नशे के सेवन से अलग पड़ने लगे हैं. शादी सहित अन्य मांगलिक अवसरों में शराब के नशे में धुत्त लोगों का हंगामा थम गया है. बारातों में फिल्मी गीतों की धुन पर थिरकने वाले युवाओं के पैर में शराबबंदी की बेड़ियां लग गई हैं. वहीं महिलाओं में उत्साह के साथ सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है. अब जरूरत है इस क़ानून को कायम रखने की. बिहार में लागू शराबबंदी क़ानून की सफलता सूबे के सामाजिक परिवेश को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है. नशे की लत के कारण अपराध के दल-दल में फंस रहे युवा वर्ग को नई दिशा मिलेगी और अपराध की घटनाओं पर नकेल भी कसेगी. गरीबों की बस्ती में खुशहाली और बच्चों की किलकारी भी गूंजेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

चुनाव आयोग और सरकार के बीच खिंची रही तलवार

विनय बिहारी सिंह

विधानसभा चुनाव ख़त्म होने को है और लोगों की निगाहें 19 मई की ओर लगी हैं, क्योंकि इसी दिन मतगणना होगी. इस बीच चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच खूब तनातनी रही. कई बार दिलचस्प मोड़ आए, फिर तनावपूर्ण मोड़ आए, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन परिस्थितियों का रणनीतिक तरीके से निपटारा किया और दहाड़ती रहीं. विपक्षी पार्टियां भी कमर कस कर उन पर हमले करती रहीं और अब भी कर रही हैं. मार्च के दूसरे सप्ताह में चुनाव आयोग ने राज्य के लगभग 40 पुलिस अधीक्षकों–ज़िलाधिकारियों आदि का तबादला कर दिया. क़रीब–क़रीब सभी ज़िलों में ऐसा हुआ. अप्रैल में एक और तबादला हुआ. दो महीने पहले नियुक्त किए गए कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार का तबादला कर दिया गया, उनकी जगह एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी सोमेन मित्र को पुलिस आयुक्त बनाया गया. ज़ाहिर है, चुनाव आयोग ने इतनी बड़ी संख्या में प्रशासनिक फेरबदल किया कि ज़्यादातर लोगों का चौंकना स्वाभाविक था. इससे राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच तनाव बढ़ता गया. राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग विरोधी पार्टियों की बातों पर ज़्यादा भरोसा कर रहा है.

अप्रैल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह आसनसोल को ज़िला बनाएंगी. फिलहाल आसनसोल बर्दवान ज़िले में है. आसनसोल को ज़िला बनाने की बात राज्य सरकार बहुत पहले से कह रही है. ममता बनर्जी ने अपनी यह पुरानी बात चुनाव के दौरान दोहराई. इस पर चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनके ख़िलाफ़ कारण बताओ नोटिस जारी कर दी. नियम है कि चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री या मंत्री जनता से कोई वादा नहीं कर सकते, क्योंकि यह जनता को लालच देना माना जाएगा. चुनाव आयोग की नोटिस पर ममता बनर्जी ने कहा, मेरे भी कुछ मौलिक अधिकार हैं, मैं एक–एक आरोप का जवाब दूंगी. चूंकि यह नोटिस एक मुख्यमंत्री को दिया गया था, इसलिए इसका जवाब राज्य के मुख्य सचिव वासुदेव चटर्जी ने दिया. चुनाव आयोग ने कहा कि यह जवाब मान्य नहीं है. नोटिस का जवाब ममता बनर्जी खुद दें या उनके वकील दें. इस पर स्वयं ममता बनर्जी ने नोटिस का जवाब दिया.

बाहुबली नज़रबंद

सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका तब लगा जब पिछले दिनों पार्टी के बीरभूम जिले के अध्यक्ष अणुव्रत मंडल को चुनाव आयोग ने लगातार निगरानी में रख दिया. उनकी हर गतिविधि चुनाव खत्म होने तक वीडियो में कैद होती रहेगी और सुरक्षा बल के जवान, वीडियो फोटोग्राफर और चुनाव आयोग के एक अधिकारी उन पर लगातार नजर. अणुव्रत मंडल को पश्चिम बंगाल की राजनीति का बाहुबली कहा जाता है. लेकिन अणुव्रत मंडल इसे लेकर तनिक भी तनाव में नहीं हैं. वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हैं, बैठकें करते हैं और जहां जाना- आना होता है, जाते हैं. हां, उनका पीछा केंद्रीय सुरक्षा बल करता रहता है. बोलपुर रेलवे ब्रिज के पास नीचू पट्टी स्थित उनकेघर पर या थोड़ी दूर उनके कार्यालय पर सुरक्षा बलों का पहरा है. सुरक्षा बलों को उनके कार्यकर्ता मानवीय आधार पर गुड- बताशा, पानी देते रहते हैं. ■

इसके बाद कोलकाता में विपक्षी नेता आएदिन नारदा टेप प्रकरण और विवेकानंद फ्लाईओवर गिरने का मुद्दा उछालने लगे. इस बार का विधानसभा चुनाव सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए इसलिए भी तनाव से भरा रहा, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन का टेप फोरेंसिक जांच के लिए अपने पास मंगा लिया. हाईकोर्ट ने कहा, यदि टेप सच साबित हुआ, तो यह लोक प्रतिनिधियों की छवि हमेशा के लिए धूमिल करने वाला होगा. ममता बनर्जी ने स्वयं कहा कि अगर नारदा टेप पहले सामने आ जाता, तो वह कुछ नेताओं को टिकट देने के प्रति सावधान हो जातीं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह स्वयं नारदा टेप की असलियत जानना चाहती हैं. बकौल ममता, आप सबने टीवी पर वीडियो क्लिप देखा होगा. मैं चाहती हूं कि सच्चाई सामने आए. मैं इतना कह सकती हूं कि पार्टी के किसी व्यक्ति ने निजी हितों के लिए किसी से एक पैसा नहीं लिया. कुछ लोग डर पैदा करना चाहते हैं. आप लोग डरें नहीं. चिंता करने की कोई बात नहीं है, तृणमूल कांग्रेस फिर सत्ता में आ रही है.

ममता ने कहा, सभी पार्टियां चुनाव के दौरान धन लेती हैं. कांग्रेस, भाजपा एवं सीपीएम अपवाद नहीं हैं. मेरे पास दस्तावेज़ हैं, जो बताते हैं कि कांग्रेस का क़रीब 82.5 प्रतिशत, भाजपा का 73 प्रतिशत और सीपीएम का 53.8 प्रतिशत चुनाव फंड अज्ञात स्रोतों से आता है. तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में ख़तरनाक चाल चल रही है. ममता ने कहा कि लोग विकास के मुद्दे पर वोट देंगे. राज्य में विकास हुआ है और लोग इसे देख रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस नेता एवं पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को ममता ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने से रोक दिया और उन्हें घर पर आराम करने को कहा है. वजह यह कि उन्होंने मीडिया से कहा था कि यदि वह मुख्यमंत्री होते, तो नारदा कांड में लिप्त नेताओं को घर बैठा देते और कहते कि जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाते, घर बैठो, चुनाव मत लड़ो. पिछले दिनों दिनेश त्रिवेदी ने यह भी कहा था कि राजनीति के दो हिस्से हैं. एक आज़ादी के पहले का और दूसरा आज़ादी के बाद का. आज़ादी के पहले के नेता देश और जनता के लिए मर–मिटने को तैयार रहते थे, लेकिन आज़ादी के बाद के नेताओं में देशसेवा के प्रति उत्साह नहीं रहा, वे धन केंद्रित राजनीति करने लगे.

आइए एक बार वाम मोर्चा की तरफ़ देखें, जो ममता बनर्जी के सत्ता में आने के पहले 34 वर्षों तक शासन में रहा. सीपीएम नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने अप्रैल के तीसरे सप्ताह में सीपीएम–कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में कस्बा, जादवपुर एवं टालीगंज में चुनाव प्रचार किया, तो लोगों में भारी उत्साह दिखा. हाल के दिनों में कम्युनिस्ट नेताओं की रैलियों में इतना उत्साह नहीं था. इसका अर्थ यह नहीं कि उक्त भीड़ वोटों में तब्दील हो जाएगी. लेकिन हां, सीपीएम– कांग्रेस गठजोड़ को पहले की तुलना में सीटें ज़्यादा मिलेंगी. इस बार गठजोड़ को कम से कम सौ सीटें मिलने की उम्मीद है. इससे ज़्यादा हो जाएं, तो आश्चर्य की बात नहीं. वजह यह कि नारदा स्टिंग ऑपरेशन टेप को लेकर आरोप–प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा था कि निर्माणाधीन विवेकानंद फ्लाईओवर भरभरा कर गिर पड़ा. इससे ममता बनर्जी की छवि को खासा धक्का लगा. फिर भी उनके सत्ता में वापस आने के दावे को नकारा नहीं जा सकता. अभी भी बड़ी संख्या में लोग ममता को ईमानदार मानते हैं. लोगों का कहना है कि सरकार ममता की बनेगी. हां, सीटें पहले की तुलना में कुछ कम हो सकती हैं. 294 सीटों वाली राज्य विधानसभा में पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 184 सीटें मिली थीं. जबकि कांग्रेस को 42 और सीपीएम को 40 सीटें मिली थीं.

उधर सीपीएम–कांग्रेस गठजोड़ के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी माकपा के राज्य सचिव एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सूर्यकांत मिश्र हैं. निश्चय ही इस बार ममता बनर्जी के लिए चुनाव आसान नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दौड़ में कहीं नहीं है. भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल बार–बार आ रहे हैं और चिर परिचित अंदाज़ में भाषण दे रहे हैं, लेकिन उनका राज्य में कोई असर नहीं दिख रहा है. लोग केंद्र सरकार की रीति–नीति से खुश नहीं हैं. राज्य की 23 सीटें ऐसी हैं, जहां 1977 से लेकर अब तक सीपीएम कभी भी नहीं हारी. भले ही उनमें से कुछ सीटों पर वह बहुत कम वोटों से जीती हो. उक्त सीटें हैं, धूपगुड़ी (अनुसूचित जाति), माल (अनुसूचित जनजाति), सैंथिया (अनुसूचित जाति), हबीबपुर (अनुसूचित जनजाति), मयूरेश्वर, जालंगी, औसग्राम (अनुसूचित जाति), डोमकल, जमुड़िया, करीमपुर, खंडघोष (अनुसूचित जाति), पलाशीपाड़ा, तालडांगरा, रायपुर (अनुसूचित जनजाति), मंगलकोट, मंतेश्वर, पांडुआ, बशीरहाट दक्षिण, संदेशखाली (अनुसूचित जनजाति), बर्दवान उत्तर, रायना (अनुसूचित जाति), चंद्रकोना (अनुसूचित जाति) और खड़गपुर. सीपीएम–कांग्रेस गठजोड़ कोशिश में है कि वह इन सीटों के बल पर कुछ और सीटों पर काबिज हो जाए. राज्य में कांग्रेस की छवि अब भी खराब है. इसलिए तृणमूल कांग्रेस को बहुमत मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं. ■

मंत्री मेरे पैर छूते हैं

नारद न्यूज के वीडियो में दिखे नेताओं के खिलाफ हाईकोर्ट में मुकदमा दायर है. इस वीडियो में बर्दवान के पुलिस अधीक्षक एसएमएच मिर्जा, नोटों की गड्डी स्वीकार करते हुए दिखाए गए हैं. इस वीडियो की सत्यता और फोरेंसिक जांच केलिए हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है. वीडियो को नारद न्यूज से मंगा कर हाईकोर्ट ने इसे एक बैंक के लॉकर में रखवा दिया है, जिसकी जांच चुनाव खत्म होने पर होगी. इस वीडियो में आईपीएस अधिकारी मिर्जा के कुछ वक्तव्य रोचक हैं. जैसे-

- मुकुल दा (मुकुल रॉय- तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष) अपने हाथ से रुपये नहीं लेते, उन्होंने कहा है कि मिर्जा को दे दो.
- स्वपन देवनाथ (राज्य मंत्री-पशु संसाधन विकास, स्वतंत्र प्रभार) को मैंने मंत्री बनवाया है. मुकुल दा से कह कर उसे मंत्री का ओहदा दिला दिया.
- स्वपन (मंत्री) से जब मेरी मुलाकात होती है, तो वह पांव छूकर प्रणाम करता है.
- सीएम (मुख्यमंत्री) ने मुझे बर्दवान भेजा. क्या करना होगा, मुझे बता दिया. नगरपालिका, पंचायत वोट. सब किया. चुपचाप. ■

feedback@chauthiduniya.com

दलित छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या पर राजस्थान में मचा है राजनीतिक घमासान

वसुंधरा पर राहुल का 'दलितास्त्र'

सुनीता सिंह

अप्रैल का महीना राज्य की राजनीति में एक दूसरी तरह की उथल–पुथल लेकर आया. दरअसल, कांग्रेस को यहां एक ऐसा मुद्दा हाथ लगा, जिसे भुनाने के लिए खुद उसके युवराज यानी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को मैदान में आना पड़ा. राहुल आए. पूरे दम–खम के साथ उन्होंने ताल ठोंकी और अंबेडकर जयंती के मौके पर उन्होंने अपना बरसों पुराना आज़माया 'दलितास्त्र' भी चला ही दिया.

दरअसल, मामला बाड़मेर इलाके का है. पिछले महीने की 29 तारीख को बाड़मेर के नोखा कस्बे के जैन आदर्श टीचर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट में पढ़ने वाली 17 साल की छात्रा डेल्टा मेघवाल की हत्या कर दी गई. उसका शव संस्थान परिसर के अंदर ही पानी की एक टंकी में पाया गया. चेहरे पर बुरी तरह चोट के निशान थे. आशंका जताई गई कि उसकी दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है. राजस्थान के त्रिमोही गांव के दो कमरों के घर में रहने वाली 17 साल की लड़की डेल्टा की आंखें भी सपने देखती थीं. पढ़ने में तेज और कला में टॉपर डेल्टा मेघवाल के शिक्षक पिता हरसंभव प्रयास से उसके हौसलों की उड़ान को परवाज देते ही रहते थे. अभावों के बीच भी पिता के लाड़–प्यार में पली डेल्टा की आंखों में प्रशासनिक अफसर बनने के सपने थे. टीचर्स–ट्रेनिंग पूरा करने के बाद डेल्टा प्रशासनिक अफसर बनना चाहती थी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, डेल्टा को हॉस्टल के वार्डन ने पीटीआइ के कमरे में साफ–सफाई के लिए भेजा था, जहां अकेले पाकर पीटीआई ने डेल्टा से दुष्कर्म किया और फिर पकड़े जाने के डर से उसे मार कर टैंक में फेंक दिया. डेल्टा के पिता महेंद्रा राम के मुताबिक बीते 28 मार्च को रात 8 बजे डेल्टा मेघवाल ने उन्हें फोन किया और बताया कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है. डेल्टा ने यह भी बताया कि हॉस्टल वार्डन प्रिया शुक्ला ने उसे पीटी इंस्ट्रक्टर विजेंदर सिंह का कमरा साफ करने के लिए भेजा. वहां आरोपी विजेंदर सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया. जिस दिन यह घटना हुई उस दिन हॉस्टल के भीतर चार लड़कियां ही मौजूद थीं. बाकी लड़कियां अपने घर गई हुई थीं.

छात्रा डेल्टा की मौत का मामला शुरुआत में अखबारों में भी कोई खास सुर्खियां हासिल नहीं कर सका. स्थानीय स्तर पर एक–दो दिन खबरें छपीं. बयानबाजी हुई. सोशल मीडिया पर चर्चा हुई, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं हुआ. उधर, भाजपा के स्थानीय नेताओं समेत सरकार की ओर से इस बारे में यह प्रचारित किया गया कि यह दुष्कर्म या हत्या का मामला नहीं, बल्कि खुदकुशी का मामला है. कांग्रेस का 13 अप्रैल को दलित सम्मेलन होना था. जानकारों का कहना है कि इस सम्मेलन को प्रदेश स्तर पर ही केंद्रित रखना था, लिहाजा केंद्रीय नेताओं का इससे कोई खास लेना–देना भी नहीं था. सम्मेलन के पोस्टर–प्रचार वाहनों पर भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत प्रदेश के कद्दावर नेताओं का ही बोल–बाला था. दलित सम्मेलन आयोजित होने से दो दिन पहले से यह सुगबुगाहट होने लगी कि राहुल गांधी भी इस सम्मेलन में शिरकत कर सकते हैं. उनके आने पर संशय था, लेकिन 11–12 अप्रैल की रात यह बात भी साफ हो गई कि राहुल गांधी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे.

राहुल गांधी जैसे दिल्ली से ही अपना प्लान चॉक आउट करके निकले थे. वे राजस्थान की धरती पर उतरे तो सीधे बाड़मेर पहुंच गए डेल्टा मेघवाल के गांव. वहां उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और अपनी ओर से उन्हें न्याय की लड़ाई में पूरा साथ देने का वादा किया. इसके बाद राहुल गांधी जयपुर लौट आए और यहां दलित सम्मेलन में हिस्सा लिया. करीब 20 मिनट तक राहुल ने भाषण दिया और दलितों के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरने के लिए तीक्ष्ण बाण चलाए. यहां उन्होंने प्रमुखता से डेल्टा मेघवाल मामले का जिक्र किया और मंच से ही सरकार को चुनौती दी. राहुल गांधी ने मंच से भाजपा को दलित विरोधी करार देते हुए हुंकार भरी कि जब तक इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश नहीं दे दिए जाते, तब तक वे इस मसले को यूं ही नहीं हवा होने देंगे.

राहुल गांधी के इस रुख से सीबीआई जांच का दबाव बनने लग गया था. अगले दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत दूसरे नेताओं ने भी इसी तरह के बयान जारी करके सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया. इस पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मामले पर बढ़ती रार के बीच यह कह कर मुद्दे को और हवा दे दी कि वे इस मसले पर कतई राजनीतिक दबाव में नहीं झुकेंगी. अगर परिजन चाहेंगे तभी सीबीआई जांच की सिफारिश की जाएगी अन्यथा नहीं. अब गेंद कांग्रेस के पाले में थी. लिहाजा, कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने डेल्टा के पिता महेंद्रा राम को बीकानेर लाकर उनकी प्रेस कांन्फ्रेंस करवाई. यहां महेंद्रा राम ने यह कह कर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया कि अगर मुख्यमंत्री यह चाहती हैं कि परिवार सीबीआई जांच की मांग करे, तो वे औपचारिक तौर पर प्रदेश सरकार से निवेदन करते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए. ■

और वसुंधरा ने कर दी सीबीआई जांच की सिफारिश

कांग्रेस-भाजपा के बीच शह-मात के इस खेल को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 19 अप्रैल को सीबीआई जांच की मांग मान कर ठंडा करने की कोशिश की. राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए गृह विभाग को निर्देशित किया. हालांकि, कांग्रेस का दावा है कि इस मामले पर सीबीआई जांच का आदेश सरकार ने कांग्रेस के कड़े रुख को देखते हुए लिया. बहरहाल, कांग्रेसी यह मान कर खुश हैं कि उनके नेता राहुल गांधी की ओर से सीबीआई जांच की मांग उठाने के एक सप्ताह के अंदर ही राज्य सरकार का झुकना प्रदेश में कांग्रेस की बढ़ती पैठ को दर्शाता है, तो वहीं भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि मैडम यानी वसुंधरा राजे ने सीबीआई जांच की मांग मान कर कांग्रेस का लंबे समय तक दलित उत्पीड़न के इस सिरे को पकड़ कर बैठे रहने की रणनीति को धो डाला. इन सबके बीच असल मुद्दा यानी डेल्टा की मौत की असली वजह उसी तरह अंधेरे में गुम हो गई, जैसे देश के अन्य मसले गुम होते जा रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

महिलाओं का हक़ अब मारा नहीं जा सकता

शफ़ीक आलम

महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में स्थित शनि शिंगणापुर मंदिर पिछले दिनों उस समय सुर्ख़ियों में आया, जब एक महिला ने सदियों पुरानी परंपरा–मान्यता तोड़ते हुए मंदिर के उस भाग में प्रवेश किया, जहां मूर्ति स्थापित है और महिलाओं का जाना वर्जित. केरल के सबरीमाला मंदिर के गर्भगृह में 10 से 50 वर्ष तक की महिलाओं के प्रवेश पर लगी पाबंदी हटाने से संबंधित मामले की सुनवाई केदौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान लैंगिक समानता का अधिकार देता है और उक्त आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को मंदिर प्रबंधन द्वारा धार्मिक मामलों के प्रबंधन अधिकार के तौर पर नहीं देखा जा सकता है. मुंबई में कुछ मुस्लिम महिलाओं ने हाजी अली दरगाह के उस हिस्से में प्रवेश की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जहां उनका जाना वर्जित है. महिलाओं से संबंधित एक और मामला सुर्ख़ियों में है, नैनीताल की सायरा बानो का, जिनके पति ने ख़त में तीन बार तलाक तलाक तलाक लिखकर उनसे अपने रिश्ते ख़त्म कर लिए. सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उक्त सभी मामले धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हैं, जिन्होंने देश में महिला विमर्श को एक बार फिर बहस के केंद्र में खड़ा कर दिया है.

धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश का मसला

पिछले वर्ष 29 नवंबर को शनि शिंगणापुर मंदिर में भूमाता ब्रिगेड की एक महिला ने शनिदेव के चबूतरे पर तेल चढ़ाकर पूजा की और मंदिर की 400 वर्ष पुरानी परंपरा तोड़ दी. वर्षों पुरानी परंपरा टूटने पर हंगामा होना अप्रत्याशित नहीं था. इस सिलसिले में सबसे पहली गाज मंदिर के सात सुरक्षाकर्मियों पर गिरी, जिन्हें मंदिर प्रबंधन ने निलंबित कर दिया. बाद में पंचायत बुलाकर मंदिर परिसर का दुग्धाभिषेक (दूध से शुद्धिकरण) और घटना के विरोध में बंद का आयोजन किया गया. दरअसल, इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की यह पहली कोशिश नहीं थी. आज से पंद्रह वर्ष पहले भी महिलाओं ने मंदिर में प्रवेश के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की थी. उक्त मुहिम में फिल्म अभिनेता एवं रंगकर्मी श्रीराम लागू भी जुड़े थे. इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मौक़े पर तृप्ति देसाई की अगुवाई में भूमाता ब्रिगेड ने 400 महिला समर्थकों के साथ पूजा करने का फ़ैसला किया था. मंदिर में प्रवेश के प्रयास में तृप्ति एवं उनके समर्थकों को कई बार हिरासत में लिया गया. बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट ने कुछ शर्तों के साथ मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी.

महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी का दूसरा मामला केरल के सबरीमाला मंदिर का है, जहां मासिक धर्म की आयु (10 से 50 वर्ष) की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है. मंदिर की मान्यता है कि चूंकि भगवान अय्यप्पा कुंवारे थे, इसलिए उनके मंदिर में मासिक धर्म की उम्र वाली महिलाओं का प्रवेश वर्जित है. लेकिन, विभिन्न महिला संगठन इस मंदिर में प्रवेश के अधिकार को लेकर अपनी आवाज़ बराबर उठाते रहे हैं. ग़ौरतलब है कि सबरीमाला मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश का विवाद बहुत पुराना है. इस सिलसिले में एक दिलचस्प मामला कन्नड़ अभिनेत्री जयमाला का है. जयमाला ने वर्ष 2006 में दावा किया था कि उन्होंने वर्ष 1986 में भगवान अय्यप्पा की मूर्ति के पैर छुए थे. इसके बाद पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ स्थानीय अदालत में चार्जशीट दाख़िल की थी. हालांकि बाद में अदालत ने मामले को ख़ारिज कर दिया था. सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर नया मोड़ तब आया, जब पिछले वर्ष नवंबर में त्रावणकोर देवाश्वम बोर्ड के नए अध्यक्ष पेरियार गोपालकृष्णन ने एक आपत्तिजनक बयान दिया. उन्होंने कथित तौर पर कहा कि महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति तब दी जाएगी, जब उनकी शुद्धता की जांच करने वाली मशीन का आविष्कार हो जाएगा. हालांकि, बाद में उन्होंने ऐसा बयान दिए जाने से इंकार कर दिया. लेकिन, इसके बाद महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर व्याप्त भ्रांतियों एवं अंधविश्वास के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया और सड़कों पर ब्लीड टू हैप्पी मुहिम शुरू हो गई. इस मुहिम को हर तरफ़ से समर्थन मिला. ब्लीड टू हैप्पी मुहिम से जुड़ी छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पूछा कि मासिक धर्म जैसे स्वास्थ्य एवं वैज्ञानिक कारणों के चलते किसी के साथ भेदभाव कैसे रखा जा सकता है और क्यों उन्हें पूजा करने से रोका जा सकता है? मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कहा कि अदालत अपना फ़ैसला संविधान के प्रावधानों के मुताबिक देगी, न कि मान्यताओं के आधार पर. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म में महिला और पुरुष अलग–अलग धार्मिक समूह कैसे हो सकते हैं?

मुस्लिम महिला संगठनों ने भी अपने अधिकारों को लेकर आवाज़ उठानी शुरू कर दी है. भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुंबई के मशहूर हाजी अली की मजार तक महिलाओं के जाने पर लगी पाबंदी को चुनौती दी है. इससे पहले महिलाओं ने मजार में प्रवेश को लेकर प्रदर्शन भी किया था. अदालत में अपना पक्ष रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को असंवैधानिक बताया है. बहरहाल, हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर कोई फ़ैसला सुनाने से पहले वह केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार करेगा. धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर एक सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि कोई मंदिर या धर्मस्थल अपनी परंपरा के अनुरूप किसी को प्रवेश की इजाज़त नहीं देता, तो फिर वैसे धर्मस्थल पर जाने की ज़रूरत क्या है? दरअसल, यह मामला जितना धार्मिक है, उतना ही सांकेतिक भी, क्योंकि जब देश का संविधान लिंग, धर्म, जाति एवं भाषा के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करता, तो फिर सवाल उठता है कि आधी आबादी के साथ लिंग के आधार पर यह भेदभाव क्यों? साथ ही सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी भी काफी अहम है कि हिंदू धर्म में महिला एवं पुरुष अलग–अलग धार्मिक समूह कैसे हो सकते हैं? जब पुरुषों को पूजा करने की अनुमति है, तो महिलाओं को क्यों नहीं? इस संबंध में यह सवाल उठाया जा सकता है कि जो महिलाएं धार्मिक स्थलों में प्रवेश की वकालत कर रही हैं, उन्हें धर्म से कम ही लेना–देना है. लेकिन, इस दलील में कोई दम नहीं है, क्योंकि यदि देश का संविधान समानता पर आधारित समाज के निर्माण की बात करता है, तो इस तरह का भेदभाव मिटाना होगा. कहते हैं कि मांगे बिना तो भगवान भी नहीं देता, तो फिर इंसानों की कौन कहे! अगर देश में सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के ख़िलाफ़ किसी ने आवाज़ न उठाई होती, तो परंपरा के नाम पर ये आज भी जारी रहतीं. दरअसल, अहम यह नहीं है कि कौन आवाज़ उठा रहा है, बल्कि अहम यह है कि क्या आवाज़ उठा रहा है.

तीन तलाक और मुस्लिम महिलाओं की समस्याएं

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष, क़ानूनविद् एवं मुस्लिम पर्सनल लॉ मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर ताहिर महमूद कहते हैं कि बाई ताहिरा, फ़ज़लून बी, जोहरा खातून, शाहबानो, शमीम आरा, इकबाल बानो, खातून निसा, शबाना बानो एवं शमीम फारूकी आदि विकीपीडिया द्वारा उठाए गए मुस्लिम नाम नहीं हैं, बल्कि ये मुस्लिम क़ानून के तीन तलाक के प्रावधान के शिकार हैं, जिन्होंने अपने गुज़ारे की मामूली रकम के लिए 1976 से सुप्रीम कोर्ट तक क़ानूनी लड़ाइयां लड़ी हैं. उनकी दु:खभरी कहानियां क़ानून की रिपोर्टों में दफन हैं. तीन तलाक का ताज़ा मामला नैनीताल की सायरा बानो से जुड़ा है. इलाहाबाद के रिजवान ने अपनी पत्नी सायरा बानो के नाम एक ख़त में तीन बार तलाक लिखकर अपने बीच के पति–पत्नी के रिश्ते को ख़त्म करने की घोषणा कर दी. सायरा खामोश नहीं बैठीं और वह सुप्रीम कोर्ट तक गईं, लेकिन एक फ़र्क़ के साथ. उन्होंने अपने पति से रखरखाव की मांग के बजाय तीन तलाक के प्रावधान को चुनौती देने का फ़ैसला किया. आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तीन तलाक का प्रावधान ख़त्म करने के किसी भी प्रस्ताव का विरोध करता है.

दरअसल, कुरान के मुताबिक, अल्लाह हलाल चीज़ों में तलाक को सबसे ज़्यादा नापसंद करता है. प्रोफेसर ताहिर महमूद का मानना है कि निकाह की तरह तलाक केवल शब्दों के उच्चारण मात्र से शादी ख़त्म नहीं करता, सही प्रक्रिया अपना कर ही शादी ख़त्म की जा सकती है. बदकिस्मती से इस्लामिक क़ानून की पारंपरिक व्याख्या ने तीन तलाक का प्रावधान स्थापित कर दिया, जो वास्तविक इस्लामिक क़ानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और जिसे तलाक़–उल–बिदत कहते हैं. तीन तलाक गुनाह है, लेकिन लागू है. इस मसले पर चौथी दुनिया के पिछले अंक में यूसुफ अंसारी ने तफ्सीली निगाह डाली है. लेकिन, मसला यहां यह है कि यदि तलाक अल्लाह के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा काम है, तो फिर यह बिदत अपनाए रखने पर इतना ज़ोर क्यों? ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं यह मांग कर रही हैं, वे कोई अनोखी बात कर रही हैं. कई मुस्लिम देशों में तीन तलाक का प्रावधान ख़त्म कर दिया गया है. ऐसे देशों में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हैं.

तुर्की और साइप्रस ने सेक्युलर सिविल क़ानून अपना रखा है. ट्यूनीशिया, अलजीरिया और मलेशिया अदालत से बाहर दिए हुए तलाक को मान्यता नहीं देते. ईरान में शिया क़ानून तीन तलाक को क़ानूनी हैसियत नहीं देता. मिस्र पहला देश था, जिसने तीन तलाक का प्रावधान 1929 में ख़त्म किया था. सूडान दूसरा देश था, जिसने 1935 में यह प्रावधान ख़त्म किया. बाद में इराक, जॉर्डन, सीरिया और इंडोनेशिया ने भी तीन तलाक का प्रावधान खत्म कर दिया. ट्यूनीशिया ने एक क़दम आगे जाते हुए 1956 में एक क़ानून बनाया, जिसके तहत अदालत के बाहर दिए गए तलाक को ख़ारिज माना गया. पाकिस्तान ने भी 1956 में एक अध्यादेश के ज़रिये तीन तलाक का निज़ाम ख़त्म कर दिया, जिसे बांग्लादेश ने बाद में भी कायम रखा.

तीन तलाक से जुड़ा एक मसला है, जिसे हलाला कहते हैं. यानी अगर पति तलाक दे दे और बाद में उसे ख्याल आए कि उसने जल्दबाजी में तलाक दिया है और तलाकशुदा पत्नी से फिर निकाह कर लेना चाहिए, तो वह हलाला के विकृत विवेचन का इस्तेमाल करता है. हलाला के तहत होता यह है कि पूर्व पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ निकाह करे और वे दोनों पति–पत्नी की तरह रह लें और फिर दूसरा पति उसे तलाक दे दे, तो पहले पति से निकाह जायज़ हो जाता है. प्रोफेसर ताहिर महमूद के अनुसार, भारत में जिस हलाला का चलन है, वह देश के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के विपरीत है. संविधान की धारा 51 महिलाओं की गरिमा को अपमानित करने वाली प्रथाओं के त्याग की बात करती है.

अब सवाल उठता है कि जब इतने सारे मुस्लिम देशों ने अपने सिविल क़ानून से तीन तलाक का प्रावधान ख़त्म कर दिया, तो फिर भारत में इसे जारी रखने का क्या औचित्य है? ऐसा नहीं है कि तलाक़ के दूसरे तरीके, जिसमें तीन तलाक को तीन अलग–अलग समय दिया जाता है, से इस्लामिक क़ानून की ख़िलाफ़वर्ज़ी होगी. दूसरा यह कि जब अल्लाह के नज़दीक तलाक़ सबसे बुरी चीज़ है, तो फिर इसके इस्तेमाल का जो बेहतर तरीका है, उसे अपनाने में क्या हर्ज है? ऑल इंडिया मुस्लिम वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर कहती हैं कि इस मामले में इस्लाम का रुख सीधा है, बिल्कुल दो और दो चार की तरह. आप अगर–मगर में उलझाएं नहीं. अल्लाह रहीम और करीम है. वह अपने बंदों की छोटी–छोटी गलतियां माफ़ कर देता है, तो उलेमा को पति–पत्नी के छोटे–छोटे झगड़े सुलटाने के लिए आगे आना चाहिए. जिस तरह कुरान में तलाक का प्रावधान है, आप उसे मानें, उसे उलझाएं नहीं. एक शख्स चिट्ठी के ज़रिये तलाक लिखकर किसी के साथ अपने रिश्ते को कैसे ख़त्म कर सकता है? सुलह की कुछ न कुछ गुंजाइश तो होनी चाहिए. भारत में महिलाओं का एक बड़ा तबका तीन तलाक के प्रावधान के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने लगा है. मुस्लिम महिलाओं से संबंधित दूसरे मसले यानी विरासत का मामला भी बहस का मुद्दा बनने लगा है. दरअसल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस मामले में दूसरे मुस्लिम देशों के सिविल क़ानून का अध्ययन करना चाहिए. ■

सायरा को शाहबानो नहीं बनने देंगे : शाइस्ता अंबर

तीन तलाक और सायरा बानो मसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर से चौथी दुनिया की एक्सक्लूसिव बातचीत के मुख्य अंश...

तीन तलाक के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड का रुख क्या है?

हमारा रुख बिल्कुल सीधा है कि इस मामले में इस्लाम एकदम सीधा–सादा है. दो और दो चार है. आप उसे अगर–मगर में न उलझाएं. पति–पत्नी की आपसी भूल सुधारने और उनके बीच सुलह कराने के लिए उलेमा को आगे आना चाहिए और कुरान में तलाक की जो प्रक्रिया है, उसका पालन होना चाहिए. एक औरत, जिसने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा पति के साथ गुज़ारा हो, आप उसे महज एक चिट्ठी के ज़रिये अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे! क्या आप उससे बात नहीं कर सकते? लोगों को गवाह नहीं बना सकते? आप गवाह बनाइए, आप अपना मामला दारुल क़ज़ा में या मौलाना के सामने रखिए. मौलाना की नीयत सुलह कराने की होनी चाहिए. कुरान सूरा तलाक में, सूरा निसा में बार–बार कहता है कि अल्लाह से डरने वाला बनो, सुलह करने की नीयत करो और गवाहों को बनाओ. सायरा के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. वह लड़की अगर मौलाना से पूछती है कि क्या यह तलाक सही है, तो मौलाना कह देते हैं कि हां, सही है. क्या यह सही है कि तलाक को एकतरफ़ा सुनकर कह दिया जाए.

क्या वजह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बार में तीन तलाक को बरक़रार रखना चाहता है?

अगर किसी आदमी ने नींद में, नशे में, ईमेल द्वारा, एसएमएस द्वारा, गुस्से में या भूल से एक बार भी तलाक बोल दिया, तो भी उसे तलाक मान लिया जाता है. अब यह भी पड़ताल नहीं करते कि वह औरत पाक है या नहीं, गर्भवती है या नहीं. इन सारी प्रक्रियाओं से सायरा बानो नहीं गुज़री है. अब अगर सायरा बानो अपनी फरियाद लेकर अदालत गई है, तो पर्सनल लॉ बोर्ड पार्टी बनकर अदालत से कह रहा है कि उसकी याचिका ख़ारिज होनी चाहिए. क्योंकि, आप नहीं चाहते कि पर्सनल लॉ बोर्ड में किसी का हस्तक्षेप हो. महिला पर्सनल लॉ बोर्ड भी कहता है कि पर्सनल लॉ बोर्ड में किसी का हस्तक्षेप न हो. कॉमन सिविल कोड और यूनिफार्म सिविल कोड को वह कुबूल नहीं करेगा. बजाय सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनने के पर्सनल लॉ बोर्ड को चाहिए था कि सायरा बानो और उसके पति से संपर्क साधा जाता और उन्हें दारुल क़ज़ा में बुलाया जाता. सायरा बानो के मामले में आप अदालत से कह रहे हैं कि वह हस्तक्षेप न करे और अपनी तरफ़ से भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. तो फिर वह मजलूम औरत जाए तो कहां जाए? आप उसके लिए दोनों दरवाज़े बंद कर रहे हैं.

सायरा बानो का जो मामला अदालत में चल रहा है, उसमें आप लोग (वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड) किस तरह शामिल होंगे?

मेरी टीम तैयार हो रही है. फ़िलहाल इस पर मैं ज़्यादा रौशनी नहीं डालूंगी. एक टीवी बहस में सायरा बानो से मेरी बात हुई. मैंने साफ़ कहा कि उसे दूसरा शाहबानो नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि उस समय कोई महिला पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं था, जो उसके साथ खड़ा हो जाता. ■

feedback@chauthiduniya.com

वजूद ख़त्म हो जाएगा आदिम जनजातियों का

झारखंड सरकार पहाड़िया जनजाति के विकास के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन गोड्डा जिले में ये योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ रही हैं. नतीजतन, जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड में रहने वाली पहाड़िया जनजाति के बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं. पहाड़िया जनजाति के नंग-धड़ंग बच्चों को देखकर तो यही लगता है कि सरकार के कुपोषण मुक्त झारखंड के सपनों पर पानी फिरता जा रहा है. आज पहाड़िया जनजाति के अधिकांश बच्चे कुपोषण का शिकार हैं. आदिकाल से ही कंद-मूल खाकर इनकी जिंदगी कटती है. आज तक इन्हें न तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो पाई हैं और न ही शिक्षा.

कुमार कृष्णन

झारखंड का गठन हुए एक अरसा बीत गया. इस दौरान काफी कुछ बदला लेकिन जिन आदिवासियों के नाम पर अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ उनकी तस्वीर नहीं बदली. सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही, लूट और देशज अवधारणा से दूर होने की वजह से आदिम जनजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं. राज्य में सबसे ज्यादा मृत्युदर इनकी है. इनकी जनसंख्या बढ़ने के बजाए घट रही है. आदिवासियों की मृत्युदर अधिक होने का कारण इनमें व्याप्त कुपोषण है. यह और अधिक चिंतनीय तब हो जाता है जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं.

आदिम जनजातियों की जनसंख्या घटने की पुष्टि ये आंकड़े भी करते हैं. 2001 में इन जनजातियों की आबादी 2,06,000 लाख थी, जो 2011 में घटकर 1,72,425 रह गई है. जिन आदिम जनजातियों की आबादी घट रही है उसमें माल पहाड़िया, पहाड़िया सबर, सौरिया पहाड़िया असुर, बिरहोर, बिरिजिया, कोरवा, और खड़िया, जनजातियां प्रमुख हैं. सौरिया पहाड़िया और सावर आदिम जनजाति विलुप्ति की कगार पर है. अंग्रेजों के ख़िलाफ लड़ने वाली इस जनजाति का अस्तित्व खतरे में है. पिछले एक दशक में 14,899 सौरिया पहाड़िया और 261 सावर गायब हो गए हैं. यानी दोनों की आबादी में क्रमश: 24.38 और 2.69 फीसदी की कमी आई है. वहीं इसी अवधि में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आदिम जनजातियों की सुरक्षा और संरक्षण पर 470 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च की जा चुकी है.

भारतीय इतिहास में महान योद्धा तिलका मांझी का नाम अंग्रजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंकने वाले सबसे पहले व्यक्ति के रूप में दर्ज है. तिलका मांझी ने सन 1784 में भागलपुर के क्रूर अंग्रेज कलेक्टर आगस्टस क्लीवलैंड की हत्या कर अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थीं. इसके बाद पहाड़िया लड़ाकों ने पहाड़िया बटालियन का गठन कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे. सैकड़ों वर्ष पूर्व पहाड़ों की कंदराओं में रहने वाले पहाड़िया जनजाति के लोगों की आज भी वही स्थिति है.

झारखंड सरकार पहाड़िया जनजाति के विकास के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन गोड्डा जिले में ये योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ रही हैं. नतीजतन, जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड में रहने वाली पहाड़िया जनजाति के बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं. पहाड़िया जनजाति के नंग-धड़ंग बच्चों को देखकर तो यही लगता है कि सरकार के कुपोषण मुक्त झारखंड के सपनों पर पानी फिरता जा रहा है. आज पहाड़िया जनजाति के अधिकांश बच्चे कुपोषण का शिकार हैं. आदिकाल से ही कंद-मूल खाकर इनकी जिंदगी कटती है. आज तक इन्हें न तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो पाई हैं और न ही शिक्षा. सुरेंद्र पहाड़िया और चांदी पहाड़िन का कहना है कि सरकार की किसी भी योजना का समुचित लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है. राज्य सरकार विलुप्त प्राय: पहाड़िया जनजाति को संरक्षित करने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, बावजूद इसके इनके बच्चों का कुपोषित होना सरकारी कारिन्दों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है. वैसे जंगली इलाकों के बारे में लोगों का मानना है कि जिन इलाकों में आज भी भरपूर जंगल हैं, वहां भूख की वजह से कोई नहीं मर सकता. लेकिन विभागीय उदासीनता, कर्मचारियों की मिलीभगत व पहाड़िया जनजाति में जागरूकता की कमी के कारण आज पूरे संथाल परगना में वन माफियाओं द्वारा जंगलों की अवैध कटाई जारी है, इस वजह से न सिर्फ पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है बल्कि लोग बीमारी और भुखमरी केशिकार हो रहे हैं तथा दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले ईंधन और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं.

गोड्डा की सुंदर पहाड़ी तो एक उदाहरण है. यह स्थिति पूरे संथाल परगना की है. संथाल परगना के पांच जिलों दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और देवघर में सौरिया, पहाड़िया जनजाति के लोग रहते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से सौरिया पहाड़िया जनजाति के लोगों की स्थिति काफी दयनीय है. इस जनजाति के तकरीबन 80 फीसदी लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं. पूरे संथाल परगना लिट्टीपाड़ा प्रखंड में सर्वाधिक 157 पहाड़िया गांव हैं जिनमें 7 हजार परिवारों के लगभग 27 हजार पहाड़िया लोग रहते हैं. आज भी इस जनजाति के लोगों को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं है. जंगली खाना, जंगली दवा, झरने और नाले का पानी पीने को विवश इस जनजाति के बच्चे कुपोषित ही पैदा होते हैं. ये बच्चे जब तक जिंदा रहते हैं जीवन के लिए संघर्ष करते रहते हैं. सड़क के अभाव में पगडंडियों के सहारे यदि ये किसी तरह इलाज के लिए पहाड़ से उतर आएं तो झोला छाप डॉक्टर भी इन्हें लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. आज़ादी के लगभग 7 दशक, बिहार से अलग होने के डेढ़ दशक बाद भी इन पहाड़िया आदिवासियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है. आज भी लिट्टीपाड़ा शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में सूबे का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र बना हुआ है. इन लोगों के भरोसे क्षेत्र के जन-प्रतिनिधियों की तक़दीर तो बदल गई लेकिन इनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है.

स्वास्थ्य सेवाओं का आलम यह है कि दुमका जिले के काठीकुंड में पिछले वर्ष इस समुदाय के एक मासूम बच्चे की सही इलाज के अभाव में मौत हो गई थी. दिमागी बुखार से पीड़ित दो साल का यह मासूम(सुकलाल देहरी) काठीकुंड प्रखंड के पोखरिया गांव का रहने वाला था. पिता राम देहरी केअनुसार उसका गांव प्रखंड मुख्यालय से लगभग 16 किमी की दूरी पर है. उनके बेटे को बुखार था, उसका इलाज उन्होंने गांव के ही एक झोलाछाप डॉक्टर से कराया. जब तबीयत नहीं सुधरी तो विकलांग पिता राम देहरी और मां शांति देवी उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. वर्तमान स्थिति यह है इन लोगों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए तीन से दस किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है. जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उन्हें कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए तय करनी पड़ती है. लंबी दूरी के कारण वे स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर इलाज नहीं करा पाते हैं.

गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड केपहाड़ों पर निवास करने वाले पहाड़िया जनजाति के लोगों के आवास का सपना अब तक साकार नहीं हो पाया है. प्रखंड के डहुबेड़ा गांव में 40 घर पहाड़िया जनजाति के लोगों के हैं. चार वर्ष पहले इन लोगों के लिए बिरसा आवास योजना के अंतर्गत घरों का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हो सका है. नतीजतन ये लोग टूटी फूटी घासफूस की झोपड़ियों में मौसम की मार झेल रहे हैं. स्थानीय निवासी चांदी पहाड़िन की मानें तो आवास के अभाव में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. यही हाल जामताड़ा का है. जामताड़ा में भी इस योजना के तहत संरक्षित जाति को लोगों के लिए आवास बन रहे हैं, लेकिन यह योजना अधिकारियों के मनमाने रवैये के कारण अधर में लटक गई है. यह योजना सरकारी बाबुओं के लिए कामधेनु गाय साबित हो रही है. स्थानीय निवासी पतास मालतो कहते हैं कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहाड़िया समुदाय को नहीं मिल पा रहा है. पहाड़ी क्षेत्र में पत्थर उत्खनन एवं क्रशर के प्रदूषण से प्रभावित या बीमार पड़ रहे पहाड़िया समुदाय के लोगों की ओर किसी का ध्यान नहीं है. सरकारी घोषणाओं और योजनाओं की हक़ीकत बयां करते हुए झामुमो विधायक कुणाल षड़ंगी कहते हैं कि राज्य में आदिम जनजाति के लोगों की जनसंख्या 80 हजार के करीब है. लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ इन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने घोषणा की थी कि दसवीं पास आदिम जनजाति के लोगों को सीधी नियुक्ति की जाएगी लेकिन आज तक किसी भी आदिवासी को नौकरी नहीं मिली.

संथाल परगना क्षेत्र में पानी की स्थिति देखें तो यहां गंगा, बांसलोइ, ब्राह्मणी, अजय और मयूराक्षी जैसी कई बड़ी नदियां हैं. इसके अलावा यहां कई जलप्रपात भी हैं. पहले यहां के प्रत्येक गांव में एक-दो बड़े जलस्रोत हुआ करते थे, जिनमें साल भर के लिए आवश्यक पानी उपलब्ध रहता था. गांव के बड़े- बुजुर्ग और जानकार बताते हैं कि बरसात के दिनों में बरसने वाला पानी साल वृक्ष की जड़ों के माध्यम से भूतल में जमा रहता था. बरसात के बाद यह जल धीरे-धीरे सोता बनकर बहता रहता था. जिससे गांव वालों को नदियों एवं जल-स्रोतों से पीने एवं खेतों को सींचने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता था. गांव पहाड़, टीले या घाटी में बसा हो यहां के लोगों को कभी जल संकट का सामना नहीं करना पड़ता था. परंतु आज जंगलों की कटाई के कारण नदियों में पानी टिकना मुश्किल हो गया है साथ ही सभी जलस्रोत भी धीरे-धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं. इस वजह से एक तरफ तो खेती के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है वहीं दूसरी तरफ पेयजल का संकट गहराता जा रहा है. आज पेयजल संकट का जो भयावह रूप इस क्षेत्र में देखने को मिलता है वैसा पहले कभी नहीं था. पहाड़ या ऊंची जगहों पर रहने वाले आदिवासियों को तो सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. आज से कई वर्ष पहले जल है, जान है योजना के तहत इस इलाकेमें हजारों कुएं खोदे गए. साथ ही चापाकल भी लगाए गए, आज भी लगाए जा रहे हैं लेकिन अफसोस उसमें से अधिकांश चापाकल आज खराब पड़े हैं और कुंए का पानी पाताल चला गया है. इन दिनों जल स्वच्छता अभियान के तहत पेयजल संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा प्रखंड स्तर पर शिकायत पेटियां लगाई गई हैं, लेकिन शिकायतकर्ताओं का मानना है कि 80 प्रतिशत शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं होती.

आदिवासियों की एक आदम प्रजाति खड़िया है, इनका एक बड़ा तबका अब भी सिमडेगा, गुमला, बोकारो व रांची के पहाड़ों में रहता है. पहाड़ों के ऊपर ही ये लोग समतल जगह बनाकर बांस और पत्तों से बनाए घरों में रहते हैं. दो दशक पहले भी ये सर्वहारा थे और अब भी हैं, फर्क़ सिर्फ इतना है कि इनकी आधी आबादी विलुप्त हो चुकी है. असीरियन जनजाति के लोग घने जंगलों में रहते हैं, वहीं कोरवा, पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया लोगों की स्थिति भी दयनीय है. इनमें अंधविश्वास बहुत ज़्यादा व्याप्त है. ये अपने आप को जादुई शक्ति से संपन्न मानते हैं और प्रेत बाधा दूर करने का दावा करते हैं. ये सबई घास से रस्सी बनाकर अपना पेट पालते हैं. सभी आदिम जनजातियों की स्थिति तकरीबन एक जैसी है.

आदिम जनजातियों को बीमारी और अकाल मौत से बचाने के लिए हो रहे प्रयासों के तहत राज्य सरकार ने उनके रिहायशी इलाकों मेंस्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी फैसला किया है. इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. इन स्वास्थ्य केंद्रों में एनएमएम, एक पैरा मेडिकल कर्मी और एक सहिया होंगे. सरकार की सोच है कि राज्य के आदिम जनजाति के लोगों का समय रहते इलाज हो सके. साथ ही इनकी घटती आबादी पर लगाम लगाई जा सके. बगोदर, कोडरमा और हजारीबाग में, चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में बिरहोर जनजाति के लोगों की अकाल मौत की खबरें आती रहती हैं. साल 2014 में लातेहार में 11 बीमार बच्चों की मौत हुई थी, वहीं साल 2015 में 10 बच्चों की अज्ञात बीमारी से मौत हुई थी. हालांकि राज्य सरकार ने इस बार बजट में आदिम जनजाति विकास प्राधिकार के गठन हेतु प्रावधान किया है. साथ ही आदिम जनजातियों हेतु बिरसा आवास निर्माण योजना का प्रावधान और मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आदिम जनजाति के सभी परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न निःशुल्क देने का प्रावधान किया है. इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब क्रियान्वयन ईमानदारी से हो, वरना इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा.■

आदिम जनजातियों को बीमारी और अकाल मौत से बचाने के लिए हो रहे प्रयासों के तहत राज्य सरकार ने उनके रिहायशी इलाकों मेंस्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी फैसला किया है. इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. इन स्वास्थ्य केंद्रों में एनएमएम, एक पैरा मेडिकल कर्मी और एक सहिया होंगे. सरकार की सोच है कि राज्य के आदिम जनजाति के लोगों का समय रहते इलाज हो सके. साथ ही इनकी घटती आबादी पर लगाम लगाई जा सके.

feedback@chauthiduniya.com

पूर्वोत्तर भारत

विकास की राह में बंदूक

एस. बिजेन सिंह

मोदी सरकार भले ही पूर्वोत्तर भारत को विकास की दौड़ में शामिल करवाने की कोशिश कर रही हो, विकास की बहुत सारी योजनाएं शुरू कर रही हो, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां के चरमपंथी गुटों को विकास की यह राह रास नहीं आ रही है. इसलिए वे समय-समय पर सरकार का विरोध करते रहते हैं. गत 13 अप्रैल को मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के नुंगबा सब-डिवीजन के लेंगलोंग में मणिपुरी नगा चरमपंथी संगठन जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) और भारतीय सेना के बीच हुई मुठभेड़ में मेजर अमित देसवाल शहीद हो गए. अमित देसवाल हरियाणा के झज्जर के रहने वाले थे. वह इंफाल स्थित सेना की 21वीं पैरा (स्पेशल फोर्स) में पदस्थ थे. पिछले दिनों ख़बर आई कि तमेंगलोंग जिले के नुंगबा सब डिवीजन के लेंगलोंग में हथियारबंद चरमपंथी गुट इकट्ठा हो रहे हैं. इसी सिलसिले में मेजर अमित देसवाल के नेतृत्व में 21वीं पैरा की एक टीम को लेंगलोंग भेजा गया. यह टीम लेंगलोंग पहुंचने ही वाली थी लेकिन वहां पहले से छिपे अत्याधुनिक हथियारों से लैस चरमपंथियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. इस मुठभेड़ में मेजर देसवाल को गोलियां लगीं और वह घटना स्थल पर ही शहीद हो गए. इस घटना में मेजर देसवाल के अलावा अन्य दो लोगों की भी मौत हो गई. जिनमें से एक स्थानीय व्यक्ति और दूसरा चरमपंथी गुट का सदस्य था.

दूसरी घटना है 14 अप्रैल की, जब ईस्ट इंफाल के मिनुथोंग स्थित असम रायफल्स के ट्रांजिट कैंप में रात में बम फेंका गया. इस घटना में 32 वर्षीय जवान गोकुलचंद यादव शहीद हो गया और तीन जवान घायल हुए. इस घटना की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) की सेना एमपीए ने ली. राजस्थान के सीकर जिले के नीम का थाना सालावली गांव के रहने वाले गोकुल चंद असम राइफल्स में तैनात थे. गोकुल होली की छुट्टियां बिताकर अपनी यूनिट में वापस लौटे थे. इससे पहले, 31 मार्च की रात लिलोंग स्थित 40 असम रायफल्स के कैंप में बम फेंका गया था. इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन इस घटना की जिम्मेदारी पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलैपाक (प्रीपाक) ने ली थी.

मणिपुर के चरमपंथी संगठनों का मानना है कि मणिपुर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा है, उसे जबरदस्ती भारत में शामिल किया गया है. मणिपुर मर्जर एग्रिमेंट–1949 के तहत मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह से बंद कमरे बंदूक की नोक पर हस्ताक्षर कराए गए थे. इसके विरोध में तब से लेकर आज तक मणिपुर में सशस्त्र आंदोलन चल रहा है. इन लोगों का मानना है कि उन्हें भारत से आजादी नहीं मिलेगी, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. इसी वजह से समय-समय पर चरमपंथी गुट भारतीय सेना या अर्ध सैन्य बलों के जवानों और उनके कैंप में हमला करके अपना विरोध दर्ज कराते रहते हैं. ऐसे हमलों में मेजर देसवाल जैसे कई जवान शहीद हो चुके हैं.

मणिपुर सहित पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों में आंदोलन कई चरमपंथी सशस्त्र गुट सक्रिय हैं. पूर्वोत्तर भारत के राज्य सिलीगुड़ी गलियारे या चिकन्स नेक से शेष भारत से जुड़े हैं. यहां के कई चरमपंथी गुट समय-समय पर अलग राज्य की मांग करते रहे हैं है, कुछ गुटों को क्षेत्रीय स्वायत्त चाहिए तो कुछ अतिवादी समूहों को पूर्ण स्वतंत्रता. पूर्वोत्तर भारत के राज्यों स्थानीय आदिवासी समुदायों और बाहरी लोगों के बीच तनाव और संघर्ष काफी पहले से चला आ रहा है. हालांकि साल 2013 में इस संघर्ष में थोड़ी कमी देखने को मिली थी लेकिन साल 2014 में यह तनाव एक बार फिर से बढ़ गया और आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा बाहरी लोगों पर हमले किए जाने की घटनाओं में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई. इस तरह के हमले असम, मणिपुर, नगालैंड और त्रिपुरा में सबसे ज्यादा हुए. पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे कम चरमपंथी गुट अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम में हैं. मिजोरम में तो चरमपंथी न के बराबर हैं. इन दोनों राज्यों में स्वाभाविक तौर पर चरमपंथी घटनाएं भी बेहद कम होती हैं.

2014 में हुए लोकसभा चुनाव में पूर्वोत्तर राज्यों में 80 फीसदी मतदान हुआ था. इसके बाद विभिन्न राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा कि मतदान प्रतिशत यह बताता है कि पूर्वोत्तर भारत के लोगों का भारतीय लोकतंत्र में विश्वास बढ़ा है. लेकिन 2015 में एनएससीएन (के) के प्रमुख एसएस खपलांग, उल्फा प्रमुख डॉ अभिजीत असोम, केएलओ के प्रमुख जीवन सिंघा और एनडीएफबी के प्रमुख बी साउरायगवरा ने संयुक्त रूप से यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेसी (यूएनएलएफडब्ल्यू) के गठन की घोषणा की. यह संगठन पूर्वोत्तर भारत की वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया के रूप में मान्यता चाहता है. इन चरमपंथी गुटों के आपसे में मिलने और एक नए संगठन का गठन करने की वजह से पूर्वोत्तर भारत में अशांति का माहौल बन गया. नए संगठन के गठन के बाद नए संगठन ने मणिपुर के चांदेल की घटना को अंजाम दिया गया था जिसमें भारतीय सेना के 18 सैनिक शहीद हुए थे. इसके बाद भारतीय सेना ने म्यांमार में इनके कैंप पर जवाबी हमला भी किया था.

आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट–1958 (अफसपा) पूर्वोत्तर भारत के अशांत राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नगालैंड में लागू है. पिछले साल त्रिपुरा से इस कानून को हटाया गया था. यह कानून अशांत क्षेत्रों में सेना को विशेषाधिकार देता है ताकि चरमपंथी संगठनों के खिलाफ प्रभावशाली तरीके से कार्रवाई की जा सके. अफसपा के लागू होने के बाद पूरे पूर्वोत्तर भारत में फर्जी मुठभेड़, बलात्कार, लूट एवं हत्या जैसी घटनाओं की बाढ़ आ गई. जब 1958 में अफसपा बना था तब यह कानून राज्य सरकार के अधीन था, लेकिन साल 1972 में इस कानून में हुए संशोधन के बाद इसे केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया. संशोधन के मुताबिक देश के किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र (डिस्टर्ब एरिया) घोषित कर वहां अफसपा लागू किया जा सकता है. इस कानून के खिलाफ कई लोग समय-समय पर विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं. मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से विख्यात इरोम शर्मिला पिछले 15 वर्षों से इस कानून को खत्म करने के खिलाफ आमरण अनशन कर रही हैं. ग़ौरतलब है कि जीवन रेड्डी समिति ने भी सरकार को यह संकेत दिया था कि यह क़ानून दोषपूर्ण है और इसमें संशोधन की ज़रूरत है. लेकिन उपरोक्त घटनाओं में कमी होने के बजाए इनमें इज़ाफा हो रहा है ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि पूर्वोत्तर राज्यों से अफसपा हटाना कितना जायज होगा. हालांकि, लोग अफसपा के खिलाफ तो हैं, लेकिन चरमपंथी संगठनों द्वारा लगातार पूर्वोत्तर सेना और अर्ध-सैन्य बलों के खिलाफ हो रहे हमले को देखकर केंद्र सरकार द्वारा अफसपा लगाने का निर्णय तार्किक लगता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत मणिपुर की 84 किमी लंबी जिरिबाम–तुपुल रेलवे लाइन का काम भी इन चरमपंथी संगठनों के विरोध की वजह से निर्धारित समय से पीछे चल रहा है. इस रेलवे लाइन के निर्माण में छह बड़े पुल, 112 छोटे पुल, तीन सड़क ओवरब्रिज का बनने हैं. पहले चरण में 39,401 मीटर लंबी 34 सुरंगें बनानी हैं. इस कार्य को साल 2016 के अंत तक पूर्ण होना था. केंद्र सरकार इस नीति के तहत दक्षिण–पूर्व और पूर्व–एशिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का कार्य कर रहा है. नगा चरमपंथी गुट जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) ने कई सप्ताह तक निर्माण कार्य को बाधित रखा. साथ ही इस रेल योजना के प्रोजेक्ट मैनेजर का इस साल जनवरी में अपहरण कर लिया गया था. इसके अलावा भी अन्य कई संगठन हैं जो इस योजना के कार्य को बाधित कर रहे हैं. राज्य सरकार भी सुरक्षा के नाम पर कुछ कर नहीं पा रही है. जेडयूएफ के पीछे नगा चरमपंथी गुट एनएससीएन (आईएम) मदद कर रहा है. एनएस–सीएन (आईएम) की केंद्र सरकार के साथ वार्ता चल रही है. बावजूद इसके वह जेडयूएफ के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजमार्ग–37 में दिनदहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहा है. बहरहाल, सरकारी आंकड़े तो यह बताते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के चरमपंथी गुट शांति की तरफ लौट रहे हैं. बावजूद इस तरह की घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है. ■

शांति प्रक्रिया की स्थिति क्या है

असम
- यूपीडीएस (यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सोलिडैरिटी) के साथ 25 सितंबर 2011 को शांति समझौता हुआ था जो बाद में टूट गया.
- डीएचडी (हिम हालामडाउगाह) के साथ 8 अक्टूबर 2012 को समझौता हुआ था. फिलहाल, भंग हो चुका है.
- उल्फा के साथ वार्ता जारी है.
- कार्बीलोंगरी एनसी हिल्स लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ) की सरकार के साथ वार्ता जारी है.

मेघालय
- एएनवीसी (अचिक नेशनल वोलंटीयर काउंसिल) का केंद्र और राज्य सरकार के साथ शांति समझौता 24 सितंबर 2014 को हुआ था जो टूट चुका है.

मणिपुर
- केएनओ (कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन) के साथ शांति समझौता अगस्त 2008 को हुआ था जो 21 जुलाई 2016 तक वैध है.
- 19 भूमिगत संगठनों के साथ समझौता 13 फरवरी 2013 को हुआ था. यूपीपीके के 80 कार्डरों ने आत्मसमर्पण कर दिया था और समझौता ज्ञापन पर 24 मई 2013 को हस्ताक्षर हुआ था. 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2014 के अंदर 593 भूमिगत लोगों ने आत्मसमर्पण किया गया.

नगालैंड
- एनएससीएन (खोले-कितोवी) और एनएससीएन (रिफॉर्मेशन) के साथ संघर्ष विराम समझौता हुआ था जो कि 27 अप्रैल 2016 तक वैध है. एनएससीएन (आईएम) ने अनिश्चितकालीन संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए.

त्रिपुरा
- एनएलएफटी (बी) के नेताओं के साथ त्रिपुरा में शांति बहाली के लिए वार्ता प्रगति पर है.

पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय चरमपंथी गुट

असम :
1. यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)
2. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी)
3. कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (केएलओ)

मणिपुर :
1. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए)
2. यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ)
3. पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलैपाक (प्रीपाक)
4. कंगलैपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (केसीपी)
5. कंगलैपाक याउल कन्ना लुप (केवाईकेएल)
6. मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एमपीएलएफ)
7. रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ)
8. को-ऑर्डिनेशन कमेटी कोर कोम (घाटी पर कार्यरत छह चरमपंथी समूह)

मेघालय :
1. हाइन्यूट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी)
2. गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जीएनएलए)

त्रिपुरा :
1. ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ)
2. नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी)

नगालैंड :
1. द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (ईसाक मुइवा)
2. द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (खपलांग)
3. द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (खोले-कितोवी)
4. द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (रिफॉर्मेशन)

मिजोरम :
1. हमार पीपुल्स कन्वेंसन डेमोक्रेसी (एचपीसीडी)
2. द्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट (बीएनएलएफ)

अरुणाचल प्रदेश :
1. नेशनल लिबरेशन काउंसिल ऑफ तानी लैंड (एनएलसीटी)
2. तानी लैंड नेशनल लिबरेशन टाइगर (टीएलएनएलटी)
3. अरुणाचल ईगल फोर्स (एईएफ)
4. यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूपीडीएफ)

साल 2007 से 2015 तक पूर्वोत्तर राज्यों में मारे गए लोगों की संख्या

राज्य	घटनाएं	गिरफ्तार चरमपंथी	मारे गए चरमपंथी	आत्म समर्पण	शहीद सुरक्षाकर्मी	मारे गए आम जन	अपहृत आम जन
अरुणाचल	332	415	115	178	08	35	255
असम	2381	3609	839	3883	107	994	749
मणिपुर	3867	11267	1205	1363	134	486	375
मेघालय	683	713	148	949	32	129	336
मिजोरम	11	28	06	18	07	03	41
नागालैंड	1308	2230	416	43	13	164	645
त्रिपुरा	245	180	35	1101	14	37	226

www.kamalmorarka.com

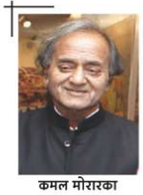

कमल मोरारका

जो सबसे अधिक सूखा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां माइक्रो मैनेजमेंट करना होगा. बिहार में जब भी नदियां उफान पर आती हैं, वहां बाढ़ आ जाती है और उसके बाद ही हम कोई क़दम उठाते हैं. इस पर गंभीर रूप से विचार करना चाहिए. प्रधानमंत्री विशेषज्ञों की एक कमेटी बना सकते हैं, जो इस समस्या का अध्ययन करे और उपाय सुझाए. अगर इसमें बड़ी रकम भी खर्च होती है, तो कोई बात नहीं. क्योंकि, जो तंत्र इसके लिए बनाया जाएगा, वह इस लायक होगा कि ऐसी स्थिति का सामना कर सके या ऐसी स्थिति पैदा होने से रोके. बाढ़ आने या सूखा पड़ने के बाद आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं, वह इससे कहीं ज़्यादा है. उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार इस पर ध्यान देगी.

संविधान का क्रियान्वयन सटीक होना चाहिए

उत्तराखंड में विश्वास मत हासिल करने से पहले राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले की सुनवाई उत्तराखंड हाईकोर्ट से होती हुई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है. इस प्रकरण के दो पहलू हैं, पहला तो घटनाक्रम है, जिसकी प्रकृति राजनीतिक है. इसमें अदालत बहुत कुछ नहीं कह सकती. दरअसल, राजनीतिक दलों को इस सिलसिले में स्वस्थ मानक स्थापित करने चाहिए. दल-बदल क़ानून जिस मकसद से बनाया गया था, बदक़िस्मती से वह मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है. लोगों के अंदर नैतिकता अलग से नहीं डाली जा सकती है. एक पार्टी से चुनाव जीतना और दूसरी पार्टी में जाना आख़िरकार नैतिकता का ही विषय है. विधायकों को एंटी डिफेक्शन क़ानून के दायरे में लाने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा. जो उत्तराखंड में हुआ और इससे पहले दूसरे राज्यों में हुआ, उसमें आम तौर पर यह देखा गया कि जब विधायकों की संख्या इतनी नहीं होती कि वे पार्टी को क़ानूनी तौर पर तोड़ सकें, तो अयोग्यता के दायरे में आने से बचने के लिए वे बगावत कर देते हैं. ऐसे में सत्ताधारी पक्ष का स्पीकर उनकी सदस्यता ख़त्म कर देता है या उन्हें निलंबित कर देता है. इस तरह सदन की क्षमता कृत्रिम तरीके से कम कर दी जाती है और यह तय हो जाता है कि सत्ताधारी पक्ष सत्ता में बना रहेगा. केंद्र सरकार, चाहे जिस भी पार्टी की हो, राष्ट्रपति शासन लगा देती है. अगर मुख्यमंत्री आ जाता है या नया स्पीकर आ जाता है, तो वह विधायकों से संबंधित अयोग्यता के फ़ैसले को उलट देगा. यह राजनीतिक कमजोरी है और इससे प्रजातांत्रिक मूल्यों में बेहतरी नहीं आती. स्पीकर को न्यायसंगत होना चाहिए, लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल में सभी स्पीकर सत्ताधारी दलों के हितों के लिए काम करते हैं.

केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट में जो पक्ष रखा गया, उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के फ़ैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती. यह एक ग़लत अवधारणा है. यह अलग बात है कि राष्ट्रपति देश के प्रतीक हैं और व्यक्तिगत तौर पर उनके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कहा जा सकता. लेकिन, उनके किसी फ़ैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, यह बात गले से नहीं उतरती. राष्ट्रपति का हर फ़ैसला मंत्रिपरिषद की सलाह और मदद से होता है. संविधान में जहां भी राष्ट्रपति शब्द आता है, तो उसका मतलब होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल (आप इसे केंद्र सरकार भी पढ़ सकते हैं). राष्ट्रपति की बात केंद्र सरकार की बात होती है. उनके शब्द केंद्र सरकार के शब्द होते हैं. इसलिए राष्ट्रपति के फ़ैसले की समीक्षा अदालत में हो सकती है. मिसाल के तौर पर, अगर राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करते हैं, तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति केवल नाम के लिए ही उक्त अध्यादेश जारी करते हैं. असल में वह अध्यादेश केंद्र सरकार की ओर से जारी किया जाता है. इसलिए यह कह देना कि राष्ट्रपति ने कोई फ़ैसला लिया है, तो कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, ग़लत है. अदालत की सुनवाई चाहे जिस दिशा में जाए, पर मसला यह है कि लेकिन राष्ट्रपति शासन हटने के बाद जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, वह अपना स्पीकर नियुक्त करेगा, जो एंटी डिफेक्शन में फंसे नौ विधायकों से जुड़े फ़ैसले को उलट देगा. यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा.

ऐसा कोई तरीका खोजना चाहिए, जिसके ज़रिये इस तरह के संकट का समाधान निकल सके. अगर कोई वास्तविक संकट पैदा होता है, तो विधानसभा भंग की जानी चाहिए और नए चुनाव कराने चाहिए, ताकि जनता की अदालत में सही फ़ैसला हो सके. लोकतंत्र में सबसे बड़ा जज जनता है. यह एक भौंडा खेल है, जो पहले अरुणाचल में खेला गया और फिर उत्तराखंड में. कांग्रेस ने भी दर्जनों बार ऐसा खेल खेला. यह सोचा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी एक नया ट्रेंड सेट करेंगे और भाजपा कुछ अच्छे मानक स्थापित करेगी, लेकिन मुझे अफ़सोस है कि ऐसा नहीं हुआ. दिल्ली में जब सिर्फ़ पांच विधायकों की ज़रूरत थी, तब उन्होंने ऐसा नहीं किया. लोगों में आशा जगी कि भाजपा इस तरह का खेल नहीं खेलेगी. भाजपा ने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जोड़-तोड़ करने की जगह चुनाव में जाना पसंद किया. भाजपा चुनाव में गई, लेकिन हार गई. अभी

वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है. लेकिन, मुझे लगता है कि बिहार चुनाव के बाद उन्होंने समझ लिया है कि जनता को टेकेन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता. इसलिए उन्होंने कांग्रेस के तरीके अपनाने शुरू कर दिए. भाजपा को लगा कि यही एकमात्र व्यवहारिक तरीका है, जो उन्होंने उत्तराखंड एवं अरुणाचल में इस्तेमाल किया और शायद आगे हिमाचल में भी उसका इस्तेमाल हो यह बहुत अफ़सोसजनक स्थिति है. जितनी जल्दी सारे राजनीतिक दल एक जगह एकत्र होकर संविधान के सही क्रियान्वयन के लिए बेहतर रास्ता निकालें, देश के लिए उतना ही अच्छा होगा.

चिंता का दूसरा विषय है महाराष्ट्र और देश के दूसरे हिस्सों में सूखे की स्थिति. अच्छे मानसून की संभावना और उसके साथ आने वाली बाढ़ सालाना समस्याएं हैं. या तो बहुत कम बारिश होगी या बहुत ज़्यादा. यानी सूखा या बाढ़ की स्थिति. मैं नहीं समझता कि हमारे पास इस स्थिति से निपटने के लिए कोई राष्ट्रीय योजना है. हमारे यहां नेशनल डिजास्टर रिलीफ कमीशन मौजूद है, जिसे वाजपेयी सरकार के दौरान गठित किया गया था. यह ठीक है. इस तरह की स्थिति में काम करने के लिए यही एकमात्र संस्था है. लेकिन, आपदा रोकने के लिए कोई योजना नहीं है. बेशक, वे नदियों को आपस में जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी से जुड़ी समस्याएं पैदा होंगी. फिलहाल, जो सबसे अधिक सूखा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां माइक्रो मैनेजमेंट करना होगा. बिहार में जब भी नदियां उफान पर आती हैं, वहां बाढ़ आ जाती है और उसके बाद ही हम कोई क़दम उठाते हैं. इस पर गंभीर रूप से विचार करना चाहिए. प्रधानमंत्री विशेषज्ञों की एक कमेटी बना सकते हैं, जो इस समस्या का अध्ययन करे और उपाय सुझाए. अगर इसमें बड़ी रकम भी खर्च होती है, तो कोई बात नहीं. क्योंकि, जो तंत्र इसके लिए बनाया जाएगा, वह इस लायक होगा कि ऐसी स्थिति का सामना कर सके या ऐसी स्थिति पैदा होने से रोके. बाढ़ आने या सूखा पड़ने के बाद आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं, वह इससे कहीं ज़्यादा है. उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार इस पर ध्यान देगी. ■

पाठकों की दुनिया

मोबाइल के ज़रिये जासूसी

कवर स्टोरी-बेहोश प्रधानमंत्री, भारत सरकार की जासूसी (18-24 अप्रैल, 2016) पढ़ा. आज बड़ी संख्या में लोगों के पास शाओमी या दूसरे चाइनीज मोबाइल हैं. सरकार को भी जानकारी है कि चीन इन मोबाइलों के ज़रिये भारत की जासूसी कर रहा है. सवाल यह है कि जानकारी होते हुए भी सरकार क्यों चुप है? सेना ने इन मोबाइलों पर रोक लगा रखी है, लेकिन सरकार इन मोबाइलों पर पूरे देश में रोक क्यों नहीं लगा रही है? आज अगर हम देखें, तो हर किसी की जासूसी हो रही है, जो पूरे देश के लिए ख़तरनाक है. इसलिए केंद्र सरकार को न सिर्फ़ इन मोबाइलों के इस्तेमाल पर, बल्कि इन कंपनियों के भारत में निवेश पर भी जल्द से जल्द रोक लगानी चाहिए.

–नंदलाल प्रसाद, *देवरिया, उत्तर प्रदेश.*

भ्रष्टाचार ने ली लोगों की जान

मानुषेर-राजनीति पर गिरा भ्रष्टाचार का पुल (18-24 अप्रैल, 2016) शीर्षक तले प्रकाशित रिपोर्ट ने सच उजागर करते हुए साफ़ कर दिया कि उक्त फ्लाईओवर के निर्माण का ठेका जिस कंपनी को दिया गया, उसे फ्लाईओवर बनाने का कोई अनुभव नहीं है. हैदराबाद बेस्ड उक्त कंपनी उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश में वर्षों से ब्लैकलिस्टेड है. उसे छत्तीसगढ़ में भी रायपुर-बिलासपुर हाइवे निर्माण के लिए ठेका मिला था, लेकिन नेशनल हाइवे अथॉरिटी ने कंपनी का काम संतोषजनक न पाए जाने पर ठेका निरस्त कर दिया था. बावजूद इसके कोलकाता में उसे फ्लाईओवर निर्माण का ठेका दिया गया. यह भ्रष्टाचार नहीं, तो क्या है?

–कमलेश सिंह, *मयूर विहार, नई दिल्ली.*

चंद्रशेखर जी की यादें

जब तोप मुक़ाबिल हो-चंद्रशेखर होने का मतलब (18-24 अप्रैल, 2016) बहुत अच्छा लगा. संतोष जी ने बिल्कुल सही कहा कि चंद्रशेखर जी ने कभी हार नहीं मानी. चंद्रशेखर जी हमेशा ग़रीबों, पीड़ितों एवं वंचितों की लड़ाई लड़ते रहे और वह आज भी हमारी यादों में रचे-बसे हैं. चंद्रशेखर जी ने एक दशक पहले जो आशंका ज़ाहिर की थी, वह सच साबित हो रही है. उदारवादी अर्थव्यवस्था के चलते देश में ग़रीब दिनोंदिन और ग़रीब होता जा रहा है, वहीं अमीर दिन दोगुनी-रात चौगुनी तरक्की कर रहा है. अगर चंद्रशेखर जी होते, तो वह ग़रीबों के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ते. सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन और अन्य विकास योजनाएं आख़िर किसके लिए हैं? जो ग़रीब आदमी ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं करा सकता, जो सामान्य श्रेणियों की ठसाठस भरी बोगियों में सफर करने को मजबूर है, वह बुलेट ट्रेन में यात्रा कर पाएगा?

–कनिका चक्रवर्ती, *जमशेदपुर, झारखंड.*

पूंजीपति लूट रहे देश का धन

चौथी दुनिया का नियमित पाठक हूं. कवर स्टोरी-पूंजीपतियों ने लूट लिया देश का धन, असली राष्ट्रद्रोही (04-10 अप्रैल, 2016) सराहनीय है. देश का धन लूटकर विजय माल्या जैसे लोग भाग गए. अगर कोई किसान उपज न होने के कारण कर्ज नहीं चुका पाता है, तो बैंक उस पर तरह-तरह से अत्याचार करते हैं. वहीं देश के पूंजीपति बैंकों के लाखों करोड़ रुपये दबाए बैठे हैं, लेकिन न बैंक उन पर कोई कार्रवाई करते हैं और न सरकार. यह कैसा राष्ट्रवाद है?

–श्याम बिहारी यादव, *ग्वालियर, मध्य प्रदेश.*

यह कैसी राष्ट्रभक्ति है

मेघनाद देसाई ने राजनीतिक हथियार के रूप में राष्ट्रवाद शीर्षक तले प्रकाशित अपने आलेख में यह बताने की कोशिश की कि राष्ट्रवाद राजनीतिक रूप से नेताओं की एक चतुर चाल है. सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस समेत अन्य भाजपा विरोधी पार्टियां इस जाल में आसानी से फंस गईं. भाजपा ने हिंदूवादी पार्टी के अपने लेबल से निकलने की कोशिश की और अब वह राष्ट्रवाद का लेबल लेकर घूम रही है. भाजपा आगे बढ़ रही है और कांग्रेस पीछे जा रही है. उदाहरण के तौर पर, कांग्रेस के हाथों से राज्यों की सत्ता का जाना है. अभी हाल में उत्तराखंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई. भाजपा या मोदी सरकार किसी पर भारत माता की जय बोलने का दबाव नहीं डाल सकती. भाजपा को किसी को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है.

–अभिषेक कुमार, *गया, बिहार.*

डॉक्टर दवाओं के नाम कैपिटल लेटर में लिखें

95 प्रतिशत डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाओं के नाम केवल मेडिकल स्टोर वाला पढ़ सकता है. मेडिकल स्टोर वाले अक्सर मिलते-जुलते नामों और फॉर्मूले वाली दवाएं ग्राहकों को पकड़ा देते हैं. डॉक्टरों से अनुरोध है कि वे रोगी पर्चे पर दवाओं के नाम लिखते समय अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करें.

–राज किशोर पांडेय, *लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.*

मध्य प्रदेश का तीखा सच

कवर स्टोरी-मृत्यु प्रदेश (28 मार्च-03 अप्रैल, 2016) के लिए चौथी दुनिया टीम बधाई की पात्र है. इस सात पृष्ठीय विस्तृत रिपोर्ट ने बताया कि देश के किसान किस कदर बदहाली का जीवन बिता रहे हैं और हर तरफ़ से थक-हारकर मौत को गले लगा रहे हैं. चौथी दुनिया ने किसानों द्वारा आत्महत्या के 18 मामलों की पड़ताल के बाद मध्य प्रदेश की ज़मीनी हक़ीक़त से पाठकों को अवगत कराया. इस रिपोर्ट ने बड़े-बड़े दावे करने वाली केंद्र एवं राज्य सरकारों की पोल खोल दी है.

–शरद श्रीवास्तव, *मुरैना, मध्य प्रदेश.*

* पिछले काफी दिनों से किसानों को लेकर, उनके द्वारा आत्महत्या किए जाने को लेकर, केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किसानों के लिए की गई घोषणाओं को लेकर तमाम समाचार, रिपोर्ट्स और आलेख पढ़ने को मिले. लेकिन, चौथी दुनिया ने अपनी विशेष आवरण कथा-मृत्यु प्रदेश के ज़रिये कृषि कर्मण पुरस्कार हासिल करने वाली मध्य प्रदेश सरकार की जिस तरह बखिया उधेड़ी, उसके लिए अख़बार तारीफ़ का हक़दार है.

–नवनीत पांडेय, *इंदौर, मध्य प्रदेश.*

* 28 मार्च-03 अप्रैल, 2016 का अंक संग्रहणीय है. चौथी दुनिया ने किसानों की बदहाली पर रोशनी डालते हुए मध्य प्रदेश को मृत्यु प्रदेश की संज्ञा दी, जो किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं है. मुख्य आलेख की प्रस्तुति का तरीका भी काफी सराहनीय है, यह विषय-वस्तु समझने में सहायक साबित हुआ.

–विनय गुप्ता, *कानपुर, उत्तर प्रदेश.*

* मध्य प्रदेश के किसानों की बदहाली और राज्य की शिवराज सरकार द्वारा किसानों के प्रति गद्दारी की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर किसानों की आवाज़ बनने के लिए चौथी दुनिया का शुक्रिया.

–उमेश तिवारी, *ई-मेल से.*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

राष्ट्रपति शासन पर निर्णायक फ़ैसला ज़रूरी

यह संपादकीय लिखते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है क्योंकि जब यह अंक आपके पास पहुंचेगा तब तक हो सकता है आपके सामने स्थिति स्वत: स्पष्ट हो चुकी हो. उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतिम रूप से संवैधानिक स्थिति की व्याख्या होनी चाहिए. उत्तराखंड में जिस तरह राष्ट्रपति शासन लगा उसे हाईकोर्ट में हरीश रावत ने चुनौती दी और हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन गलत लगाया गया है और उसने राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर दिया. इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि राष्ट्रपति राजा नहीं है, भगवान नहीं है, जिसके ऊपर बातचीत न की जा सके. इस टिप्पणी के पीछे केंद्र सरकार का यह बयान था कि कहीं पर भी राष्ट्रपति द्वारा दी गई सलाह के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कब फैसला देगा पता नहीं लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस सवाल के ऊपर फैसला देना चाहिए कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति, जो धारा 356 के तहत साफ की गई है, को और साफ करने की आवश्यकता है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट को यह भी साफ करना होगा कि हाईकोर्ट की यह टिप्पणी कि 9 विधायकों ने संवैधानिक पाप किया है. अगर हाईकोर्ट की यह टिप्पणी सही है तो सुप्रीम कोर्ट को इसे पुष्ट करना चाहिए ताकि देश की किसी विधानसभा में दलबदल की आशंकाओं को समाप्त किया जा सके.

दरअसल, एक तो हमारी राज्य सरकारें काम नहीं करतीं जहां काम करती हैं, वहां उन्हें अंदर और बाहर दोनों तरफ से विरोध का सामना करना पड़ता है और तीसरा, विधायक अपनी पार्टी में राजनीतिक विरोध कर उन्हीं पर्टियों से हाथ मिला लेते हैं जिन पार्टियों को हराकर वो विधानसभा में पहुंचे हैं. दलबदल कानून लागू है लेकिन दलबदल कानून का उद्देश्य पूरी तरह विफल रहा है. इसलिए राज्यपाल के हस्तक्षेप करने का समय और तरीका, केंद्र सरकार द्वारा विश्लेषण करने का समय व तरीका तथा राष्ट्रपति का इस्तेमाल केंद्र सरकार अपने राजनीतिक हितों के लिए कितना करे, ये सारी स्थितियां स्पष्ट होनी आवश्यक हैं. भारत के इतिहास में संभवत: पहली बार किसी राज्य के हाईकोर्ट ने इतना बड़ा फैसला लिया है और हाईकोर्ट यह अवश्य जानता होगा कि इस फैसले के खिलाफ जो पक्ष है वह सुप्रीम कोर्ट में अवश्य जाएगा. सुप्रीम कोर्ट इस फैसले की विवेचना करने के बाद जो निर्णय देगा वह निर्णय हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और विधानसभाओं के कार्य करने के तरीके पर बहुत बड़ा असर डालने वाला है.

> भाजपा किसी भी तरह सत्ता चाहिए की नीति पर नहीं चलती तो उसे देश में अद्भुत समर्थन मिलता. नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय मिलने वाला समर्थन आने वाले अच्छे भविष्य की स्थापना के लिए लोगों द्वारा किया गया एक अभियान था. उस अभियान के रथ पर सवार होकर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन दो साल के बाद जो भी वक्त जा रहा है वह वक्त नरेंद्र मोदी के प्रति या भाजपा के प्रति इस देश में एक चिंता खड़ी कर रहा है.

हरीश रावत बड़ी मुश्किलों से मुख्यमंत्री बने. उन्होंने अपने पूर्ववर्ती साथी और उनसे पहले के मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा की नाराजगी मोल ली क्योंकि विजय बहुगुणा को यह लगा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटवाने के पीछे हरीश रावत का हाथ है. हो सकता है यह सही हो या गलत हो, लेकिन विजय बहुगुणा उत्तराखंड में कुछ बड़े औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे और जिस दलबदल को लेकर यह सारा संकट शुरू हुआ वह उसके निर्माताओं में से एक रहे हैं. विजय बहुगुणा को अभी तक कांग्रेस पार्टी ने दल से निष्कासित नहीं किया है सिर्फ उनके बेटे को कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित किया है. यदि कांग्रेस पार्टी को फैसला लेना ही था तो विजय बहुगुणा के खिलाफ भी फैसला लेना चाहिए था. हरक सिंह रावत उत्तराखंड में अब तक कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं. मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी रहे हैं और मुझे आशा है कि भाजपा ने अवश्य यह वादा किया होगा कि यदि वह कांग्रेस में विद्रोह करा सकते हैं तो भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर बैठाएगी. लेकिन अब स्थिति दूसरी हो गई है यदि हाईकोर्ट के इस फैसले को मानें तो सभी बागी 9 सदस्यों की सदस्यता रद्द हो जाएगी. और यह सदस्यता रद्द होने के बाद क्या नौ विधायक तत्काल अगला उपचुनाव लड़ पाएंगे या उनके चुनाव लड़ने के ऊपर भी कोई रोक हाईकोर्ट लगाएगा, यह देखना अभी बाकी है.

भाजपा एक शुद्ध राजनीति का झंडा लेकर शासन करने पहुंची, लेकिन भाजपा ने वो सारे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए जिन हथकंडों के लिए आज तक कांग्रेस बदनाम रही है. हो सकता है भाजपा को यह अहसास हुआ हो कि उन्हें चुनाव के द्वारा विधानसभाओं में बहुमत मिलना थोड़ा मुश्किल है इसलिए जितनी सरकारों के नीचे से ज़मीन खींची जा सके उस ज़मीन को खींचना चाहिए और देश को कांग्रेस मुक्त बनाने की दिशा में तेज़ी से दौड़ना चाहिए. कांग्रेस मुक्त भारत वोटरों को समझाने का नरेंद्र मोदी का एक बहाना था यह नारा वोटरों के लिए था. लेकिन सरकारों को गिराकर, विधायकों को तोड़कर देश को कांग्रेस मुक्त बनाना ये सवाल कहीं न कहीं संविधान के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है. हम जो कहें वही संविधान कह रहा है, इस बात को कहने वाले राजनेता यह भूल जाते हैं कि संविधान का एक अलग रुख होता है और वह रुख सही है या गलत है इसका फैसला या तो अदालत या फिर जनता करती है. भाजपा किसी भी तरह सत्ता चाहिए की नीति पर नहीं चलती तो उसे देश में अद्भुत समर्थन मिलता. नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय मिलने वाला समर्थन आने वाले अच्छे भविष्य की स्थापना के लिए लोगों द्वारा किया गया एक अभियान था. उस अभियान के रथ पर सवार होकर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन दो साल के बाद जो भी वक्त जा रहा है, वह वक्त नरेंद्र मोदी के प्रति या भाजपा के प्रति इस देश में एक चिंता खड़ी कर रहा है. टेलीविजन, अखबार और रेडियो की इस दुनिया में, जो आज घर-घर पहुंच चुका है, जो लोग अखबार पढ़ रहे हैं या टेलीविजन देख रहे हैं वह यह सवाल जरूर करते हैं कि आपने तो यह कहा था, अब आप यह कह रहे हैं. आप तो ये करने वाले थे आप अब ये कर रहे हैं और ये सवाल लोगों को पूछने ही चाहिए. क्योंकि हम जब किसी वादे को ध्यान में रखकर वोट देते हैं और बाद में कह दिया जाए कि यह तो एक चुनावी जुमला था तो ऐसा लगता है कि जीती हुई राजनीतिक पार्टी स्वयं एक जुमले के इर्द-गिर्द घिरी हुई है.

और यहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी की भारतीय जनता पार्टी से अलग आज अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है. अमित शाह की भाजपा वोटरों के ऊपर इंपैक्ट जमाने में लगभग नाकामयाब है इसलिए अगर सुप्रीमकोर्ट को हाईकोर्ट द्वारा उत्तराखंड सरकार के संदर्भ में संपूर्ण फैसले और संपूर्ण टिप्पणियां सामने रख इसके बारे में अपना अंतिम रुख बहुत जल्दी सार्वजनिक करना चाहिए क्योंकि देश के लोग अब सरकारों की तरफ कम और अदालत की तरफ ज्यादा देखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकारें तो करप्शन भी करेंगी, सरकार काम भी नहीं करेंगी अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अदालतों के द्वारा हो सकता है इसलिए वो अदालत की तरफ देखती भी है. अदालत के फैसले का सम्मान भी करती है और अदालत से अपेक्षा भी करती है कि वह ऐसे किसी भी अंतरविरोध की स्थिति में आईने की तरफ साफ फैसला लोगों के सामने दे. उत्तराखंड के मसले में हमारा भी यही अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट को अंतिम स्थिति बहुत जल्दी स्पष्ट करनी चाहिए. ■

editor@chauthiduniya.com

2019 में बन सकता है गठबंधनों का गठबंधन

मेघनाद देसाई

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का उत्सुकता से इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन 2019 के बड़े मैच की तैयारी अभी से शुरू हो गई है. आप कह सकते हैं कि हर राज्य के चुनाव नतीजे अगले आम चुनाव की दिशा तय करेंगे. पिछले वर्ष बिहार और दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने भाजपा-एनडीए विरोधी खेमे में जोश भर दिया था. लिहाज़ा, आगे की लड़ाई के लिए भाजपा विरोधी ताक़तों को संगठित करने की कवायद शुरू हो गई है. एक तरफ़ जदयू का कुछ हद तक बड़ा गठबंधन है, जिसे उत्तर प्रदेश में चुनाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इसके एक से अधिक अर्थ हैं. यह रणनीति 2019 में भाजपा विरोधी गठबंधन के नेता के रूप में नीतीश कुमार की मज़बूत दावेदारी के लिए अपनाई जा रही है. कांग्रेस ने पहले से ही इस गठबंधन में शामिल होने की अपनी इच्छा ज़ाहिर कर दी है.

पिछले वर्ष दिल्ली में आयोजित एक कांफ्रेंस में अखिलेश यादव ने घोषणा की थी कि मुलायम सिंह यादव 2019 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे. उन्होंने कांफ्रेंस में मौजूद राहुल गांधी को उपप्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आमंत्रित किया था. खुशक़िस्मती से राहुल गांधी के पास दो नेता हैं, जिनके वह नायब की भूमिका निभा सकते हैं. अभी यह साफ़ नहीं हुआ है कि समाजवादी पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले भाजपा विरोधी गठबंधन का हिस्सा बनेगी या नहीं. यह इस पर निर्भर करता है कि अगले वर्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे कैसे आते हैं. फ़िलहाल वहां सपा, बसपा और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुक़ाबले की संभावना दिख रही है. वहां जदयू की कोई खास भूमिका नहीं होगी, चाहे कांग्रेस उसके गठबंधन में शामिल हो या नहीं. इस बीच भाजपा दो तरह के संकेत दे रही है. पहला यह कि हिंदुत्व के बजाय राष्ट्रवाद उसका मूल संदेश है. दूसरा यह कि उसने राज्य स्तर पर पिछड़े वर्ग के नेतृत्व को प्रमुखता दी है. केशव प्रसाद मौर्य के रूप में उसने उत्तर प्रदेश के लिए एक आदर्श नेता ढूंढ लिया है, जो पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं और मंदिर मुद्दे पर भी (हालांकि, वह इससे जुड़े क़ानूनी पहलुओं से आगाह हैं) उनका मज़बूत पक्ष है. अगर राज्य के ब्राह्मण भाजपा को छोड़ देते हैं, तो सपा और बसपा में से किसी विकल्प को चुनना उनकी मजबूरी होगी.

अरविंद केजरीवाल 2019 के चुनाव के डार्क हॉर्स (अप्रत्याशित विजेता) साबित हो सकते हैं. अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में प्रभावकारी तरीके से चुनाव जीत जाती है, तो केजरीवाल की राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा पुनर्जीवित हो जाएगी. इसके लिए आम आदमी पार्टी को पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी होने की आवश्यकता भी नहीं है. उसे केवल सरकार बनाने के लिए कांग्रेस या शिरोमणि अकाली दल को बाहर से उसका समर्थन लेने पर मजबूर करना होगा. अगर ऐसा हो गया, तो अरविंद केजरीवाल 2019 के नेतृत्व के दावेदार बन जाएंगे. अगर भाजपा की पाकिस्तान नीति पर केजरीवाल के हमले पर ग़ौर करें, तो उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा समझ में आ जाएगी. लेकिन हमें आशा करनी चाहिए कि अगर केजरीवाल चुनाव जीत जाते हैं, तो वह भी पाकिस्तान के साथ नरेंद्र मोदी की तरह संयम की नीति अपनाएंगे, न कि न्यूक्लियर बहस छेड़ेंगे.

2009 के चुनाव से पहले, जैसा कि बहुतों को याद होगा, यूपीए के विरुद्ध 18 दलों का एक गठबंधन बना था, जो पूरी तरह नाकाम हो गया था. एक बार फिर 2019 में एक से अधिक गठबंधन की उम्मीद है या ऐसा भी हो सकता है कि अलग-अलग गठबंधनों को कई प्रधानमंत्री उम्मीदवारों (नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, अरविंद केजरीवाल और मायावती) के साथ एक जगह एकत्र होना पड़े. जब कांग्रेस एक प्रभावी राष्ट्रीय पार्टी थी, तो उसे पहली बार 1977 में जनता गठबंधन ने निर्णायक तौर पर हराया था. वह गठबंधन भाजपा के सबसे बड़ी इकाई के तौर पर उभरने से बिखर गया और बाक़ी हिस्सा जनता दल के अलग-अलग घटकों में बंट गया. अब जबकि भाजपा बहुत बड़ी हो गई है, जनता दल को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाएगा. इस बार कांग्रेस की भूमिका अहम होगी. अब नई जनता पार्टी का अस्तित्व बचेगा या नहीं, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. ■

> एक बार फिर 2019 में एक से अधिक गठबंधन की उम्मीद है या ऐसा भी हो सकता है कि अलग-अलग गठबंधनों को कई प्रधानमंत्री उम्मीदवारों (नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, अरविंद केजरीवाल और मायावती) के साथ एक जगह एकत्र होना पड़े. जब कांग्रेस एक प्रभावी राष्ट्रीय पार्टी थी, तो उसे पहली बार 1977 में जनता गठबंधन ने निर्णायक तौर पर हराया था. वह गठबंधन भाजपा के सबसे बड़ी इकाई के तौर पर उभरने से बिखर गया और बाक़ी हिस्सा जनता दल के अलग-अलग घटकों में बंट गया. अब जबकि भाजपा बहुत बड़ी हो गई है, जनता दल को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाएगा. इस बार कांग्रेस की भूमिका अहम होगी. अब नई जनता पार्टी का अस्तित्व बचेगा या नहीं, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती.

वास्तु विहार®
एक विश्वस्तरीय टाउनशिप
AN ISO : 9001 : 2008 : 14001 : 18001 : 2007 COMPANY

The Most Cost Effective Builder in India

4 से 50 लाख तक में घर

Customer Care : 080 10 222222

www.vastuvihar.org

शिक्षकों की लड़ाई में छात्र बेहाल

सुबील सौरभ

बिहार में मगध विश्वविद्यालय के भीतर शिक्षकों की आपसी लड़ाई ने छात्रों के भविष्य को अधर में डाल दिया है. राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक मगध विश्वविद्यालय में पढ़ाई छोड़ कर सब कुछ हो रहा है. इस विश्वविद्यालय में पठन-पाठन की क्या स्थिति है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्वविद्यालयों को ग्रेड देने वाली संस्था नैक की टीम ने अपने निरीक्षण के बाद मगध विश्वविद्यालय को सी ग्रेड दिया. यदि डी ग्रेड मिलता तो मगध विश्वविद्यालय की मान्यता भी समाप्त हो सकती थी. नैक की टीम ने निरीक्षण के बाद मगध विश्वविद्यालय के विभागों में शैक्षणिक माहौल का अभाव, शिक्षकों तथा शोध की बेहद कमी पर तल्ख टिप्पणी की थी. नैक ने यह भी कहा था कि पठन-पाठन का माहौल सबसे अच्छा होना चाहिए. लेकिन इस बात की कमी इस विश्वविद्यालय में है.

नैक का निरीक्षण कराने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर सभी भवनों का रंग-रोगन और जीर्णोद्धार कराया गया, लेकिन शिक्षण व्यवस्था पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया. इस कारण कभी देश में अपनी शैक्षणिक गरिमा के लिए चर्चित रहे मगध विश्वविद्यालय को जब सी ग्रेड मिला तो बड़ी बदनामी हुई.इस दौरान शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के संघों ने भी मगध विश्वविद्यालयों के कुलपति समेत कई पदाधिकारियों के कार्यकलापों पर सवाल उठाये. लेकिन इनकी आवाज प्रशासनिक दबाव में दबा दी गई. मगध विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राओं को अपनी पढ़ाई के लिए आन्दोलन करना पड़ता है. यहां छात्र के हितों की बात कम होती है. इसका प्रमाण है कि मगध विश्वविद्यालय सीनेट की बैठक 10 अप्रैल 2016 को विश्वविद्यालय मुख्यालय से बाहर राजगीर में कराया गया. जिसमें के लाखों रुपये बेमतलब खर्च हुआ.

कारण यह था कि विभिन्न छात्र संगठनों ने दलीय भावना से हटकर छात्रहित की बात करने और अपनी विभिन्न मांगों को सीनेट की बैठक के दौरान उठाने की बात की थी. छात्रों द्वारा अपनी मांगों को लेकर हंगामे से बचने के लिए राजगीर में सीनेट की बैठक करायी गयी. यह बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, छात्र समागम तथा अन्य छात्र संगठनों के नेताओं ने कहीं. 44 अंगीभूत और डाई सौ से अधिक संबद्ध कॉलेजों वाले मगध विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भी भारी कमी है. कई अंगीभूत कॉलेजों के विभाग तो एक शिक्षक के सहारे ही चल रहे हैं. छात्रों की पढ़ाई के लिए मगध विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों की कमी को देखते हुए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है. वहीं दूसरी ओर अंगीभूत कॉलेजों के व्याख्याता से लेकर प्रोफेसर तक अपने विभागों के क्लास को छोड़कर सेल्फ फाइनांस वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में ज्यादा रुचि दिखाते हैं. इस मामले पर यदि जांच की जाए तो गया कॉलेज के कई शिक्षक बेनकाब हो जाएंगे. इन सब से अलग मगध विश्वविद्यालय मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी अपने विभागों में आवंटित राशि को जल्द से जल्द वारा-न्यारा करने में लगे रहते हैं. इन दिनों मगध विश्वविद्यालय कई अनियमितताओं के कारण जांच के दायरे से गुजर रहा है. बिहार सरकार के निगरानी विभाग द्वारा मगध विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमियता की जांच की जा रही है. वहीं दूसरी ओर कई विदेशियों को बिना भारत आए ही पीएचडी की डिग्री दिए जाने का मामला भी जांच के घेरे में आ गया है. विकट स्थिति तब हो गई, जबकि मगध विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रो. कृतेश्वर प्रसाद ने राजभवन को पत्र लिखकर अपने ही अधिकारियों के अधिकार पर सवाल खड़ा कर दिया. प्रति कुलपति ने अपने पत्र में कुलाधिपति सह राज्यपाल को कहा कि मगध विश्वविद्यालय में वित्त परामर्शी को नजर अंदाज कर वित्तीय काम किये जा रहे हैं.

> मगध विश्वविद्यालय मुख्यालय में तैनात पदाधिकारी विभागों में आवंटित राशि का जल्द से जल्द वारा-न्यारा करने में लगे रहते हैं. इन दिनों मगध विश्वविद्यालय विभिन्न अनियमितताओं के कारण अनेक जांच के दायरे से गुजर रहा है.

उन्होंने कहा कि वित्त परामर्शी के बिना सहमति व सलाह के ही कई प्रस्तावों को सिंडिकेट से पास करा दिया गया है. जो कि बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 3, 6, 7 का उल्लंघन है. प्रति कुलपति द्वारा लिखा गया है कि विश्वविद्यालय के कुलसचिव के द्वारा अधिनियम 12 ए की इपधारा 6 का हनन किया गया है. प्रति कुलपति ने लिखा है कि सिंडिकेट में कोई भी प्रस्ताव लाने से पहले वित्त परामर्शी से सलाह व अनुमति लेना अनिवार्य है. लेकिन ऐसा नहीं कर तथ्यों को छुपाते हुए प्रस्तावों को सिंडिकेट से पारित करा लिया गया. प्रति कुलपति ने कुलाधिपति से इस गंभीर मामले पर शीघ्र हस्तक्षेप करने की मांग की है. मगध विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के संचालकों को भी मगध विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों द्वारा प्रताड़ित करने का मामला भी सामने आते रहता है.

हालांकि पिछले एक दशक में जो भी कुलपति आए, उनका एक ही मकसद रहा कि मगध विश्वविद्यालय में जमा राशि को कैसे खर्च किया जाए? हालांकि मगध विश्वविद्यालय की स्थिति जब बहुत ही दयनीय थी तो वीएन पाण्डेय कुलपति बनकर आये और यहां के माहौल को बेहतर बनाया. लेकिन बाद के दिनों में मगध विश्वविद्यालय अपने काले कारनामों के लिए चर्चा में आ रहा है और विभिन्न तरह के जांच के घेरे में हैं. यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि मगध विश्वविद्यालय में पठन-पाठन को छोड़कर बाकि सबकुछ हो रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

नकली बीज ने मक्का किसानों के सपने तोड़े

कोसी तथा मिथिला इलाके में इस बार भी नकली बीज विक्रेताओं ने किसानों को इस कदर ठगा कि असली कीमत पर बीज तो किसानों के द्वारा खरीदे गए लेकिन मक्के की अच्छी पैदावार नहीं हुई. नतीजतन किसानों के घरों में सिसकियां गूंज रही है.

राजेश सिन्हा

feedback@chauthiduniya.com

नकली बीज का कारोबार करने वाले धंधेबाजों ने इस बार भी असली बीज के पॉकेट में नकली मक्के के बीज किसानों को उपलब्ध कराए. इस कारण मक्का फसल इस बार ठीक नहीं हुई. महाजनों से सूद पर रुपये लेकर किसानों ने बीज इस ख्याल से बोए थे कि अच्छी पैदावार होगी. लेकिन उनके सपने पूरे नहीं हो सके.

यह पहली बार नहीं है जब किसानों को धोखा हुआ है. इसके पहले भी किसान बीज खरीददारी के मामले में ठगी का शिकार हो चुके हैं. उस समय धरना प्रदर्शन कर किसानों के द्वारा रोष प्रकट किया गया था. सरकारी हुक्मरानों के द्वारा ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया, लेकिन वक्त के साथ-साथ ठगी का मामला दफन होकर रह गया. अब एक बार फिर किसान ठगी का शिकार हुए हैं. लेकिन लगता नहीं है कि इस बार भी राज्य सरकार कोई ठोस कार्रवाई कर सकेगी. हां! किसानों को ठोस कार्रवाई का भरोसा जरूर मिल रहा है.

अन्य इलाकों की बातों को अगर नजरअंदाज कर भी दिया जाय तो मक्का का गढ़ कहे जाने वाले फरकिया अर्थात खगड़िया, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल तथा खगड़िया मुख्यालय से सटे रहीमपुर कुहरचक्की सहित अन्य गांव के किसान इस बार मक्का की अच्छी पैदावार नहीं होने के कारण माथा पीट रहे हैं. खगड़िया जिलेद के अन्तर्गत परबत्ता प्रखंड के किसान जयराम यादव का कहना है कि सही समय पर मक्के का सरकारी बीज नहीं मिलने के कारण किसानों ने निजी कंपनियों के बीज खरीदे. सौ रुपये किलो के भाव से इनलोगों ने प्रोएग्रो कम्पनी का मक्का बीज खरीदा था. लेकिन पैदावार नहीं के बराबर होने से अब मक्का के पौधे का उपयोग मवेशियों के चारे के लिए किया जा रहा है.

सहरसा जिले के चर्चित किसान नेपाली मंडल, राजेश सदा, सुबोध साह तथा लाली झा ने अपनी बेबसी बयान करते हुए कहा कि वह लोग कई बार सरकारी बीज पाने की चाहत में ठगे गए. समय व्यतीत होने के बाद सरकारी बीज उपलब्ध कराया गया. इस तरह की स्थिति के कारण उन लोगों ने प्रोएग्रो कम्पनी का मक्का बीज खरीदा था. बीज विक्रेता ने अच्छी पैदावार होने का भरोसा दिलाया था. बावजूद इसके जब अच्छी पैदावार नहीं हुई तो बीज विक्रेता से शिकायत की गई. लेकिन बीज विक्रेता ने यह कहकर पल्लू झाड़ लिया कि कंपनी के सेल्समैन के द्वारा दिलाए गए भरोसे के आधार पर उन्होंने किसानों को अच्छी पैदावार का भरोसा दिलाया था. इस संदर्भ में कंपनी से शिकायत की गई है. अगर कंपनी के द्वारा इस संदर्भ में कोई पहल की जाएगी तो किसानों को सूचना दी जाएगी.

> यह पहली बार नहीं है जब किसानों को धोखा हुआ है. इसके पहले भी किसान बीज खरीददारी के मामले में ठगी का शिकार हो चुके हैं. उस समय धरना प्रदर्शन कर किसानों के द्वारा रोष प्रकट किया गया था. सरकारी हुक्मरानों के द्वारा ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया, लेकिन वक्त के साथ-साथ ठगी का मामला दफन होकर रह गया.

खगड़िया प्रखंड मुख्यालय स्थित शेखपुरा गांव के किसान जवाहर महतो का कहना है कि पहले लोग मक्के का उत्पादन होने के बाद कुछ अच्छे मक्के के दानों को बीज के बाबत रख लेते थे. बुआई के समय मक्का बीज के रूप में इसी घरेलू बीज का प्रयोग किया जाता था लेकिन पैदावार बहुत अच्छी नहीं होती थी. काफी मेहनत के बाद भी अधिक से अधिक प्रति बीघा साठ मन अनाज ही होता था. इसी बीच कारगिल 900 एम नामक मक्का बीज बाजार में आया. किसानों के द्वारा जब इस बीज का प्रयोग किया गया तो प्रति बीघा सौ से एक सौ बीस मन मक्का हुआ. इस तरह की स्थिति देखकर अधिसंख्य किसानों के द्वारा इसी बीज का उपयोग किया जाने लगा. इस बीज से अच्छी पैदावार होने के कारण किसानों का कारगिल 900 एम के प्रति विश्वास जम गया. बस तुरंत ही बाजार में कारगिल 900 के नकली बीज उतार दिए गए. नतीजतन किसानों को भारी धक्का सहना पड़ा. उसके बाद प्रोएग्रो बीज आ गया. किसानों को जब इससे लाभ होने लगा तो फिर इसका भी नकली बीज बाजार में आ गया. कई किसानों ने इस बार अच्छी पैदावार होने के बाद बिटिया की शादी तो कई ने घर बनाने की सोच रखी थी. लेकिन सब बर्बाद हो गया.

एक अधिकृत बीज विक्रेता का कहना है कि कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि बाजार में उसकी साख पर बट्टा लगे. नकली बीज का कारोबार करने वाले कंपनियों का नाम बदनाम करते हैं. उधर नकली बीज का धंधा करने वाले एक कारोबारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि जिस कंपनी के बीज पर किसान अधिक भरोसा करने लगते हैं, उसी कंपनी के बैग में नकली बीज पैक कर बाजार में उतार दिया जाता है. किसान भरोसे के बल पर इस वर्ष भरोसे की कंपनी का ही बीज खरीदते हैं और ठगे जाते हैं.

किसानों द्वारा असली और नकली बीज पहचान पाना संभव नहीं है. इसी का फायदा उठाते हुए धंधेबाजों के द्वारा किसानों को ठगी का शिकार बनाया जाता है. बीज विक्रेता अगर चाहें तो किसानों को ठगी का शिकार होने से बचाया जा सकता है लेकिन अधिक मुनाफा पाने की चाहत में विक्रेताओं के द्वारा किसानों को गुमराह किया जाता है.

दूसरी तरफ खगड़िया के जिलाधिकारी साकेत कुमार का कहना है कि यह काफी हद तक सही है कि सस्मय किसानों को सरकारी बीज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं जिसके कारण निजी कंपनियों के बीज का उपयोग किसानों के द्वारा किया जाता है. नकली बीज का धंधा करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध समय-समय पर कारवाई की जाती है. अगर इस बार भी किसानों के द्वारा शिकायत की जाएगी तो निश्चित तौर पर आरोपी दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. लेकिन किसानों को भी चाहिए कि अधिकृत बीज विक्रताओं से ही बीज की खरीदारी करें वह भी रसीद के साथ.

बहरहाल, ठगी का शिकार होने वाले किसानों की शिकायत पर नकली बीज विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई होगी या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा लेकिन राज्य सरकार को चाहिए कि किसानों को न केवल सही समय पर सरकारी बीज उपलब्ध कराई जाय बल्कि नकली बीज का कारोबार करने वालों पर ठोस कार्रवाई भी हो. ■

CRM
TMT BAR

ISO 9001 - 2000 Certified Co.
IS:1786:2008
CM/L-5746178

Fe-500
मुख्य खूबियाँ
• बचत
• मजबूती
• शानदार फिनीश

Mfg. : CITY ROLLING MILLS PVT. LTD., PATNA
HELPLINE : 0612-2216770

VCSM®
विश्व कम्प्यूटर साक्षरता मिशन
A program initiated by Sanjeeo Technological System (P.) Ltd.
ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 Certified
VCSM की फ्रेंचाइजी बनिए और अपने साथ-साथ हजारों के कैरियर बनायें।
विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें : जूही अलका 9386551901

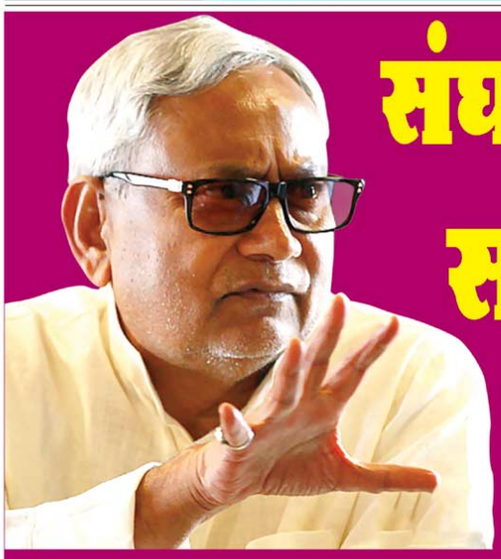

संघ मुक्त भारत का सपना साकार करेंगे नीतीश

राजनीति में नई छलांग लेने के लिए नीतीश कुमार के पक्ष में कई सकारात्मक बातें हैं. केन्द्र में वर्षों तक मंत्री और दस साल से अधिक समय से बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे इस समाजवादी राजनेता की छवि बेदाग तो है ही, उनकी पहचान बेहतर प्रशासक और विकास पुरुष की रही है. बिहार को उन्होंने अंधेरी सुरंग से निकाल कर आशा और विश्वास की डगर पर लाकर खड़ा किया है. यह राजनीतिक हलके में उन्हें गंभीरता प्रदान करता है. बिहार विधानसभा चुनावों में नरेन्द्र मोदी को शिकस्त देने के बाद वह बड़े लड़ैया के तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में पहचाने जाने लगे हैं. बिहार में लालू प्रसाद को साध कर आगे बढ़ रहे हैं, सरकार चला रहे हैं. पिछले दस वर्षों में उन्होंने महिला-अतिपिछड़ा-महादलित का व्यापक वोट बैंक तैयार करने की कोशिश की है. महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के अनेक कार्यों को जमीन पर उतारने के बाद अब शराबबंदी के कारण बिहार में महिला मतदाताओं की उन्हें पहली पसंद माना जाने लगा है.

सरोज सिंह

बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल (यू) के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार रौ में हैं और 'मिशन 2019' के अपने एजेंडे को एक-एक कर सामने ला रहे हैं. उनका सबसे ताज़ा एजेंडा है 'आरएसएस मुक्त भारत.' उनका मानना है कि संघ की सत्ता के रहते भारत का समावेशी विकास नहीं हो सकता है. देश की रक्षा के लिए इसे संघ से मुक्त करना होगा, गैर-संघवाद का व्यापक अभियान चलाना होगा. इस सपने को साकार करने के लिए सभी भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों को एक छतरी के नीचे लाने की जरूरत वह महसूस करते हैं और इस दिशा में सक्रिय भी हैं. इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री ने देश में दो ध्रुवीय राजनीति के पक्ष में अपनी राय दी है. उनकी समझ है कि देश में दो राजनीतिक ध्रुव ही हो सकता है: भाजपा समर्थक और भाजपा विरोधी, अर्थात् आरएसस समर्थक और आरएसएस विरोधी. देश में सक्रिय राजनीतिक दलों को किसी पक्ष में तो जाना ही होगा. पर ऐसा निर्णय लेते वक्त भाजपा के पुराने सहयोगी शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल के अनुभवों को भी देखना होगा. उन्होंने संघ मुक्त भारत बनाने के लिए डॉ. राम मनोहर लोहिया के गैर कांग्रेसवाद के प्रयोग को भी याद किया. हालांकि उस प्रयोग का एक बड़ा घटक तत्कालीन भारतीय जनसंघ था. नीतीश कुमार जद(यू) के औपचारिक सुप्रीमो पिछले हफ्ते ही बने हैं और तब से वह मिशन 'मिशन 2019' के तहत अपने एजेंडों की ताबड़तोड़ घोषणा कर रहे हैं.

सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने की जरूरत को उन्होंने तो रेखांकित किया ही है, निजी क्षेत्र में भी इसे लागू करने की मांग कर दी है. उन्होंने शराबबंदी के लिए देशव्यापी अभियान के लिए प्रयास करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है, और अब उनका सबसे ताज़ा एजेंडा है 'आरएसएस मुक्त भारत'. जद(यू) सुप्रीमो की इस राजनीतिक रणनीति का कांग्रेस और वमपंथी सहित प्रायः उन सभी पार्टियों ने स्वागत किया है जो भाजपा विरोधी हैं. उन राजनीतिक समूहों की भी सहानुभूति इस अभियान के साथ दिखती हैं जो भाजपा की विरोधी हों या न हों, नरेन्द्र मोदी के विरोध में हैं. लेकिन नीतीश कुमार का यह अभियान किस हद तक उड़ान लेता है, अभी यह कहना कठिन है. इसे लेकर महागठबंधन के दलों में भी मिश्रित भाव ही हैं.

राजनीति को यह नई छलांग देने के लिए नीतीश कुमार के पक्ष में कई सकारात्मक बातें हैं. केन्द्र में वर्षों तक मंत्री और दस साल से अधिक समय से बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे इस समाजवादी राजनेता की छवि बेदाग तो है ही, उनकी पहचान बेहतर प्रशासक और विकास पुरुष की रही है. बिहार को उन्होंने अंधेरी सुरंग से निकाल कर आशा और विश्वास की डगर पर लाकर खड़ा किया है. यह राजनीतिक हलके में उन्हें गंभीरता प्रदान करता है. बिहार विधानसभा चुनावों में नरेन्द्र मोदी को शिकस्त देने के बाद वह बड़े लड़ैया के तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में पहचाने जाने लगे हैं. बिहार में लालू प्रसाद को साध कर आगे बढ़ रहे हैं, सरकार चला रहे हैं. पिछले दस वर्षों में उन्होंने महिला-अतिपिछड़ा-महादलित का व्यापक वोट बैंक तैयार करने की कोशिश की है. अर्थात नीतीश कुमार हिन्दी पट्टी के उन गैर-कांग्रेसी और गैरभाजपाई नेताओं में शीर्ष पर हैं जिनका राजनीतिक आधार जाति और धर्म से बाहर है.

हालांकि भाजपा विरोधी राजनीति में सबसे बड़ी और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस है, पर गैर कांग्रेसी दलों में नीतीश कुमार की स्वीकार्यता हिन्दी पट्टी और पूर्वी भारत में किसी कांग्रेसी नेता से भी अधिक है. तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी, बीजद सुप्रीमो नवीन पटनायक जैसे नेताओं का साथ हासिल करने की राजनीतिक क्षमता उनमें है. वामपंथी दल भी उनके साथ आ सकते हैं. इसके अलावा तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडु, शिरोमणि अकाली दल के प्रकाशसिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल, तमिलनाडु की द्रमुक और अन्ना-द्रमुक, कर्नाटक के जनता दल (एस) आदि को जरूरत पड़ने पर साथ लाने की कोशिश रंग ला सकती है. ये सारी खासियत नीतीश कुमार को राष्ट्रीय फलक के बड़े राजनेता की हैसियत देते हैं. जद(यू) के प्रवक्ता और सीनियर विधान पार्षद नीरज कुमार ने कहा है कि 'संघ मुक्त भारत' के आह्वान को सफल तो होना ही है. एनडीए विरोधी दल तो इस अभियान में शामिल होंगे ही, एनडीए में शामिल दल भी पीछे नहीं रहेंगे. जद(यू) नेताओं की यह आशावादिता साकार हो रही है क्या? इस प्रश्न का उत्तर देना अभी कठिन है.

नीतीश कुमार एक बात बार-बार कहते है, 'सरकार चलाने में किसी का कोई दबाव मेरे ऊपर नहीं है.' ऐसी ही बात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद दूसरे तरीके से बोलते है, 'सरकार को कहीं से कोई खतरा नहीं है.' यह अपना कार्यकाल पूरा करेगी. महागठबंधन में सबसे बड़ा दल राजद है और उसके 80 विधायक हैं जबकि सबसे छोटा दल कांग्रेस है जिसके विधायकों की संख्या 27 है. नीतीश कुमार के जद(यू) के 71 विधायक हैं. सूबे में सत्ता समीकरण बनाने-बिगाड़ने में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं बनती है, लिहाजा दोनों बड़ी पार्टियां इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं समझतीं. कांग्रेस की उपयोगिता राष्ट्रीय राजनीति में इन दोनों दलों को एक छतरी से अधिक कुछ नहीं दिखती है. लालू प्रसाद और उनके राजद का बिहार के बाहर कोई संसदीय और राजनीतिक वजूद नहीं है, भले संगठन देश भर में हो. जद(यू) की भी यही हालत है. बिहार के बाहर उसके नेता तो दिखते हैं, कहीं-कहीं संगठन भी दिखता है, पर वक़्त कहीं नहीं दिखती. ऐसे हालात में बिहार के किले को किसी भी सूरत में बचाना दोनों की राजनीतिक विवशता है. नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता के कारण मुशासक और विकास पुरुष का तमगा मिला है. इसी रन-वे से उनकी राजनीति नई उड़ान ले रही है. इसी तरह, कोई एक दशक बाद लालू प्रसाद के परिवार का राजनीतिक पुर्नवास हुआ है. सो, सरकार को अबाध चलाना ही नहीं, कामकाजी और परिणाम-उन्मुखी बनाना दोनों की मजबूरी है. हालांकि मतभेद के कई अवसर आए हैं, आते रहते हैं, पर बिहारी राजनीति के दोनों भाई-लालू प्रसाद और नीतीश कुमार-बड़े हिसाब से गाड़ी खींच रहे हैं. पर, यह सिलसिला इसी तरह सहज भाव से चलता रहेगा? यह लाख टके का सवाल है. दोनों दलों के उत्साह से लबरेज कुछ नेता-कार्यकर्ताओं को अपवाद मान लें, तो अधिकांश हंस कर टाल जाते हैं. राजनीतिक पंडितों के लिए इतना ही काफी है.

बिहार से दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर ही है और बिहारी राजनीति के इन दोनों भाइयों-लालू प्रसाद और नीतीश कुमार- के बीच यह फंस गया है. यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह संबंध पर असर डाल रहा है, पर इस मसले को दोनों टालते रहना चाहते हैं. नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश में अपनी नई पारी की शुरुआत कर दी है. वह गाजीपुर में कुशवाहा समाज के आयोजन के साथ ही इसका आगाज कर चुके हैं. चौधरी अजित सिंह के राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के जद(यू) में विलय की बातचीत अंतिम दौर में बताई जा रही है. यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार की राजनीति को नया रास्ता देगा. बताते हैं कि रालोद की शर्त के अनुरूप अजित सिंह को राष्ट्रीय नेतत्व में बड़ा ओहदा मिलना तो तय है ही, उनके पुत्र जयंत चौधरी को उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार के दल (जो अभी बनना है) की ओर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित किया जाना है.

मुलायम सिंह की राजनीतिक घेराबंदी के ख्याल से अजित सिंह को ऐसा तवज्जो दिया जाना लालू प्रसाद और उनके परिवार को रास नहीं आ रहा है. फिर, पीस पार्टी के साथ उनके चुनावी तालमेल का मसला है. यह बातचीत नीतीश कुमार खुद बातचीत कर रहे हैं. हालांकि लालू प्रसाद फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं, वे किसी ओर की खातिर अपनी और परिवार की परेशानी बढ़ाना नहीं चाहते. लिहाजा खामोश हैं. नीतीश-लालू दोनों कह रहे हैं कि इस महागठबंधन का वजूद बिहार तक ही है. पर, यूपी कांटा बन सकता है. और कांटों के साथ पारी लंबी नहीं हो सकती है. ऐसी हालत में बिहार की राजनीति की पिच पर दोनों की परेशानी बढ़ सकती है. गैर संघवाद को घर से ही ऐसा कोई झटका मिले तो विस्मय नहीं होना चाहिए. कांग्रेस भी मामूली मसला नहीं है. वह राष्ट्रीय पार्टी है और बिहार में वह बहत ही जूनियर हैसियत में है. राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे किसी राजनीतिक अभियान में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका चाहेगी. ऐसा हो पाएगा क्या? इस सवाल का जवाब कठिन नहीं है. फिर, कांग्रेस के बगैर आरएसएस मुक्त भारत या गैर संघवाद की स्थिति को के बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ नहीं है.■

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : डॉ. साहब मेरी उम्र 62 साल की है। उठने बैठने में काफी परेशानी होती है, जोड़ों में अकड़न रहता है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। दीनानाथ सिंह, राँची

उत्तर : आप REPL निर्मित ऑर्थोविट कैप्सूल एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को सोते समय लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालीश करें काफी लाभ होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 21 वर्ष है, काम क्रीड़ा में जबरदस्त उल्लास उठता है। मगर स्पर्श मात्र से ही स्खलित हो जाता हूँ। अंग भी छोटी है-मैं क्या करूं? प्रभात, औरंगाबाद

उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें और विगोरा ऑयल से मालिश करें, निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 32 वर्ष है कुछ दिनों से शिघ्रपतन से परेशान हूँ और एक बार सम्बन्ध स्थापित करने के बाद दोबारा मन नहीं करता और आलस्य बना रहता है। अरूण सिन्हा, नोयडा

उत्तर : आप REPL निर्मित विगोरा 5000 दिन में 3 बार) कप पानी में लें और विगोरा ऑयल से अंग पर मालिस करें। आपकी परेशानी दूर हो जायेगी।

प्रश्न : मैं 42 वर्षीय दो बच्चों का पिता हूँ मेरी समस्या यह है कि मुझे पत्नी से सहवास की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो मुश्किल से 15 सेकेन्ड के लिए। मैं क्या करूं? शंकर तिवारी, गुरगांव

उत्तर : बढ़ती उम्र में अक्सर ऐसा होता है। तनाव, भागदौड़ एवं किशोरावस्था की गलती बहुत से कारण हो सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप विगोरा हाई पावर का 90 दिन का कोर्स करें एवं हाई पावर मुसली ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें। निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : उम्र 64 वर्ष है। संभोग की तिव्र इच्छा होती है मगर शिश्न में कोई हरकत नहीं होती है। इसलिए मन मारकर रह जाता हूँ। सुनील मेहरा वर्धमान

उत्तर : इस उम्र में ऐसा होता है। आप विगोरा 5 X का 5 शीशी का कोर्स करें और साण्डह ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें।

प्रश्न : डॉ. साहब मैने टी.वी. पर विज्ञापन देखकर वासनोउत्पति के लिए एक हलवा तरह की दवा मंगवाया उस दवा से फायदा तो कुछ नहीं हुआ उलटा पूरी रात सिर दर्द से छटपटाता रहा। कोई आर्युवेदिक और हानिरहित दवा बताएं। ईश्वरी राय, गाजियाबाद

उत्तर : ईश्वरी जी, कुछ दवा निर्माता बड़े-बड़े विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने भ्रम जाल में फंसाते हैं और अपने दवा में सिर्फ सिल्डेनाफी मिलाकर बेचते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। मेरे सुझाव से आप REPL निर्मित सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आर्युवेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफैक्ट नहीं है।

प्रश्न : मैं 24 वर्षीया एक अविवाहित युवती हूँ मेरे स्तनों का विकास अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। जिससे मैं काफी परेशान रहती हू, आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करायेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा।

उत्तर : स्तनों का का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दे एवं REPL का Breastrim Oil स्तनों पर सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से स्तन में उभार आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आयेंगी।

प्रश्न : मैं 36 वर्षीय विवाहित स्त्री हूँ पिछले एक वर्ष से पानी गिरने की समस्या है और मेरी जननांग भी काफी ढीली हो गई है। कोई हानिरहित उपचार बतायें। आभा दिल्ली।

उत्तर : आभा जी आप विगोरा 1000 दिन में 2 बार 15-15 बूँद आधा कप पानी मिलाकर पियें और Virgin Oil का अंरुनी हिस्से पर लगाएं। यह बिल्कूल ही हानिरहित दवा है।

प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरूष हूँ। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्त आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है एवं सहवास की भी इच्छा नहीं होती है। कोई आयुर्वेदिक दवा बतायें। शम्भु सिंह, देहरादून

उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।

चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें :
REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला
फेडरल, पटना - 801505

Contact : 9304792851,9386880107 & 0612-2251189, (10 AM to 5 PM)
E-mail : customercare@replpharma.com, Visit us at : replpharma.com

डिस्ट्रीब्यूटर: दिल्ली/हरियाणा/पंजाब : निशा मेडिकोज 8860206755, 9988532909, जयपुर: आर.के. डिस्ट्रीब्यूटर 0141-2315071, उत्तर प्रदेश-कानपुर : खरया मेडिकल एजेंसी 0512-2372347, 9415127822, मुगलसराय: प्रकाश होमियो स्टोर 253078, मध्य प्रदेश-जबलपुर : मनीष फार्मा 0761-4004863, 9425157379, छत्तीसगढ़-भिलाई : सिंह होमियो हॉल 0788-403828, 9302839666, रायपुर : जर्मन होमियो 0771 4095630, बिहार: मॉर्डन डिस्ट्रीब्यूटर 9304018193, नॉर्थईस्ट आसाम- मोरिक होमियो रेमेडिज 03672 225340, 09435061793, पश्चिम बंगाल : एम एस ट्रेडर्स 9903175579, देव मार्कटिंग 033-30221018, सिलिगुड़ी : कलकत्ता होमियो 9593313011, झारखंड: सिंघानियां डिस्ट्रीब्यूटर 9431164318, उड़ीसा-भुवनेश्वर डायनेमिक होमियो हॉल 9437110810 कर्नाटक -बिजापुर 9341610592 गुलबर्ग:9343834519

दैनिक दिनचर्या को सुधारना जरूरी

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

Dr. Rajiv Kr. Ray M.S. (Ortho)
ऑर्थोकेयर हॉस्पिटल, मदन जी का हाता, पकरी, आरा

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.

A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil

Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus

Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg

Acoba Syp.
Methylcobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

समस्या यदि है तो किसी अच्छे ऑर्थो डॉक्टर से सम्पर्क करें ■ भारती

नवीन सचिवालय भवन के निर्माण में मजदूरों से अमानवीय बर्ताव

सत्ता प्रतिष्ठान ही कर रहा मजदूरों की दुर्गत

सूफी यायावर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट निर्माणाधीन नवीन सचिवालय भवन मजदूरों की मौत का सबब बनता जा रहा है. अखिलेश के एक और ड्रीम प्रोजेक्ट मेट्रो रेल के साथ भी ऐसा ही हादसा पेश आया जो अभी कुछ ही दिनों पहले पश्चिम बंगाल में घटित हुआ था. गनीमत यह रही कि लखनऊ में मेट्रो की शटरिंग गिरने से एक मजदूर की मौत हुई और कुछ लोग जख्मी हुए, जबकि कोलकाता हादसे में दर्जनों लोग मारे गए. लखनऊ में विधानसभा के ठीक सामने उत्तर प्रदेश निर्माण निगम द्वारा मजदूरों की जिंदगी को खतरे में डालकर नवीन सचिवालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है. यूपी वर्कर्स फ्रंट के प्रतिनिधियों ने मौके पर जाकर जो दृश्य देखा, वह भयावह है. फ्रंट ने इस बारे में मुख्यमंत्री को भी पत्र लिख कर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है.

फ्रंट की जांच टीम ने मौके पर पाया कि नवीन सचिवालय भवन के निर्माण में श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. निर्माण मजदूरों की जिंदगी दांव पर लगी है. जांच टीम को बाराबंकी के एक मजदूर ने ही बताया कि यदि कोई मजदूर मर जाए तो उसकी लाश का भी पता नहीं चलेगा. अगर लाश मिल भी गई तो ठेकेदार उसे अपना मजदूर मानने से ही इंकार कर देगा. जांच टीम में यूपी वर्कर्स फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनकर कपूर, निर्माण मजदूर मोर्चा के जिलाध्यक्ष बाबूराम कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष राम सुदर निषाद और केश चंद मिश्रा शामिल थे. मौके की स्थिति और मजदूरों से बातचीत के बाद फ्रंट ने आधिकारिक तौर पर कहा कि नवीन सचिवालय के निर्माण में भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम-1996 और उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम-2009 के प्रावधानों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.

निर्माणाधीन भवन में मिर्जापुर की अहरौरा घाटी से आए उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिन पत्थरों को पूर्ववर्ती मायावती की सरकार ने पार्कों और स्मारकों में लगवाया था. इन पत्थरों की कटिंग, उन पर नक्काशी करने और उन्हें लगाने का काम राजस्थान के मजदूर कर रहे थे. इन पत्थरों की कटिंग और नक्काशी के काम में भारी धूल उड़ रही थी, पर किसी भी मजदूर के पास मास्क नहीं था. पूछने पर राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले मजदूरों ने जांच टीम को बताया कि धूल-गर्द से बचने के लिए उन्हें गुड़ और मास्क नहीं दिया जाता. इस धूल के कारण कई मजदूरों के फेफड़े छलनी हो जाते हैं और उन्हें टीबी जैसी बीमारियां हो रही हैं. टाइल्स और पत्थर कटिंग का काम करने वाले मजदूरों के लिए तिरपाल का शेड तक नहीं लगवाने के कारण मजदूरों को इस भीषण गर्मी में धूप में काम करना पड़ रहा है. मजदूरों को सेफ्टी बेल्ट भी उपलब्ध नहीं कराया गया है. सेफ्टी बेल्ट और जाल का सही उपयोग कराने के लिए लगातार निरीक्षण करने का सरकारी

नियम इस जगह बेमानी है. जांच टीम ने देखा कि सबसे ऊपरी मंजिल पर काम कर रहे मजदूरों ने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया हुआ था और बेहद अव्यवस्थित और फटे हुए जाल लगे हुए थे. जबकि दो माह पूर्व इसी बिल्डिंग से गिरकर दो मजदूरों की मौत हो चुकी है. एसी फिटिंग का काम कर रहे रायबरेली के मजदूरों ने जांच टीम को बताया कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है. न्यूनतम मजदूरी नहीं दिए जाने की शिकायत शटरिंग से लेकर हर जगह काम करने वाले मजदूरों ने की. यह भी पाया गया कि निर्माणाधीन भवन में मजदूरों से 12 घंटे काम कराया जा रहा है, लेकिन आठ घंटे काम के 250 रुपये और शेष चार घंटे काम के सिंगल ओवरटाइम के हिसाब से 125 रुपये ही मिलते हैं. जबकि उत्तर प्रदेश में अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 273 रुपये, अर्ध-कुशल मजदूर की 300 रुपये और कुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 350 रुपये है. किसी भी मजदूर से आठ घंटे से अधिक काम कराने पर यूपी भवन एवं सन्निर्माण नियम-2009 की धारा-39 के तहत मजदूरी के दुगने की दर से भुगतान करना होगा. बोनस, ईपीएफ, वेतन किताब, रोजगार कार्ड तो किसी भी मजदूर को नहीं मिलता है. यहां तक कि टीम ने पाया कि कई मजदूरों का अभी भी कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है. मजदूरों के लिए कानून और नियम के तहत बने कोई भी कल्याणकारी प्रावधान यहां लागू नहीं हैं. जांच टीम ने पाया कि मजदूरों के लिए साफ पेयजल तक की व्यवस्था नहीं है. मजदूरों ने बताया कि पानी के कुछ पाइप लगे हैं, पर उनमें भी कभी-कभी तीन-तीन दिन तक पानी नहीं आता. वहां बने हुए शौचालय खराब पड़े हुए पाए गए. प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं थी. जबकि कानून के अनुसार ऐसे निर्माणस्थल पर बकायदा एम्बुलेंस और डाक्टरों की व्यवस्था रहनी चाहिए. मजदूरों के स्वास्थ्य के नियमित परीक्षण के बारे में पूछने पर मजदूरों ने बताया कि ऐसा कोई परीक्षण नहीं कराया जाता. कुछ मजदूरों के लिए जो अस्थायी आवास की व्यवस्था की गई है उनकी हालत बेहद खराब है. श्रम विभाग ने घोषणा की थी कि यहां काम करने वाले मजदूरों को 10 रुपये में खाना उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन इसके बारे में मजदूरों ने बताया कि शुरुआत में तीन दिन सस्ता खाना आया पर उसके बाद बंद हो गया.

फ्रंट ने मजदूरों के साथ हो रहे ऐसे अमानुषिक बर्ताव की तीखी निंदा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन देकर यह बताने में लगी है कि वह मजदूरों के हित की बड़ी योजनाएं चला रही है, लेकिन सत्ता के ठीक नीचे मजदूरों की जिंदगी दांव पर चढ़ी हुई है. फ्रंट के नेताओं ने लखनऊ के उप-श्रमायुक्त से मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया और भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम-1996 और यूपी भवन एवं सन्निर्माण (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम-2009 के प्रावधानों को सख्ती से लागू कराने की मांग की. उप-श्रमायुक्त को मजदूरों की दुर्दशा की विस्तृत रिपोर्ट भी दी गई. ■

feedback@chauthiduniya.com

लोगों की मौत का सबब बन रहा लखनऊ मेट्रो

राजधानी लखनऊ में लखनऊ मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन कभी पुल का पूरा मलबा गिर जा रहा है तो कभी पुल ही धराशाई हो जा रहा है. इससे मेट्रो केकाम की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं. निर्माणाधीन लखनऊ मेट्रो का एक पुल आलमबाग के पास पिछली 17 अप्रैल को धराशाई हो गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई. हादसे में कम से कम दर्जनभर मजदूरों और आम लोगों को गंभीर चोटें आईं. दुर्घटना का दिन अगर रविवार नहीं होकर कोई अन्य काम-काज वाला दिन होता तो यह बड़े हादसे की शक्ल ले लेता. घटना के पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन सरकार का अपना अंदाज है, वह वजहों का पता लगाएगी और इस क्रम में असली वजह खा जाएगी. घटना के बाद तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और हादसे का जायजा लिया, उन्हें भी कारण समझ में आ गया, उनमें से कई अधिकारियों को तो कारण के बारे में पहले से पता है. लेकिन सरकारी औपचारिकता भी तो कोई चीज होती है. इससे पहले भी सरोजनीनगर के पास दो अप्रैल को मेट्रो की छत गिर गई थी, जिसमें कार के ऊपर छत का कच्चा मसाला गिर गया था. उसमें कोई घायल तो नहीं हुआ था, लेकिन एक कार बर्बाद हो गई थी. कुछ अर्सा पहले भी कृष्णानगर क्षेत्र में मेट्रो ट्रैक के पिलर से डम्पर टकरा गया था. बेकाबू डम्पर की जोरदार टक्कर से पिलर का ढांचा एक तरफ झुक गया था. हादसे में कोई मेट्रो कर्मी घायल नहीं हुआ था, लेकिन पूरे पिलर को फिर से बनाना पड़ा. ■

नौकरशाहों और जन प्रतिनिधियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराने का मामला

अदालत के आदेश पर सरकार की कुंडली

दीनबंधु कबीर

सभी जन प्रतिनिधियों और नौकरशाहों के बच्चों की सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अनिवार्य किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश में कोई अमल नहीं हुआ. नेताओं और नौकरशाहों ने हाईकोर्ट के आदेश को ताक पर रख दिया है. इसे फिर से सक्रिय करने और अदालत के आदेश के कार्यान्वयन पर जोर देने के इरादे से राजधानी लखनऊ में नायाब पहल हुई है. फ्यूचर ऑफ इंडिया मंच ने इस मुद्दे को जाग्रत करने की पहल की और मंच के मजहर आजाद ने गांधी प्रतिमा पर बेमियादी अनशन शुरू की.

उल्लेखनीय है कि 18 अगस्त 2015 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका (संख्या 57476) व अन्य के संदर्भ में आदेश दिया था कि छह माह के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि सभी सरकारी तनख्वाह पाने वाले लोगों व जन प्रतिनिधियों के बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला सुनिश्चित हो. यह भी कहा गया था कि उपर्युक्त व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2016-17 से लागू हो जानी चाहिए. हाईकोर्ट के इस आदेश पर कार्यान्वयन के बारे में प्रदेश के मुख्य सचिव से आरटीआई के जरिए सूचना मांगी गई तो नकारात्मक जवाब मिला.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि नेता-अफसर और सरकारी खजाने से वेतन या मानदेय पाने वाले हर व्यक्ति के बच्चे को सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य करें. ऐसा न करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया जाए. कोर्ट ने इसे अगले सत्र से ही लागू करने का निर्देश दिया था, साथ ही कहा था कि जिन नौकरशाहों और नेताओं के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ें, वहां की फीस के बराबर रकम उनके वेतन से काटे जाएं. साथ ही ऐसे लोगों का इंक्रिमेंट और प्रमोशन भी कुछ समय के लिए रोकने की व्यवस्था की जाए. हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि जबतक इन लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, वहां के हालात नहीं सुधरेंगे. इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने जूनियर हाईस्कूलों में गणित व विज्ञान के सहायक अध्यापकों की चयन प्रक्रिया पर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया था. याचिकाओं में सरकारी स्कूलों की दुर्दशा सामने आने पर यह फैसला सुनाया गया.

हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले की बुनियाद में कोर्ट को मिली वह जानकारियां थीं, जिसे सुनकर अदालत खुद हैरत में थी. सुनवाई के दौरान अदालत को जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश के एक लाख 40 हजार जूनियर व सीनियर बेसिक स्कूलों में अध्यापकों के दो लाख 70 हजार पद रिक्त हैं. सैकड़ों स्कूलों में पानी, शौचालय, बैठने की व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है तो कई स्कूलों में छत ही नहीं है. सरकार, नेता व अफसर इस बदहाली के बावजूद बेसिक शिक्षा के प्रति संजीदा नहीं हैं क्योंकि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं बल्कि कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश में तीन तरह की शिक्षा व्यवस्था है, अंग्रेजी माध्यम के कॉन्वेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल और बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित स्कूल. आजादी के 68 साल बीत जाने के बावजूद सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं. ऐसा अफसरों, नेताओं, न्यायिक अधिकारियों के बच्चों का सरकारी स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य न होने के कारण है. इसी कारण वहां न योग्य अध्यापक हैं और न मूलभूत सुविधाएं. सरकारी खजाने से वेतन व सुविधाएं हासिल करने वालों के बच्चे जब तक सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तब

तक इन स्कूलों की हालत में सुधार नहीं होगा.

सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) इस मुद्दे पर लगातार संघर्ष कर रही है. मैगसेसे पुरस्कार विजेता व प्रमुख समाजसेवी संदीप पांडेय ने कहा कि संविधान में किसी भारतीय नागरिक को यह छूट नहीं कि वह जहां चाहे वहां अपने बच्चे को पढ़ाए. सरकार इसके लिए नीति तय कर सरकारी तनख्वाह पाने वाले व जन प्रतिनिधियों के बच्चों के लिए सरकारी विद्यालयों में पढ़ना अनिवार्य कर सकती है. जब हम किसी सड़क के किनारे दुकान पर कुछ खा रहे होते हैं अथवा चाय की दुकान पर चाय पी रहे होते हैं तो हमें कई बार यह अहसास ही नहीं होता कि जो हाथ हमें खिला-पिला रहे हैं उन हाथों में असल में पेंसिल-किताब होनी चाहिए. इन बच्चों को जिन्हें आम तौर पर छोटू कह कर सम्बोधित किया जाता है का हम कई बार नाम भी पूछने की जरूरत नहीं समझते. इनमें से कुछ हमें साइकिल-मोटरसाइकिल की मरम्मत की दुकानों पर मिल जाएंगे. कुछ पटाखे, शीशे व बुनाई के कारखानों में मिलेंगे तो कई घरों में काम करते हुए मिल जाएंगे. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24, 21-ए व 45 बाल दासता को रोकने के लिए पर्याप्त होने चाहिए थे. अब तो कई कानून भी बन गए हैं. कारखाना अधिनियम-1948, खदान अधिनियम-1952, बाल मजदूर (प्रतिबंध एवं नियंत्रण) अधिनियम-1986, नाबालिग बच्चों को न्याय (संरक्षा एवं सुरक्षा)- 2000 व मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 जैसे कानूनों का क्रियान्वयन ईमानदारी से हो जाता तो काम करते हुए बच्चे कहीं दिखाई नहीं पड़ते. इन कानूनों के होते हुए भी बाल मजदूरी धड़ल्ले से चल रही है. इसका मतलब है कि न तो सरकार उपर्युक्त कानूनों के क्रियान्वयन के प्रति गम्भीर है और न ही नागरिकों को बाल मजदूरी से कोई दिक्कत है. कभी बच्चे के परिवार की मजबूरी बता कर या शिक्षा की बच्चे की जिंदगी में निरर्थकता बता हम किसी न किसी तर्क से बाल मजदूरी को जायज ठहरा देते हैं.

दुनिया के सभी विकसित देशों व कई विकासशील देशों ने भी 99-100 प्रतिशत साक्षरता की दर हासिल कर ली है. भारत में आधे बच्चे विद्यालय स्तर की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते. इसमें से आधे बाल मजदूरी के शिकार हैं. जिन देशों ने 99-100 प्रतिशत साक्षरता की दर हासिल की है, उन्होंने अपने यहां समान शिक्षा प्रणाली लागू की है. इसका मतलब यह है कि सभी बच्चों को लगभग एक गुणवत्ता वाली शिक्षा हासिल करने के अवसर उपलब्ध हैं. भारत में 1968 में कोठारी आयोग ने समान शिक्षा प्रणाली एवं पड़ोस के विद्यालय की अवधारणा को लागू करने की सिफारिश की थी, लेकिन तब से लेकर अब तक सभी सरकारों ने उसे नजरअंदाज किया है. 2009 में (मुफ्त एवं अनिवार्य) शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ जिसने गरीब परिवारों के बच्चों को सभी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की, लेकिन इस प्रावधान को लागू करने में सरकारें गम्भीर नहीं हैं.

भारत में अब दो तरह की शिक्षा व्यवस्थाएं हैं - एक पैसे वालों के लिए जो अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाते हैं तो दूसरी गरीब लोगों के लिए जो अपने बच्चे सरकारी विद्यालय में भेजने के लिए अभिशप्त हैं, जहां पढ़ाई ही नहीं होती. इस तरह भारत में शिक्षा अमीर व गरीब के बीच दूरी को और बढ़ा देती है. यदि भारत में सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होनी है तो सिवाए समान शिक्षा प्रणाली को लागू करने के और कोई उपाए नहीं है. सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता सुधारने का सबसे सीधा और एकमात्र तरीका यही है कि सभी सरकारी वेतन पाने वालों व जन प्रतिनिधियों के बच्चों के लिए सरकारी विद्यालयों में पढ़ना अनिवार्य किया जाए. यदि सरकार और प्रशासन में बैठे लोग सरकारी विद्यालयों को अपना नहीं मानेंगे तो भला और कौन मानेगा? जब सरकारी अधिकारियों ने घाटे में चलने वाली एअर इंडिया को यह नियम बना कर जिंदा रखा है कि सरकारी काम से यात्रा करने वाले लोगों को एअर इंडिया से ही यात्रा करनी होगी तो सरकारी विद्यालयों को जिंदा रखने के लिए वे अपने बच्चों को इन विद्यालयों में भेजने का नियम क्यों नहीं बना सकते? ■

वायुसेना की महिला अफसर ने बचाई तीन जख्मियों की जान

चौथी दुनिया ब्यूरो

भारतीय वायु सेना की महिला अधिकारी फ्लाइंग अफसर नेहा गुरनानि ने अपने धैर्य एवं साहस का परिचय देते हुए सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल तीन नागरिकों की जान बचा कर मानवीयता और प्रतिबद्धता का नायाब परिचय दिया. पिछले दिनों मोटर साइकिल पर सवार तीन लोग खटोला गांव के रहने वाले विनोद, सर्वेश और किशन मेमोरा वायु सेना स्टेशन के पास राजमार्ग पर गंभीर रूप से जख्मी हालत में पड़े थे. फ्लाइंग अफसर नेहा गुरनानी उसी समय वहां से गुजर रही थीं. उन्होंने आस-पास मौजूद लोगों और वहां से गुजर रहे वाहन चालकों से भी उनकी मदद के लिए आगे आने की गुहार लगाई, लेकिन कोई नहीं रुका. फ्लाइंग अफसर ने पास ही खड़े स्कार्पियो गाड़ी के मालिक को मदद करने के लिए मनाया और उसी वाहन से घायलों को लेकर वायु सेना स्टेशन मेमोरा के अस्पताल पहुंचीं. वहां मौजूद वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट मितुल सिंह ने तत्काल प्राथमिक चिकित्सा शुरू की. सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण घायल सर्वेश का रक्तचाप लगातार कम हो रहा था और उसकी नाड़ी का स्पंदन भी काफी धीमा था. फिर भी चिकित्सक ने अपना काम जारी रखा और आखिरकार घायलों की जान बचाने में कामयाबी हासिल की. घायलों की स्थिति में सुधार होने पर तीनों घायलों को वायुसेना के एम्बुलेंस से ही लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया. इस दौरान रास्ते में एक मरीज को दो बार दौरा पड़ने पर सेना चिकित्सक द्वारा सीपीआर प्रणाली के जरिए उन्हें दोबारा होश में लाया गया. सेना के प्रवक्ता ने बताया कि फ्लाइंग अफसर नेहा गुरनानी द्वारा धैर्य और साहस से की गई त्वरित कार्रवाई एवं फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट डॉक्टर मितुल सिंह द्वारा उपलब्ध कराई गए त्वरित चिकित्सा से तीनों घायलों की जिंदगी बचाई जा सकी. ■

फ्लाइंग अफसर नेहा गुरनानी

feedback@chauthiduniya.com

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती पर मुलायम ने साधे कई सियासी लक्ष्य

फिर समाजवादियों को एक करने की चाहत

चौथी दुनिया ब्यूरो

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती के जरिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने अपने कई राजनीतिक हित साधे, साथ ही विरोधियों पर भी कई लक्ष्य साधे. मुलायम ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के सांसद को तोड़ कर चंद्रशेखर की सरकार बनवाई थी. टूटने वाले कांग्रेस सांसद थे संजय सिंह. अभी कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनाव में संजय सिंह को तुरुप का पत्ता बना कर इस्तेमाल करना चाहती है कि ऐन मौके पर मुलायम ने उनकी वफादारी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस नेतृत्व के मन में खटास पैदा करने का काम कर दिया. अभी हाल ही पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज भारद्वाज ने कहा था कि भ्रष्टाचार के कारण मुलायम के नेतृत्व वाली समाजवादी सरकार को यूपीए-1 के दौरान कांग्रेस बर्खास्त करना चाहती थी. मुलायम के इस बयान को हंसराज भारद्वाज के उस बयान से हुई नाराजगी से जोड़ कर देखा जा रहा है.

बहरहाल, सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि चंद्रशेखर से उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे. उन्होंने ही कांग्रेस सांसद संजय सिंह को तोड़कर चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया था. मुलायम ने कहा, जब भी मैं चंद्रशेखर जी के पास जाता था तो वह मुझे गाड़ी तक छोड़ने आते थे. एक बार कुछ लोग खड़े थे तो मैंने कहा कि चंद्रशेखर जी आपको प्रधानमंत्री बनना चाहिए. इस पर चंद्रशेखर जी के मुंह से निकला कि अगर मुलायम सिंह चाहें तो मैं 10 दिन में शपथ ले लूं. चंद्रशेखर के इतना कहने के बाद मैं गंभीर हो गया और कहा कि विचार करूंगा. फिर मैंने कांग्रेस से संजय सिंह को तोड़ा. उस समय मैं मुख्यमंत्री था पर तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मुझे कभी मुख्यमंत्री के रूप में देखा ही नहीं. धीरे-धीरे तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह से लोगों की नाराजगी बढ़ती गई और हम लोगों ने विद्रोह कर चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बना दिया. उसके बाद बात उठी कि कांग्रेस को कौन तोड़े तो मैंने राजीव गांधी से मिलकर बात की. चंद्रशेखर को समर्थन के सवाल पर वह राजीव गांधी से मिले. राजीव गांधी ने यह शर्त रखी कि मंत्रिमंडल कितना भी बड़ा हो पर कमल मोरारका को मंत्री न बनाया जाए. लेकिन चंद्रशेखर ने यह बात नहीं मानी. उन्होंने कमल मोरारका को मंत्री बनाया और मित्रता के निर्वहन के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवा दी. चंद्रशेखर जी अपने निष्ठावान साथी का अपमान नहीं होने देना चाहते थे. मुलायम ने कहा कि चंद्रशेखर साधारण घर से निकलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे. वह हमारे आदर्श हैं. हम लोगों ने वीपी सिंह से विद्रोह करके उन्हें प्रधानमंत्री बनवाया था. यदि वह कमल मोरारका को मंत्रिपरिषद से हटा देते तो कांग्रेस उनसे समर्थन वापस नहीं लेती.

मुलायम ने कहा कि जब सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी मिलकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी तब इसमें कई गुट बने लेकिन तब भी चंद्रशेखर जी ने कोई गुट नहीं बनाया. मुलायम ने चंद्रशेखर को बेमिसाल नेता बताया. मुलायम ने इसी बहाने मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि देश में दो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और चौधरी चरण सिंह ने यूपी पर ध्यान दिया, जबकि दिल्ली में बैठी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार मनमर्जियां करती है. केंद्र सरकार मनमानियां कर रही है. समाजवादी नेताओं का अब अलग-थलग रहने से काम नहीं चलेगा. सभी समाजवादियों को इकट्ठा होना पड़ेगा. मोदी के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने कहा कि बनारस में अभी तक क्या काम हुआ है? कितने घाट संवर गए हैं? प्रधानमंत्री मोदी शौचालय की बात करते हैं, जबकि हमने 1989 में ही शौचालय बनवाने शुरू कर दिए थे. मुलायम ने यूपी को संवारने के लिए चंद्रशेखर और चौधरी चरण सिंह के प्रति अपना आभार जताया. मुलायम ने यहां तक कहा कि समाजवादी पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को अपने आदर्श नेता के रूप में मानती है. मुलायम ने इस मौके पर जनता दल का भी जिक्र किया और कहा कि जनता परिवार बनने के दौरान सबने पार्टी मुखिया के रूप में सर्वसम्मति से उनके नाम की घोषणा की. पार्टी में सभी नेताओं का बराबर सम्मान है. लिहाजा सबकी राय लेने के बाद पार्टी में कोई फैसला लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सबको लेकर आगे चलना है, तभी कामयाबी मिलेगी.

चंद्रशेखर जयंती के मौके पर सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह दव ने अलग ही लाईन ली. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के साथ पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी नाम लिया और कहा कि दोनों हमारे राष्ट्रीय धरोहर हैं. शिवपाल ने यह भी कहा कि हमारे लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नहीं बल्कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का हिंदुत्व आदर्श है. शिवपाल सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर ने हमेशा जनसंघर्षों की अगुवाई की. उन्होंने आचार्य नरेन्द्र देव से समाजवाद की दीक्षा ली और जीवनपर्यंत समाजवाद और लोकतंत्र को मजबूत करते रहे. वे बुनियादी तौर पर हर तरीके के अन्याय, भ्रष्टाचार व गैर बराबरी के धुर विरोधी थे. उन्होंने सदन में पक्ष-विपक्ष से परे एक निष्पक्ष परम्परा डाली और पूरी ईमानदारी से इसे आगे बढ़ाया. वे हमेशा लोहिया की स्वदेशी विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे. न केवल भारतीय बल्कि बीपी कोइराला व शैलजा आचार्य जैसे नेपाल के समाजवादियों से भी उनके अति-मधुर संबंध रहे. अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने खाड़ी युद्ध के दौरान उपजे भुगतान संतुलन के संकट से गुजर रही भारतीय अर्थव्यवस्था को संभाला. आज चंद्रशेखर जैसे नेताओं की देश को बहुत जरूरत है. इसके पूर्व शिवपाल सिंह यादव ने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश के बुद्धिजीवियों को राधाकृष्णन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह अपने ज्ञान का प्रयोग देश और समाज के हित और समाज की विकृतियों को दूर करने के लिए किया जाए. राधाकृष्णन का हिन्दुत्व सभी को समाजिक सौहार्द के धागे से बांधता है जो हमें कबीर और स्वामी विवेकानन्द के करीब लाता है.

चंद्रशेखर की 89वीं जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 17 अप्रैल को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया. सपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के संसद में दिए भाषणों पर वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह द्वारा संकलित स्पीचेज़ इन पार्लियामेंट किताब का मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, भगवती सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं के हाथों विमोचन भी हुआ. कार्यक्रम में कावीना मंत्री अरविंद सिंह गोप, राजा भैया, राजेंद्र चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय, वरिष्ठ मंत्री अहमद हसन, बलवंत सिंह रामूवालिया, बलराम यादव, ओमप्रकाश सिंह, डॉ. मधु गुप्ता, अम्बिका चौधरी, अरिदमन सिंह, रामगोविन्द चौधरी, नारद राय, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र सांसद नीरज शेखर, एसआरएस यादव, योगेश प्रताप सिंह, राज किशोर सिंह, राम आसरे विश्वकर्मा, डॉ. अशोक बाजपेयी, अर्चना राठौर, मयंकेश्वर शरण सिंह, शंखलाल मांझी, प्रदीप तिवारी, बृजेश यादव, गीता सिंह, डॉ. राजपाल कश्यप, कुलदीप सिंह सेंगर, सरोजनी अग्रवाल, जावेद आब्दी, मूलचन्द्र चौहान, सुनील यादव समेत कई नेता मौजूद थे. कार्यक्रम की अध्यक्षता भगवती सिंह और संचालन विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह ने किया. इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार धीरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा सम्पादित पुस्तक राष्ट्रपुरुष चंद्रशेखर का भी सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने विमोचन किया. ■

feedback@chauthiduniya.com

नापाक सियासतदानों के कारण बर्बाद हो गई बुंदेलों की पावन भूमि

नेताओं ने बुंदेलखंड को लूट-लूट कर ऐसा बना दिया

इखरार पठान

न सियासत का सलीका, न बोलने की समझ, न नेतृत्व वाले गुण और न ही नमकहलाली की नियत! यही निचोड़ है बुंदेलखंड के सियासतदानों की. चुनावों में तो ये बहु-रूप धारण कर जनता को लुभाते हैं, लूटते हैं और उन्हें रोने, बिलखने को छोड़ कर निकल लेते हैं. बुंदेलखंड की राजनीतिक ज़मीन ऐसे ही तमाम लह-चूसक नेताओं से भरी पड़ी है. झांसी से लेकर चित्रकूट तक और सत्ता से लेकर विपक्ष तक हर जगह और कमोवेश हर दल में ऐसे चेहरों की भरमार है, जो मुखौटे बदल-बदल कर वर्षों से यहां की भोली-भाली जनता को छलते आए और आज मरणासन्न बुंदेलखंड में उन्हें लोगों की फिक्र नहीं. उन्हें चिंता है तो बस अपनी राजनीति को किसी तरह जिंदा करने का जुगाड़ करने की.

बुंदेलखंड की बदहाली के वैसे तो अनगिनत कारण हैं, लेकिन जो वजह सबसे अहम और बड़ी है, वह है यहां की कमजोर राजनीति और गैर जिम्मेवार नेता. सूबे के अन्दर वन एवं खनिज में अव्वल स्थान रखने के बाद भी आज यह क्षेत्र व्यापारिक तरक्की के मामले में शून्य पर है. आज यहां न कोई बड़ा उद्योग है और न ही कोई ऐसे श्रोत जिनको रोजगार के लिहाज से पर्याप्त कहा जा सके. आजादी से लेकर अब तक यहां जो तरक्की हुई उसका स्तरहीन प्रतिशत बुंदेलखंड की कमजोर राजनीति को उजागर करता है. हालत यह हो गई कि राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखने वाला बुंदेलखंड आज अपनी बदहाली और विद्रूप के लिए जाना जा रहा है. वाकई बुंदेलखंड की राजनीति ही यहां के लिए अभिशाप बन गई. चुनावी मेलों में जनता के सामने शेर की तरह गरजने वाले नेता सदन में पहुंचकर भीगी बिल्ली बन जाते हैं. आजादी से

अब तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं में से कुछ एक को यदि अलग कर दें तो रिकॉर्ड इस बात के गवाह हैं कि ज्यादातर ने अपने समूचे कार्यकाल में सदन के अंदर क्षेत्र के कल्याण के लिए मुंह तक नहीं खोला. विधानसभा हो या विधान परिषद, राज्य सभा हो या फिर देश का सर्वोच्च सदन कमोबेश हर जगह पर बुंदेलों की नुमाइंदगी करने वाले नेताओं की भूमिका शून्य ही रही है. यदि किसी अन्य माध्यमों से बुंदेलखंड को लेकर सदनों में कोई मुद्दा गर्म भी हुआ तो इन उदासीन माननीयों के ठंडे रवैये के कारण वह ठंडे बस्ते में ही दफ्न होकर रह गया.

बुंदेलखंड के इन कथित माननीयों की योग्यता को आइना दिखाते ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं जो उनकी नीयत और नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं. झांसी से वर्तमान सांसद और केंद्र सरकार में बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली जल संसाधन विकास मंत्री उमा भारती हों या फिर पूर्व की केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके प्रदीप जैन आदित्य या फिर गंगाचरन राजपूत, अशोक सिंह चंदेल, शिवकुमार पटेल, चन्द्रपाल यादव, भैरोंप्रसाद मिश्रा, राजनारायण बुधौलिया और पुष्पेन्द्र सिंह सरीखे सांसद, कमोबेश ये सभी नेता इस क्षेत्र की बदहाली के लिए जिम्मेवार हैं. समय-समय पर इस क्षेत्र से निर्वाचित होते आए केंद्र की राजनीति में सक्रिय इन सभी जन प्रतिनिधियों की जाति, ज़हनियत और ग़रीरिक बनावट में भले फर्क रहा हो पर इनकी नीयत एक जैसी ही रही है. आजादी से लेकर अब तक हुई इस क्षेत्र की भयंकर उपेक्षा केंद्रीय राजनीति के इन मठाधीशों की नीयत उजागर करने के लिए काफी है. भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती और कांग्रेस नेता प्रदीप जैन को अलग कर दें तो बाकी सारे सांसद लोकसभा की शोभा तो बढ़ाते रहे पर किसी में कुछ बोलने का माद्दा नहीं दिखा. राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो कुछ बुंदेली सांसद जहां अपने आपराधिक इतिहास को छिपाने के लिए समूचे कार्यकाल में चुप्पी साधे रहे, तो वहीं कुछ को पांच साल तक यही नहीं मालूम चला कि सदन में कैसे और कब बोला जाता है. जनता को विकास का लॉलीपाप देकर लोकसभा में पहुंचने वाले यह सांसद सदन में भले ही कुछ न कर पाए हों पर उन्होंने अपने क्षेत्र में जनता को पलीता लगाने में खूब कीर्तिमान स्थापित किया. कहीं लोगों की जमीनें हड़पीं तो कहीं गरीब जनता के विकास के लिए मिली निधि ही डकार ली.

सदन में अपनी बात न रखने और क्षेत्र के विकास को लेकर निष्क्रियता बरतने जैसे मामले में सांसदों के साथ-साथ विधायक भी पीछे नहीं रहे हैं. पिछले तीन दशक का इतिहास खंगाल कर देखें तो यहां से निर्वाचित विधायकों की असलियत स्वतः खुल जाएगी. इस समयावधि में विधायक बने अधिकांश जनप्रतिनिधियों का बस एक ही प्रयास रहा, खुद के विकास का. जिस प्रकार इनके द्वारा पेट्रोल पम्प और बड़ी-बड़ी एजेंसियां हथियाई गईं तथा जिस तरह बेशकीमती जमीनों पर कब्जा कर एवं अवैध खनन के सहारे तरक्की हासिल की गई, वह जनता के प्रति इनकी नमकहलाली साबित करने के लिए काफी है. सूबे में कांग्रेस शासन जाने के बाद तो यह लूट अपने चरम पर पहुंच गई. आंकड़े बताते हैं कि जब-जब प्रदेश में सपा और बसपा सत्ता पर काबिज हुई, इनके स्थानीय नुमाइंदों ने दिल खोलकर जनता को लूटा. उसी जनता का लहू पीया जिसने इन्हें विधानसभा तक पहुंचाया. बांदा में बसपा शासनकाल की सुर्खियां बन चुका भगवानदीन यादव भूमि विवाद रहा हो या फिर सपा के जमाने में चर्चा बटोरते झांसी जनपद के वे दो भूमाफिया माननीय जो मुख्यमंत्री के स्वजातीय भी हैं और बेहद कृपापात्र भी! बताते हैं कि यहां सपा के राज्यसभा सदस्य चंद्रपाल यादव और गरोठा के सपा विधायक दीपनारायण को बुंदेलखंड के खनन माफिया की महिमामंडित पहचान मिली हुई है. बीते दिनों सोशल मीडिया में वायरल हुआ वह ऑडियो इस कथन की पुष्टि करता है जिसमें राज्यसभा सांसद चंद्रपाल यादव गुलाब सिंह नामक अधिकारी को बालू से भरा ट्रक छोड़ देने के लिए किस तरह धमका रहे थे.

जनता के प्रति जवाबदेही से बचते और खुद की तिजोरियां भरने में यहां कोई नेता किसी से पीछे नहीं रहा है. महोबा की राजनीति में सक्रिय और कभी सपा सरकार में मंत्री पद से नवाजे गए सिद्धगोपाल साहू के बेशुमार क्रशर्स और शानदार शोरूम तथा दल बदलने के लिए प्रसिद्ध गंगाचरन राजपूत की ढेर सारी एजेंसियां इनकी नीयत को ही उजागर करती हैं. बुंदेलखंड की जनता को लूटने का जिक्र हो और नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बादशाह सिंह, दद्दू प्रसाद तथा बाबू सिंह कुशवाहा का नाम न आए यह संभव नहीं. कभी आर्थिक लिहाज से बेहद साधारण दिखने वाले इन नेताओं ने जिस तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ीं उसे शब्दों में बयान कर पाना मुमकिन नहीं है. हालांकि जिस बुंदेली जनता को छलकर ये राजनीति के शिखर पर पहुंचे उसी जनता ने इनमें से कई को हाशिए पर भी ला दिया. कभी बुंदेलखंड की राजनीति के अहम किरदार रहे कुछ नेता अब उस राजनीतिक जमीन को हासिल करने के लिए फिर नित नए ढोंग कर रहे हैं जो उन्होंने अपनी करतूतों के चलते खो दी है. ऐसे नेताओं की लिस्ट तो बहुत लम्बी है पर जो सुर्खियों में बने हैं, उनमें पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत, आशोक सिंह चंदेल पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, दद्दू प्रसाद और बादशाह सिंह प्रमुख हैं. हालांकि बाबू सिंह कुशवाहा के पास कुछ जनाधार अभी भी शेष बताया जाता है लेकिन अन्य सभी का जनाधार पोपला हो चुका है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सितारों के बायोपिक का दौर

अनंत विजय

जब फिल्म पान सिंह तोमर आई तो उसकी सफलता ने लोगों को चौंकाया था. कम लागत में बनी इस फिल्म को तारीफ तो मिली ही थी, इसने जमकर मुनाफा भी कमाया था. पान सिंह तोमर भारतीय फौज में थे और उन्होंने 1958 के टोक्यो एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. इस बायोपिक को लोगों ने पसंद किया था, क्योंकि इसमें एक फौजी के बागी बनने की कहानी थी. चंबल के रहने वाले पान सिंह ने किस तरह से बंदूक उठाई, उसको फिल्मकार ने दर्शकों के सामने परोसा था. उसके बाद तो हिंदी फिल्मों में बायोपिक का दौर चल पड़ा. 2013 में ओलंपियन मिल्खा सिंह पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग ने तो सफलता के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 109 करोड़ का बिजनेस कर डाला. मिल्खा सिंह की जिंदगी भी पान सिंह तोमर की तरह ही नाटकीय है. उसमें सफल बॉलीवुड फिल्म के सारे तत्व मौजूद हैं. भारत विभाजन के बाद हुए दंगों में मिल्खा सिंह के माता-पिता की जान चली गई थी. उसके बाद वो दिल्ली आते हैं, फिर सेना में शामिल होकर ओलंपिक गेम्स तक पहुंचते हैं. आज भी लोग मिल्खा सिंह को उड़न सिख कहते हैं, तो उनके जेहन में 1960 का ओलंपिक आता है जब पलभर से मिल्खा सिंह पदक से चूक गए थे. चार सौ मीटर की उस रेस में मिल्खा सिंह आधी दूर तक सबसे आगे थे लेकिन उसके बाद वो पिछड़ गए थे. करीब पौने छियालीस सेकेंड का उनका रिकॉर्ड भारत में चार दशकों तक कायम रहा था और कोई भी धावक उसको पार नहीं कर पाया था. एक तो भारत विभाजन का वक्त, दूसरे एक परिवार के तहस-नहस होने के बाद उसके सदस्य का उठ खड़ा होना लोगों को भा गया. इसी तरह से पिछले दिनों बॉक्सर मैरी कॉम पर प्रियंका चोपड़ा अभिनीत बायोपिक *मैरी कॉम* आई थी. प्रियंका चोपड़ा के शानदार अभिनय और उत्तर पूर्व के राज्य मणिपुर के एक छोटे से कस्बे से निकलकर मैरी कॉम पांच बार एमैच्योर बॉक्सिंग की विश्व चैंपियन रहीं. मैरी कॉम ने न केवल इचियोन एशिएन्यन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था बल्कि ओलंपिक में भी अपने मुक्के का कमाल दिखाया था. उस वक्त मैरी कॉम पूरे देश में नायिका की तरह उभरी थीं. मैरी कॉम पर बनी फिल्म भी हिट रही थी और इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक उसने 62 करोड़ का बिजनेस किया था. दरअसल होता यह है कि स्पोर्टस के सितारों के जीवन पर फिल्म बनाने के लिए बॉलीवुड के फिल्मकार और निर्देशक ज्यादा उत्साहित रहते हैं. उस उत्साह की कई वजहें हैं. सबसे बड़ी वजह है तैयार बाजार मिलता है. इस तैयार बाजार का फायदा यह होता है कि यहां मुनाफे की गुंजाइश ज्यादा रहती है. तैयार बाजार को भुनाने के लिए फिल्मकार उन खिलाड़ियों की जिंदगी की ओर आकर्षित होते हैं जिनके साथ किवदंतियां, किस्से कहानियां जुड़े हों और लोग उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हों. इसके अलावा भारतीय दर्शक कुछ अलग देखने की चाहत भी रखते हैं. अपने नायक को रूपहले पर्दे पर देखने की उनकी ख्वाहिश भी उनको सिनेमा हॉल तक खींच लाती हैं. इसके अलावा अपने नायक के जीत को भारत का दर्शक बार-बार देखना चाहता है. अगर फिल्मकार दर्शकों के इस मनोविज्ञान को पकड़कर ठीक से उसको फिल्मा देता है, तो फिल्म के सफलता की गारंटी रहती है. इसके अलावा एक और वजह होती है खिलाड़ियों की लोकप्रियता को भुनाने की, लेकिन यहां एक पेंच भी होता है. वो पेंच है लोकप्रियता के साथ या तो संघर्ष हो या फिर कोई लंबे समय तक चला विवाद. इसका फायदा यह होता है कि फिल्मकारों को और निर्देशकों को अपनी रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को दिखाने के लिए खुले आकाश जैसा विस्तार मिलता है जहां वो खुल कर खेल सकते हैं.

अब, अगर देखें तो इस वक्त तीन क्रिकटरों के अलावा एक गणितज्ञ और एक पहलवान पर बायोपिक आने वाली है. पहली फिल्म आ रही है टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर. फिल्म का नाम है अजहर. इस फिल्म में अजहरुद्दीन की भूमिका निभा रहे हैं इमरान हाशमी और यह 13 मई को रिलीज होगी. अब अगर हम अजहरुद्दीन की जिंदगी पर नजर डालते हैं, तो ये एक फिल्म की परफेक्ट स्क्रिप्ट की तरह नजर आती है. अजहर की जिंदगी जहां एक सितारे की बनने की दास्तां है, उसके बाद उसके बॉलीवुड की एक नायिका के साथ प्रेम है, विवाह है और फिर है अलगाव. कहानी यहीं पर ही नहीं रुकती है. भारतीय क्रिकेट का यह सितारा मैच फिक्सिंग के जाल में भी फंसता है. मैच फिक्सिंग की फांस में घिरे इस क्रिकेट कप्तान पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाता है फिर लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उसको हाईकोर्ट से मामूली राहत मिलती है. इस बीच वो शख्स राजनीति में आता है और सांसद बन जाता है. पारिवारिक जिंदगी में भी दर्द का सामना करना पड़ता है. इस बीच एक अन्य बैडमिंटन खिलाड़ी से उसके रोमांस की खबरें आम होती हैं, हलांकि वो प्यार परवान नहीं चढ़ता है. तो जहां जिंदगी में इतना मसाला हो वहां बॉलीवुड की नजर न जाए, संभव ही नहीं है. अजहर के बाद दूसरी फिल्म आ रही है टीम इंडिया के कैप्टन कूल महेन्द्र सिंह धोनी पर. इस फिल्म का नाम है *एम एस धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी* और यह सितंबर के पहले सप्ताह में रिलीज होने को तैयार है. इस फिल्म में धोनी के किरदार को निभाया है अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने. अब धोनी की जिंदगी में सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद के साथ-साथ उनकी कहानी लगातार किवदंती बनती जा रही है. कई बार ये किस्सा सामने आया है कि किस तरह से धोनी अपना एक क्रिकेट मैच खेलने के लिए रांची से पूर्वोत्तर के राज्य में पहुंचे थे. इसके अलावा रेलवे के टिकट चेकर की नौकरी से अरबपति होने की दास्तां अपने आप में दिलचस्प है. इसी तरह से आमिर खान की फिल्म दंगल भी हरियाणा के मशहूर पहलवान महावीर सिंह फोगट की जिंदगी पर आधारित है. यहां भी इस चरित्र के साथ किवदंतियां जुड़ी हुई हैं.

बॉलीवुड की नजर अजहर और धोनी पर तो जाती है, लेकिन उनकी नजर सचिन तेंदुलकर या फिर सुनील गावस्कर पर नहीं जाती है. ये दोनों क्रिकेटर महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं, लेकिन इनके संघर्ष में मसाला नहीं है, लिहाजा इन पर बॉलीवुड की नजर नहीं गई. हॉलीवुड के जेम्स इर्सकिन सचिन पर फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है सचिन-अ बिलियन ड्रीम्स. इस फिल्म का एक पोस्टर भी हाल ही में रिलीज किया गया है. फिल्म के पोस्टर के रिलीज के मौके पर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि कैमरे को फेस करना किसी भी फास्ट बॉलर को फास्ट पिच पर खेलने के जैसा कठिन है. खैर ये अवांतर प्रसंग है. हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की बायोपिक फिल्मों की. दरअसल यही बुनियादी फर्क है बॉलीवुड या हॉलीवुड में. बॉलीवुड में नजर होती है मसाला और मुनाफा पर जबकि हॉलीवुड कला पर भी अपना ध्यान केंद्रित करता है. हमारे देश के फिल्मकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या फिर सरदार पटेल पर फिल्म बनाने के लिए सरकार का मुंह जोहते हैं और सरकारी मदद के बाद ही इन शख्सियतों पर फिल्में बनाते हैं. यह विडंबना ही कही जाएगी कि गांधी पर अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म भारत से बाहर बनी है. रिचर्ड अटनबरो को ही गांधी में संभावना नजर आई और उन्होंने विश्व प्रसिद्ध फिल्म का निर्माण किया. गांधी पर बनी ये फिल्म 1982 में रिलीज हुई थी. बेन किंग्सले अभिनीत इस फिल्म की याद करीब तीन दशक से ज्यादा बीत जाने के बाद भी भारतीय मानस में ताजा है. *द मैन हू न्यू इनफिनिटी* के बनने की बेहद दिलचस्प दास्तां है. रॉबर्ट केनिगेल की किताब-*द मैन हू न्यू इनफिनिटी, ए लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन* को अमेपिकर स्क्रिप्ट राइटर मट ब्राउन ने ढूंढ निकाला और उस पर फिल्म बनी. पिछले साल इसका प्रीमियर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में हो चुका है. पिछले साल गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को दिखाया गया था. अब यह फर्क साफ तौर पर देखा जा सकता है. दरअसल, बॉलीवुड में फिल्म मेकिंग शुद्ध कारोबार है और फिल्म या कहानी का चयन मुनाफे को ध्यान में रखकर किया जाता है. बायोपिक अगर ज्यादा बन रहे हैं, तो इसके पीछे भी *भाग मिल्खा भाग* और *मैरी कॉम* की सफलता है. इस बात को फिल्म से जुड़े लोग स्वीकार भी करते हैं. इंतजार तो इस बात का है कि कब हमारे यहां भी असल मायने में बायोपिक बनाने वाले फिल्मकार सामने आएंगे. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

अश्वगन्धा

परिचय

सम्पूर्ण भारतवर्ष में विशेषत: शुष्क प्रदेशों में अश्वगन्धा के स्वयंजात वन्यज या कृषिजन्य पौधों 2000-2500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं. वन्यज पादपों की अपेक्षा कृषिजन्य पौधे गुणवत्ता की दृष्टि से उत्तम होते हैं, लेकिन तैलादि के लिए वन्यज पौधों का व्यवहार ही बेहतर है. यह देश-भेद से कई प्रकार की होती है, परन्तु असली अश्वगन्धा के पौधों को मसलने पर अश्व के मूत्र जैसी गंध आती है, जो इसकी ताजी जड़ में अपेक्षाकृत अधिक होती है. इसके दो प्रकार हैं-1. एक छोटी असगन्ध. इसका क्षुप छोटा होने से यह छोटी असगन्ध कहलाती है. किन्तु इसकी जड़ बड़ी होती है. नागौर (राजस्थान) में यह बहुत हुआ करती है और वहां के जलवायु के प्रभाव से यह विशेष प्रभावशाली होती है और इसीलिए इसकी नागौरी असगन्ध के नाम से प्रसिद्धि बनी हुई है. 2. दूसरी बड़ी या देशी असगन्ध है. इसका क्षुप बड़ा होता है, लेकिन जड़ें छोटी और पतली होती है. यह बाग-बगीचों, खेतों और पहाड़ी स्थानों पर सामान्य रूप में पाई जाती है. असगन्ध में वाजीकरण गुणों की प्रधानता होने से और उनकी गन्ध कुछ अश्व के मूत्र की गन्ध जैसी होने से संस्कृत में इसकी वाजी या अश्व से सम्बन्धित नाम रखे गए हैं तथा अश्वगन्धा का ही अपभ्रंश हिन्दी में असगन्ध हुआ है.

बाह्य-स्वरूप

❖ **अश्वगन्धा**-इसका 0.3-2 मीटर ऊंचा, सीधा, धूसर वर्ण का घनरोमश क्षुप होता है. इसका काण्ड शाखित, शाखाएं-गोलाकार, टेढ़ी-मेढ़ी तथा साधारणतया तारकार श्वेत रोमों से आवृत होती हैं. इसके पत्र सरल, एकांतर अथवा लगभग विपरीत, चौड़े, अण्डाकार, 5-10 सेमी लम्बे एवं 2.5-7 सेमी चौड़े तथा रोमयुक्त होते हैं. इसके पुष्प हरिताभ अथवा पीत वर्ण के होते हैं. इसके फल 6-8 मिमी व्यास के, छोटे-छोटे गोल मटर या मकोय के फल के समान पहले हरे वर्ण के चिकने और पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं. यह फल रक्त वर्ण के तनु आवरण से ढके हुए रहते हैं. इसके बीज अनेक, छोटे, पीले, वृक्काकार अथवा चक्राकार, चिकने तथा चपटे, 2.5 मिमी व्यास के होते हैं. इसकी मूल ऊपर से धूसर, भीतर से श्वेत, दृढ़ 2-3 सेमी व्यास की, 30-35 सेमी तक लम्बी, पतली, गोल, चिकनी, बेलनाकार होती है. इसका पुष्पकाल एवं फलकाल मार्च से अगस्त तक होता है.

❖ **काकनज**- इसका लगभग 1.2 मी तक ऊंचा, झाड़ीदार क्षुप होता है. इसकी पत्तियां भालाकार, हरिताभ-भूरे वर्ण की तथा घन रोमश होती है. पुष्प पीत वर्ण के तथा फल गोलाकार, लाल अथवा भूरे वर्ण के होते हैं. इसकी मूल पतली तथा छोटी होती है.

आयुर्वेदीय गुण-कर्म एवं प्रभाव

❖ अश्वगन्धा कफ वातशामक, बलकारक, बृंहण, रसायन, वाजीकरण, नाड़ी-बलकारक, दीपन, पुष्टिकारक, शुक्रकारक, धातुवर्धक व पाचक होता है.

❖ अश्वगन्धा के फल एवं बीज मूत्रल तथा निद्राकारक होते हैं.

❖ अश्वगन्धा के पत्र कटु, ज्वरहर तथा कृमिनाशक होते हैं.

❖ अश्वगन्धा की मूल मूत्रल, स्वेदक, रोग प्रतिरोधक क्षमता नियामक (Immunomodulator), तनावरोधी, प्रशामक, वाजीकारक तीक्ष्ण, तिक्त, आर्तवर्धक, श्वित्र, विबन्ध, अनिद्रा, मानसिक विकार, दौर्बल्य, श्रम, तनावजन्य विकार, जलशोफ, अजीर्ण, हिक्का संधिशूल, फुफ्फुसशोथ तथा उन्माद नाशक होती है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

शिरो रोग :

❖ **पालित्य**- 2-4 ग्राम अश्वगंधादि चूर्ण का सेवन करने से वली (बालों का असमय सफेद होना) तथा पलित रोगों में लाभ होता है.

नेत्र रोग :

❖ **नेत्र-ज्योतिवर्धनार्थ**- 2 ग्राम अश्वगन्धा चूर्ण, 2 ग्राम धात्री फल चूर्ण तथा एक ग्राम मुलेठी चूर्ण मिलाकर एक चम्मच प्रात: सायं जल के साथ सेवन करने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है.

कण्ठ रोग :

❖ **गंडमाला**- समभाग अश्वगन्धा पत्र चूर्ण तथा पुराने गुड़ को मिलाकर 1/2-1 ग्राम की वटी बनाकर, प्रात:काल बासी जल के साथ सेवन करने से तथा पत्र कल्क का गंडमाला पर लेप करने से गंडमाला में शीघ्र लाभ होता है.

वक्ष रोग :

❖ **क्षयरोग**- 2 ग्राम अश्वगन्धा चूर्ण को अश्वगन्धा के ही 20 मिली क्वाथ के साथ सेवन करने से क्षय रोग में लाभ होता है.

❖ 2 ग्राम अश्वगन्धा मूल चूर्ण में 1 ग्राम बड़ी पीपल का चूर्ण, 5 ग्राम घी और 5 ग्राम मधु मिलाकर सेवन करने से क्षय रोग में लाभ होता है.

❖ **कास (खांसी)**- अश्वगन्धा की 10 ग्राम जड़ों को कूट लें, इसमें 10 ग्राम मिश्री मिलाकर 400 मिली जल में पकाएं, जब आठवां हिस्सा रह जाए तो इसे थोड़ा-थोड़ा पिलाने से कुकुर खांसी या वात जन्य कास पर विशेष लाभ होता है.

❖ अश्वगन्धा के पत्तों के 40 मिली घन क्वाथ में 20 ग्राम बहेड़े का चूर्ण, 10 ग्राम कत्था चूर्ण, 5 ग्राम काली मिर्च तथा ढाई ग्राम सेंधानमक मिलाकर 500 मिग्रा की गोलियां बना लें. इन गोलियों को चूसने से सब प्रकार की खांसी दूर होती है. क्षयजकास में भी यह विशेष लाभदायक है.

जारी...

आचार्य बालकृष्ण

साईं वंदना

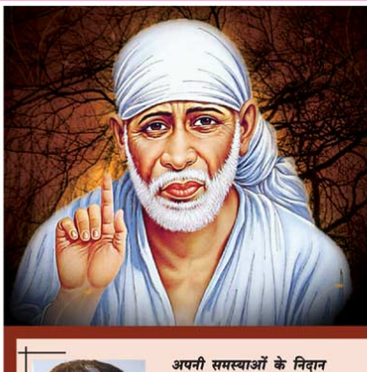

शुद्ध अंत:करण से मिले ईश्वरीय सहायता

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

अपनी समस्याओं के निदान के लिए ईश्वर की सहायता किस स्थिति में संभव है?

ईश्वर तो सदा ही अपने भक्तों की सहायता के लिए तत्पर हैं, परंतु वे भक्तों की सहायता तभी कर पाएंगे जब भक्त अपने हृदय में ईश्वर को वह स्थान दें, जिसे ग्रहण कर वे उनकी सहायता कर सकें. हृदय को नाना विकारों से ग्रस्त रखकर हम ईश्वर से यह अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वे हमारी सहायता करें.

अपनी समस्याओं के निदान के लिए अनेक प्राणी आपके पास आते हैं. यह जानते हुए भी कि उनकी समस्याएं उनके कर्म-फल का परिणाम हैं, आप उनकी सहायता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं. इस संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

मैं तो ईश्वर से केवल प्रार्थना ही करता हूं, कोई आदेश नहीं देता. ईश्वर से मेरी मात्र यही याचना होती है कि यदि दु:ख से पीड़ित भक्त पर कृपा करेंगे, तो उसके कष्ट दूर हो जाएंगे. आगे ईश्वर पर है, वे जैसा चाहें वैसा करें, जब भी कोई प्राणी ईश्वर को सच्चे मन से याद करता है, तो उस समय की भाव-दशा में वह पाप की छाया से दूर होता है. मेरा प्रयत्न सदा यही रहता है कि वह भक्त संमार्ग की दिशा में प्रेरित हो.

इस दुनिया में कोई इतना असहाय नहीं है कि वह किसी दूसरे का सहारा न बन सके. जो सद्गुरु के प्रति जीवन समर्पित कर देता है, वह स्वयं को कभी भी असहाय अनुभव नहीं करता, क्योंकि सद्गुरु किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करते हैं. जब कोई भी साथ नहीं हो, सद्गुरु अवश्य साथ चलते हैं.

रोग-निदान

असाध्य रोगों से पीड़ित कुछ रोगी मंदिर में आते हैं और बाबा की कृपा से ठीक भी हो जाते हैं. यह कैसे संभव हुआ?

यह तो बाबा की असीम कृपा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है. वे दया के सागर हैं. उनकी करुणा अपार है. मैं तो केवल यही कह सकता हूं :

अनंता तुला ते कसे रे स्तवावे.
अनंता तुला ते कसे रे नमावे.
अनंता मुखांचा शिणे शेष गातां.
नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा.

-आप अनंत हैं, मैं आपका कैसे स्तुतिगान करूं? आप अनंत हैं, मैं कैसे आपका नमन करूं? सहस्र फन वाले शेषनाग भी आपकी महिमा का गान करने में थक जाते हैं. मैं तो आपको मात्र साष्टांग प्रणाम करता हूं.

अकेलापन

आज जीवन में अकेलेपन के कारण व्यक्ति अपने को असहाय-सा अनुभव करता है. इस संबंध में आपका क्या दृष्टिकोण है?

प्रकृति का नियम है कि कोई अकेला नहीं है. कोई न कोई अवश्य साथ होता है. आत्मा शरीर को लेकर चलती है. शरीर पंचभूत को और मृत्यु के पश्चात सद्गुरु साथ चलते हैं. फिर मृत्यु से भी क्या आकुल होना? जीवन में दुख न हो तो सुख का कोई मूल्य नहीं है. इस दुनिया में कोई इतना असहाय नहीं है कि वह किसी दूसरे का सहारा न बन सके. जो सद्गुरु के प्रति जीवन समर्पित कर देता है, वह स्वयं को कभी भी असहाय अनुभव नहीं करता, क्योंकि सद्गुरु किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करते हैं. जब कोई भी साथ नहीं हो, सद्गुरु अवश्य साथ चलते हैं.

सुख-दुख से जीवन चले,
साईं-कृपा की छांव तले.

प्रिय-अप्रिय

हम सदैव आनंद प्रदान करने वाली स्थितियों की ओर ही उन्मुख होते हैं? क्या यह उचित है?

किसी स्थिति में प्रिय एवं अप्रिय के भाव के आधार पर देखने की अवधारणा भी हमारे भावों को सीमित कर देती है और सभी सीमाओं एवं अवधारणाओं से परे ईश्वर के भाव से दूर रखती है. इन दोनों प्रिय तथा अप्रिय लगने वाली अवस्थाओं की सीमाओं के पार जाकर उस असीमित एवं सार्वभौमिक की अनुभूति संभव है. जब प्रिय अप्रिय दोनों ही स्थितियों में सम रहेंगे तब जानेंगे ईश्वर क्या है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

फुटबॉल भी बनेगा ग्लैमरस!

फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी यह है कि 2017 में भारत फीफा अंडर-17 विश्वकप की मेजबानी कर रहा है. इसमें विश्व की 24 टीमें भारत में खेलती दिखाई देंगी. भारत के पास फुटबॉल की तरफ युवाओं को आकर्षित करने का यह सबसे बड़ा मौका है. यह एक ऐसा अवसर है जो नौजवानों के अंदर फुटबॉल के लिए एक नया जोश, नया उत्साह भर देगा. इस मेजबानी का एक फायदा तो है ही कि हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा. खेल के लिए जो सुविधाएं हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा. भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए नौजवानों को इससे जोड़ने की जरूरत है.

धनेंद्र सिंह

भारत में खेलों की एक नई क्रांति आई है. भारत के युवाओं के बीच क्रिकेट की तरह फुटबॉल लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है. चाहे ईपीएल हो, स्पैनिश लीग हो या फिर इंडियन सुपर लीग हो. भारतीय युवा उसे देखने के लिए क्रिकेट की तरह समय जरूर निकाल रहा है. भारत में फुटबॉल बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इंडियन प्रीमियम लीग(क्रिकेट) की तर्ज पर इंडियन सुपर लीग(आईएसएल) की शुरुआत की गई, जिसमें आठ टीमें एथलेटिको-डि-कोलकाता, चेन्नईयन एफसी, दिल्ली डायनमोज़, एफसी गोवा, केरला ब्लास्टर्स, मुंबई सिटी एफसी, नॉर्थ-ईस्ट यूनाइटेड एफसी और एफसी पुणे शामिल हैं. क्रिकेट, बॉलीवुड और व्यावसायिक जगत की कई बड़ी हस्तियों के जुड़े होने के कारण इस लीग के साथ फुटबॉल का भी खूब प्रचार होता है. आईसीएल की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कहा जा सकता है कि फुटबॉल भारत का दूसरा क्रिकेट बन सकता है. पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और एथलेटिको-डि-कोलकाता के सह मालिक सौरव गांगुली का कहना है कि भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) को बीसीसीआई से सीख लेनी चाहिए. फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी यह है कि 2017 में भारत फीफा अंडर-17 विश्वकप की मेजबानी कर रहा है. इसमें विश्व की 24 टीमें भारत में खेलती दिखाई देंगी. भारत के पास फुटबॉल की तरफ युवाओं को आकर्षित करने का यह सबसे बड़ा मौका है. यह एक ऐसा अवसर है जो नौजवानों के अंदर फुटबॉल के लिए एक नया जोश -नया उत्साह भर देगा. इस मेजबानी का एक फायदा तो है ही कि हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा. खेल के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा. भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए नौजवानों को इससे जोड़ने की जरूरत है. यह सभी चीजें हम क्रिकेट में देखते हैं, लेकिन यही चीज अन्य खेलों में भी लाने की जरूरत है. वैश्विक स्तर पर भारत की ब्रांडिंग करने के लिए यह एक सुअवसर है. साथ ही भारत की युवा शक्ति की पहचान कराने का यह सबसे बड़ा अवसर है.

भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही है. उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम में सवालिया लहजे में कहा कि इतना बड़ा अवसर जब भारत में आ रहा है, तो हम सिर्फ मेजबान बनकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे? उनका कहना है कि इस पूरे वर्ष को फुटबॉल मय बना दिया जाए. स्कूलों में, कॉलेजों में, हिन्दुस्तान के हर कोने पर हमारे नौजवान, हमारे स्कूलों के बालक पसीने से तर-ब-तर हों. चारों तरफ फुटबॉल खेला जाए. अगर हम यह करेंगे तो मेज़बानी का मज़ा आएगा इसलिए हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि फुटबॉल को गांव-गांव और गली-गली तक कैसे पहुंचाएं.

एशिया के साथ ही पूरी दुनिया में भारत फुटबॉल में कभी अच्छा प्रदर्शन करने वालों में गिना जाता था. 1951, 1962 एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और 1956 में ओलंपिक खेलों में भारत चौथे स्थान पर रहा था. लेकिन दुर्भाग्यवश भारत पिछले कुछ दशकों में बेहद निचले पायदान पर चला गया. फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय टीम 160वें पायदान पर पहुंच गई है. भारतीय टीम के पास मौजूदा समय में 142 अंक है. एशियाई देशों में ईरान 44वें स्थान के साथ शीर्ष पर है. रैंकिंग में बेल्जियम शीर्ष स्थान पर और विश्वकप उप-विजेता अर्जेंटीना दूसरे जबकि स्पेन तीसरे स्थान पर है. विश्व चैंपियन जर्मनी चौथे और पांच बार का चैंपियन ब्राजील छठे स्थान पर है.

भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए आस्ट्रेलिया की फुटबॉल स्टार अकादमी (एफएसए) भारत में फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रही है. एफएसए कोयंबटूर में सबसे पहले अपना पहला ट्रेनिंग सेंटर खोलगी. एफएसए ऑस्ट्रेलिया के कोच और व्यवसायी विकास प्रबंधक डेविड थॉमसन का कहना कि एफएसए रॉक्स पालीकूडम के साथ मिलकर ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू करेगा. जिससे खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा. अकादमी विभिन्न खेल सुविधाओं के लिए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाने में भी मदद करेगी, जिसमें उभरते हुए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे. एफएसए के 56 केंद्रों के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रत्येक सप्ताह 5000 से ज्यादा छात्रों को ट्रेनिंग मिलती है.

इसके साथ ही आस्ट्रेलिया फुटबॉल महासंघ आस्ट्रेलियाई सरकार के साथ मिलकर भारत में जमीनी स्तर पर फुटबॉल के विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित करेगा. इस कार्यक्रम का आयोजन आस्ट्रेलिया फुटबॉल महासंघ केरल में करेगा. केरल के अलावा अन्य राज्यों में इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आस्ट्रेलियाई फुटबॉल महासंघ अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और भारतीय खेल प्राधिकरण से बात कर रहा है. इस कार्यक्रम का नाम जस्ट प्ले है. आस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री जूली विशप ने कहा कि जस्ट प्ले कार्यक्रम बच्चों को समाजिक संबंध बनाने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा.उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मकसद छह से 12 साल के बच्चों को फुटबॉल का सकारात्मक अनुभव देना है.

फीफा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जियानी इनफैनटिनो आगामी वर्षों में भारत में इस खेल को बढ़ते देखना चाहते हैं. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के प्रमुख प्रफुल्ल पटेल को जियानी इनफैनटिनो के साथ अच्छे संबंध होने की उम्मीद है. वह उनके साथ देश में खेल के विकास के लिए काम करना चाहते हैं. इंडियन सुपर लीग क्लब एथलेटिको -डि -कोलकाता और स्पेन के ला-लीगा चैंपियन एटलेटिको मैड्रिड ने भारत में नई फुटबॉल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम की घोषणा की है. भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए पहले से कई अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित होते आ रहे हैं. लेकिन उसका प्रभावशाली असर जमीनी स्तर देखने को नहीं मिल रहा है. भारत के लोगों में खासकर युवाओं में फुटबॉल को लेकर उत्साह है. इसलिए इसे जमीनी स्तर बढ़ावा देने की जरूरत है. कई यूरोपियन क्लब और फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर भारतीय संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य तो करते हैं, लेकिन वह उस कार्यक्रम जारी नहीं रखते. प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि फुटबॉल को बढ़ावा देने की जरूरत है. इसलिए फुटबॉल को भी अगर क्रिकेट की तरह आगे ले जाना है और गली-मोहल्लों तक लोकप्रिय बनाना है, तो हमें सच में जमीनी स्तर पर कार्य करने होंगे.■

feedback@chauthiduniya.com

हॉकी

आसान नहीं होगी ओलंपिक पदक की राह

नवीन चौहान

भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक पदक साल 1980 में मॉस्को ओलंपिक में जीता था. 36 साल से चले आ रहे पदक के इस सूखे को दूर करने की कोशिश में भारतीय हॉकी टीम जुटी हुई है. हाल ही में मलेशिया में संपन्न हुई अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता के 25 वें संस्करण में भारतीय टीम उपविजेता रही. फाइनल मुक़ाबले में विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4-0 से हराकर रिकॉर्ड नौवीं बार अजलान शाह कप पर कब्जा किया. भारतीय टीम ने फाइनल तक का सफर सधे हुए अंदाज में पूरा किया था, लेकिन अंजाम वैसा नहीं हो सका. लीग मैचों में उसे दो मैचों मे हार का सामना करना पड़ा. मलेशिया के खिलाफ आखिरी लीग मैच में भारत के सामने करो या मरो वाली स्थिति थी. ऐसे में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और मलेशिया को 6-1 के अंतर से मात देकर फाइनल में जगह बनाई.

लंदन ओलंपिक के बाद चार सालों में भारत महज एक बार अलजान शाह कप के फाइनल में जगह बना सका, जबकि विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया चार बार फाइनल में पहुंचा और तीन बार खिताब पर कब्जा किया. पिछले साल फाइनल में न्यूजीलैंड ने उसे मात दी थी. इस साल अगस्त में ब्राजील के रियो में ओलंपिक का आयोजन होना है. आठ बार की ओलंपिक चैंपियन टीम से सवा अरब भारतीयों को पदक की आस है. लेकिन भारतीय टीम का जैसा प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में रहा है क्या उस प्रदर्शन के बल पर भारतीय टीम रियो में पोडियम तक पहुंचने में कामयाब होगी. साल 2012 में लंदन ओलंपिक से पहले भी भारतीय टीम अजलान शाह कप में कांस्य पदक जीता था. इसके बाद ओलंपिक में भारतीय टीम ने बेहद खराब प्रदर्शन किया और अंतिम पायदान पर रही. इसलिए इस बार भी पूरे निश्चय के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि टीम की तैयारियां पुख्ता हैं. हालांकि भारतीय टीम के कोच ओल्टमस अजलान शाह कप से पहले यह कह चुके हैं कि रियो ओलंपिक में भारत से स्वर्ण पदक की उम्मीद करना व्यावहारिक नहीं होगा. उनका मानना है कि उनकी टीम अभी शीर्ष 6 में जगह बनाने पर ध्यान दे रही है और इससे बेहतर प्रदर्शन बोनस होगा.

अजलान शाह कप में भारतीय टीम को फाइनल सहित कुल सात मैचों में से तीन में हार का सामना करना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लीग मैच में 5-1 से और न्यूजीलैंड ने 2-1 के अंतर से मात दी. वहीं फाइनल में भारतीय टीम को 4-0 से हार मिली. ऑस्ट्रेलिया का सामना भारतीय टीम नहीं कर सकी और उनके डिफेंस को भेद पाने में नाकामयाब रही. उनके खिलाफ दो मुक़ाबलों में महज़ एक गोल कर सकी. हालांकि पूरी प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने 18 गोल किए और गोल करने के मामले में टीम इंडिया विजेता ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पर रही. भारतीय टीम ने आक्रामक अंदाज में पाकिस्तान को 5-1 और मलेशिया को 6-1 के गोल अंतर से मात दी.

भारत ने ओलंपिक से पहले अपनी बेंच स्ट्रेंथ को परखने के लिए इस टूर्नामेंट के लिए युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के मिश्रण वाली टीम भेजी थी. स्वदेश लौटने के बाद कप्तान सरदार सिंह ने कहा कि यह उन युवाओं के लिए अच्छा अनुभव था, जो पहली बार सीनियर टीम के साथ खेल रहे थे. विशेषकर हरमनप्रीत, सुरेंद्र और हरजीत ने अपने खेल से दिखा दिया कि वे उच्च स्तर पर खेलने के लिए सक्षम हैं. ये सभी खिलाड़ी टीम में अच्छी तरह से फिट हो गए. वहीं कोच कोच रोलैंट ओल्टमस भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुश हैं. उन्होंने रजत पदक जीतने के कहा कि यह रियो ओलंपिक के लिए हमारी अच्छी तैयारी है. हमने अपनी कुछ कमियों को पहचाना है जो ऐसी प्रतियोगिताओं में साफ पता चल जाती हैं. अब हम इन कमियों पर काम कर सकते हैं ताकि ओलंपिक में अपना मजबूत प्रदर्शन सुनिश्चित कर सकें.

भले ही भारतीय टीम को एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करके ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया, लेकिन उसके लिए अभी भी यूरोपीय टीमों और ऑस्ट्रेलिया से पार पाना मुश्किल नज़र आ रहा है. भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने अधिकांश मौकों पर हथियार डाल देती है, टीम के पास उसका तोड़ नहीं है. रियो ओलंपिक में भारत को ग्रुप-बी में ओलंपिक चैंपियन जर्मनी, अर्जेंटीना, कनाडा, आयरलैंड और नीदरलैंड के साथ जगह मिली है. जबकि ग्रुप-ए में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और स्पेन हैं. दोनों ग्रुप्स से दो टॉप टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी. यदि भारतीय टीम किसी तरह सेमीफाइनल में जगह बना भी लेती है तो वहां उसका मुक़ाबला ऑस्ट्रेलिया, स्पेन या न्यूजीलैंड से होगा. इन टीमों के ख़िलाफ पिछले 4 सालों में भारतीय टीम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है. जर्मनी दो बार से ओलंपिक चैंपियन है, वहीं स्पेन ने लंदन ओलंपिक में रजत पदक हासिल किया था. लंदन ओलंपिक में भारत 12 वें स्थान पर रहा था. जबकि 2008 में ओलंपिक के लिए क्वालीफाई भी नहीं कर सका था. ऐसे में भारतीय टीम से पदक जीतने की आशा कैसे की जा सकती है. भारत के अलावा इस बार और कोई एशियाई टीम ओलंपिक के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी है, इसलिए ओलंपिक में भारत के ऊपर पूरे एशिया की नज़रें रहेंगी.

अजलान शाह कप में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, जापान और मलेशिया टीमों ने भाग लिया था. इन टीमों में से भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा ने ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया है, इनमें से केवल कनाडा के खिलाफ ही भारतीय टीम जीत हासिल कर सकी. इससे टीम की ओलंपिक की तैयारियों का अंदाजा लगाया जा सकता है. हालांकि भारतीय टीम के पास अपनी तैयारियों को आंकने का एक मौका अभी भी शेष है. लंदन में 10 से 17 जून के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है, चैंपियन्स ट्रॉफी में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ग्रेट-ब्रिटेन, बेल्जियम और दक्षिण कोरिया का सामना करना है. दक्षिण कोरिया के अलावा अन्य सभी टीमें ओलंपिक में भाग लेंगी. ऐसे में इन टीमों के खिलाफ जीत दर्ज किए बगैर ओलंपिक की तैयारियों को पुख्ता कर पाना असंभव है. ■

navinonline2003@gmail.com

फ्लैशबैक

दिलीप कुमार एक महानायक की गाथा

> दिलीप कुमार को जिन छह अन्य फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया वे हैं आज़ाद (1955), देवदास (1956), नया दौर (1957), कोहिनूर (1960), लीडर (1964) तथा राम और श्याम (1967). 1997 में उन्हें भारतीय सिनेमा को बहुमूल्य योगदान देने के लिए एनटी रामाराव अवॉर्ड दिया गया, जबकि 1998 में समाज कल्याण के क्षेत्र में योगदान के लिए रामनाथ गोयनका अवॉर्ड दिया गया.

फिल्म *मेला, शहीद, अंदाज, आन, देवदास, नया दौर, मधुमती, यहूदी, पैगाम, मुगल-ए-आज़म, गंगा-जमुना, लीडर तथा राम और श्याम* जैसी फिल्मों के नायक दिलीप कुमार अपने शुरुआत के दिनों में ही लाखों युवा दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गए थे. भारतीय उपमहाद्वीप के करोड़ों लोगों ने पर्दे पर उनके अभिनय को देखा है. इस अभिनेता ने रंगीन और रंगहीन (श्वेत-श्याम) सिनेमा के पर्दे पर अपने आपको कई रूपों में प्रस्तुत किया. असफल प्रेमी के रूप में उन्होंने विशेष ख्याति पाई, लेकिन यह भी सिद्ध किया कि हास्य भूमिकाओं में भी वे किसी से कम नहीं हैं. वे ट्रेजेडी किंग भी कहलाए और ऑलराउंडर भी. उनकी गिनती अतिसंवेदनशील कलाकारों में की जाती है, लेकिन दिल और दिमाग के सामंजस्य के साथ उन्होंने अपने व्यक्तित्व और जीवन को ढाला.

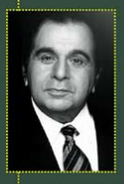

महज पच्चीस वर्ष की उम्र में ही दिलीप कुमार देश के नंबर वन अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए थे. वह शीघ्र ही राजकपूर और देव आनंद के आगमन से दिलीप-राज-देव की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति का निर्माण हुआ. तीनों नए चेहरों ने आम सिने दर्शकों का मन मोह लिया.

दिलीप कुमार प्रतिष्ठित फिल्म निर्माण संस्था बॉम्बे टॉकिज़ की उपज हैं, जहां देविका रानी ने उन्हें काम और नाम दिया. यहीं वे यूसुफ खान से दिलीप कुमार बने और उन्होंने अभिनय का गुण सीखा. अशोक कुमार और शशधर मुखर्जी ने फिल्मिस्तान की फिल्मों में लेकर दिलीप कुमार के करियर को सही दिशा में आगे बढ़ाया.

44 साल की उम्र में अभिनेत्री सायरा बानो से विवाह करने तक दिलीप कुमार ने वे सभी फिल्में की जिनके लिए आज उन्हें याद किया जाता है. बाद में दिलीप कुमार ने कभी काम और कभी विश्राम की कार्यशैली अपनाई. वैसे वे तसल्ली से काम करने के पक्षधर शुरू से थे. अपनी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता को दिलीप कुमार ने पैसा कमाने के लिए कभी नहीं भुनाया.

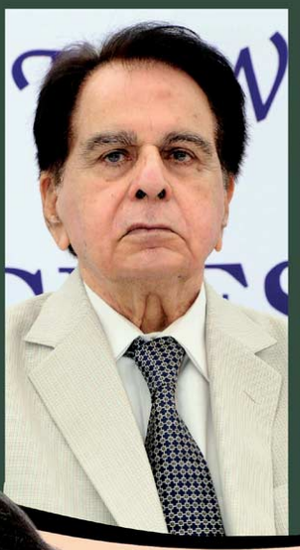

इस महानायक ने अपनी इमेज का सदैव ध्यान रखा और अभिनय स्तर को कभी गिरने नहीं दिया. इसलिए आज तक वे अभिनय के पारसमणि बने हुए हैं जबकि धूम-धड़ाके के साथ कई सुपर स्टार, मेगा स्टार आए और आकर चले गए.

दिलीप कुमार ने अभिनय के माध्यम से राष्ट्र की जो सेवा की, उसके लिए भारत सरकार ने उन्हें 1991 में पद्म भूषण की उपाधि से नवाज़ा और 1995 में राष्ट्रीय सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान किया. पाकिस्तान सरकार ने भी उन्हें 1997 में निशान-ए-इम्तियाज़ से नवाज़ा था, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है.

1953 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के शुरुआत के साथ ही दिलीप कुमार को फिल्म *दाग* के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था. अपने जीवनकाल में दिलीप कुमार कुल आठ बार फिल्म फेयर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पा चुके हैं और यह एक कीर्तिमान है जिसे अभी तक तोड़ा नहीं जा सका. अंतिम बार उन्हें वर्ष1982 में फिल्म शक्ति के लिए यह पुरस्कार दिया गया था, जबकि फिल्म फेयर ने ही उन्हें 1993 में राज कपूर की स्मृति में लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिया.

विद्या की कहानी-2

साल 2012 की सुपरहिट थ्रिलर फिल्म कहानी का सीक्वल बनना शुरू हो चुका है. इस फिल्म की शूटिंग कोलकाता में शुरू हो चुकी है. विद्या बालन इस बार भी कहानी-2 में मुख्य भूमिका निभा रही हैं. फिल्म के निर्देशक सुजॉय घोष ने सोशल मीडिया पर कहानी-2 की शूटिंग शुरू होने की ख़बर दी.

सुजॉय ने ट्विटर पर लिखा कि पहली फिल्म को सराहने और प्यार देने के लिए शुक्रिया. हम इस फिल्म में और ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि आपकी उम्मीदों पर खरे उतर सकें.

इस फिल्म में विद्या के साथ अर्जुन रामपाल भी अहम किरदार निभा रहे हैं. कहानी-2 की शूटिंग शुरू होने पर अर्जुन ने ट्विटर पर सुजॉय और कहानी-2 की टीम को शुभकामनाएं दी.

पिछले काफी समय से कहानी के सीक्वल की बात चल रही थी, मगर पिछले महीने विद्या ने कबूल किया कि वो कहानी-2 में काम कर रही हैं. अब फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि यह सीक्वल विद्या के करियर में कोई नया मोड़ लेकर आएगा, क्योंकि पिछले काफी समय से विद्या की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही हैं.

ढिशूम में जैकलिन का कूल अंदाज़

हाल ही में ढिशूम का फर्स्ट लुक जारी किया गया है. ढिशूम के फर्स्ट लुक में वरुण और जॉन एक साइड कार वाली मोटरसाइकिल में आक्रामक अंदाज़ में नज़र आ रहे हैं. यह फिल्म 29 जुलाई को रिलीज़ होगी.

बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस अपनी आने वाली फिल्म *ढिशूम* में किस अंदाज में दिखेंगी, इसकी एक झलक उन्होंने दिखला दी है. दरअसल, उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस फिल्म से अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनके हाथ में हथकड़ी नज़र आ रही है. फिर भी कैजुअल लुक में जैकलिन का अंदाज बिल्कुल कूल है.

इसे जैकलिन का फर्स्ट लुक कहा जा सकता है. उन्होंने इस तस्वीर को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, *"She wants to run but she's been chained down.. What's 'Ishika' hiding?"*

यानि इस फिल्म जैकलिन के किरदार का नाम इशिका होगा. वैसे इसमें कोई शक नहीं कि फिल्म *ढिशूम* एक्शन से भरपूर फिल्म है, जिसे वरुण धवन के भाई रोहित धवन निर्देशित कर रहे हैं. वरुण धवन भी जॉन अब्राहम के साथ पुलिस के किरदार में नज़र आएंगे. नरगिस फाख़री भी कैमियो रोल में दिखेंगी और यह फिल्म 29 जुलाई को रिलीज होगी.

हाल ही में *ढिशूम* का फर्स्ट लुक जारी किया गया है. *ढिशूम* के फर्स्ट लुक में वरुण और जॉन एक साइड कार वाली मोटरसाइकिल में आक्रामक अंदाज में नज़र आ रहे हैं. जैकलीन ने भी इस पोस्टर को ट्विटर पर साझा किया है. *ढिशूम* को साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं.

आलिया और सिद्धार्थ को मिला आशिकी-3 का ऑफर

> राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की आशिकी 1990 में आई थी, जो म्यूजिकल हिट हुई थी. उसके बाद 2013 में आशिकी-2 आई और यह भी हिट हुई.

पिछले काफी समय से आशिकी-3 की कास्टिंग को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि इस फिल्म में आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा की कास्टिंग पक्की है. आशिकी-3 का निर्देशन मोहित सूरी करेंगे. महेश भट्ट ने आलिया और सिद्धार्थ को फिल्म में काम करने के लिए कहा है. आलिया के पिता ने उन्हें ऑफर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि आलिया इस फिल्म में काम करने से मना नहीं करेंगी. वहीं, दूसरी ओर सिद्धार्थ आलिया के ख़ास दोस्त हैं, तो उनसे भी फिल्म ठुकराने की उम्मीद नहीं की जा सकती. राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की आशिकी 1990 में आई थी, जो म्यूजिकल हिट हुई थी. उसके बाद 2013 में आशिकी-2 आई और यह भी हिट हुई. ऐसे में आशिकी-3 में आलिया और सिद्धार्थ भी खुशी-खुशी काम करना चाहेंगे. आलिया और सिद्धार्थ से पहले इस फिल्म में रितिक रोशन और सोनम कपुर की कास्टिंग की खबरें थीं.

सुल्तान के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं अनुष्का शर्मा

बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा अपनी आगामी फिल्म सुल्तान के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं. बॉलीवुड फिल्मकार आदित्य चोपड़ा इन दिनों सलमान खान को लेकर फिल्म सुल्तान बना रहे हैं. अली अब्बास ज़फ़र निर्देशित इस फिल्म में अनुष्का की भी अहम भूमिका है. इस फिल्म के लिए अनुष्का ने छह सप्ताह तक कठिन प्रशिक्षण लिया. अपने अभिनय के प्रति अनुष्का के इस समर्पण को देखकर फिल्म के निर्देशक अली अब्बास ज़फ़र काफी खुश हैं. बताया जाता है कि अनुष्का ने नियमित तौर पर अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया और इसके लिए काफी प्रशिक्षण लिया. अपने किरदार को यथार्थ बनाने के लिए अनुष्का ने एक पहलवान की जीवनशैली को भी अपनाया. अनुष्का ने जिस मेहनत से प्रशिक्षण लिया है, उससे उनके हाव-भाव में बड़ा बदलाव आया है.

दूसरी ओर सुल्तान में सलमान और अनुष्का का आईटम नंबर शूट हो चुका है. गाने के बोल हैं *बेबी को बास पसंद है* और इसे गाया है बादशाह ने. वहीं गाने को कोरियोग्राफ किया है फ़राह खान. यह फिल्म ईद के अवसर पर आठ जुलाई को रिलीज होगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com